राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

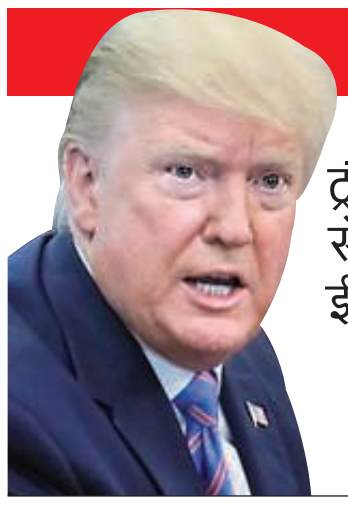

ट्रंप बोले, आग से खेल रहा ईरान
>> 11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 23

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 3 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

जलाशयों को संवारने में जुटी हैं 'जल प्रहरी' बेटियां

कोटद्वार : उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की बेटियां 'जल प्रहरी' बन सूखे

जलाशयों को नवजीवन देने में जुटी हुई हैं। बेटियां आगे आईं तो अन्य लोग भी इस मुहिम में जुड़ते गए। अब सभी मिलकर अपने क्षेत्र में पुरखों के बनाए जलाशयों को पुनर्जीवन देने का प्रेरक प्रयास कर रहे हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

ताकि न बुझे किसी और के घर का चिराग...

भोपाल : मप्र की राजधानी भोपाल निवासी मंदार(16) दोस्तों के साथ केरवा डैम पर

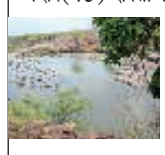

घूमने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मंदार की मां प्रतिभा और पिता विश्वास घुषे ने दूसरों को बचाने का प्रण किया। उनकी मुहिम से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा है। (पेज-13)

हमारी सरकार

रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय विधि व न्याय, संचार तथा इलेक्टॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

जीवन के मूल मानकों से समझौता नहीं ● पेज 5

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करने वाले काटेंगे छह माह जेल

नई दिल्ली, : बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी और उनका परित्याग करने वालों को अब छह माह की जेल तक काटनी पड़ेगी। सरकार ऐसे बच्चों के लिए जुर्माना और जेल की सजा के मौजूदा प्रावधान में बदलाव करने जा रही है। साथ ही बच्चों की परिभाषा का दायरा भी विस्तृत किया जाएगा ।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

बजट में हाउसिंग सेक्टर पर हो सकती है खास इनायत

नई दिल्ली : मंदी से जूझते रीयल एस्टेट सेक्टर पर बजट में खास इनायत हो सकती है। सरकार ने संकेत दिया है कि इस क्षेत्र में मांग बढ़ाने के कई उपाय किए जाएंगे। 2022 तक हर परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य पाने के लिए सस्ती आवासीय इकाइयों के बढ़ावे पर जोर दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

भारत को नाटो सहयोगी जैसा दर्जा देने जा रहा है अमेरिका

वाशिंगटन : अमेरिकी सीनेट ने रक्षा सहयोग को बढ़ावे का कानून पास किया है, जिससे भारत का दर्जा नाटो सहयोगियों व इजरायल तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान हो जाएगा। पिछले सप्ताह पारित एनडीएए में इस तरह का प्रस्ताव निहित था।

दो टूक ▶ बेलगाम भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश

किसी की मनमानी नहीं चलेगी

आकाश विजयवर्गीय मामले में पीएम बोले- किसी का भी बेटा हो, ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम का अभिवादन करते अमित शाह। एएनआइ

अपने बयानों और कामों से भाजपा की छवि खराब कर रहे नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कुछ दिनों पहले बल्ले से इंदौर के एक अधिकारी की पिटाई करने वाले भाजपा विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय के बारे में प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि कोई भी प्रतिनिधि ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। यह मनमानी नहीं चलेगी। यह अहंकार, यह घमंड, यह दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए फिर वह चाहे किसी का भी बेटा हो। साथ ही ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद पार्टी आकाश को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इस मामले में प्रधानमंत्री के सख्त तेवर से पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को इसलिए कड़ी फटकार लगाई थी क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की एक फोटो शेयर करते हुए यह कहा था कि इसी तरह का फलाहार का कार्यक्रम नवरात्र में भी कराया जाना चाहिए।

17वीं लोकसभा के गठन के बाद मंगलवार को पहली संसदीय दल की बैठक में पीएम का रुख सख्त था। एक तरफ जहां आकाश विजयवर्गीय का मामला था तो दूसरी तरफ वह संसद में सदस्यों की कम मौजूदगी से नाराज थे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, मोदी ने कहा, 'ये क्या हो रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वह कर रहा है और फिर उसका समर्थन किया जा रहा है। वह चाहे किसी का भी बेटा हो, सांसद हो, मंत्री हो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या होगा अगर एक विधायक कम हो जाएगा।'

उन्होंने आकाश के उस कथन पर भी आश्चर्य जताया जिसमें उन्होंने कहा था, 'पहले निवेदन, फिर आवेदन और फिर दनादन।' मोदी ने कहा, 'भाजपा को कई लोगों ने खून पसीने के साथ यहां तक पहुंचाया है और कुछ लोग इस तरह का आचरण करते हैं जो समाज में अस्वीकार्य है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और उस इकाई को तो भंग कर देना चाहिए जो स्वागत करने गई थी।' पीएम ने कहा,अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए पश्चाताप भी होना चाहिए, लेकिन उसका स्वागत किया जाना बहुत गलत है। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में मौजूद थे। ध्यान रहे कि जेल से जमानत पर बाहर आए आकाश का स्वागत करने कई नेता पहुंचे थे। खुद कैलाश ने भी अब तक आकाश के आचरण का बचाव ही किया है। पीएम का यह बयान सीधे तौर पर आकाश के लिए था। मोदी ने तत्काल तीन तलाक बिल पेश किए जाने के दौरान सांसदों की कम मौजूदगी पर भी नाराजगी जताते हुए सांसदों को आगाह किया कि वे पूरी तैयारी से संसद आएं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विचार रखें। चूंकि यह संसदीय दल की पहली बैठक थी लिहाजा पीएम के साथ-साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी स्वागत किया गया।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में भी अपनाए थे सख्त तेवर : लोकसभा चुनावों के दौरान महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रज्ञा ठाकुर समेत कुछ अन्य भाजपा नेताओं द्वारा देशभक्त बताए जाने पर भी मोदी ने इसी तरह के सख्त तेवर अपनाए थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि प्रज्ञा और बाकी लोग जो गोडसे और बापू के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, वह खराब है। भले ही प्रज्ञा ने माफी मान ली हो, लेकिन मैं दिल से उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। (पेज-7 भी देखें)

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा सही नहीं है कोलेजियम व्यवस्था

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने मोदी को पत्र भेज कोलेजियम व्यवस्था पर उठाए सवाल
- कहा, जजों की नियुक्तियों में परिवारवाद और जातिवाद का है बोलबाला

न्यायपालिका के अंदर से ही अब जवाबदेही और पारदर्शिता की आवाज उठने लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगनाथ पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायपालिका में व्याप्त विसंगतियों से अवगत कराया है। उन्होंने आरोप लगाया, 'हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में परिवारवाद व जातिवाद का बोलबाला है। यहां न्यायाधीश के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायाधीश होना सुनिश्चित करता है।' ज्ञात हो, कोलेजियम व्यवस्था में बदलाव को लेकर एक वक्त पर सरकार की ओर से कवायद भी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इन्कार कर दिया था।

जस्टिस पांडेय ने एक जुलाई को भेजे पत्र में लिखा है, राजनीतिक कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन चुनाव में जनता करती है, प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करनी पड़ती है। अधीनस्थ न्यायालय में जजों को नियुक्ति के लिए परीक्षा पास कर योग्यता साबित करनी पड़ती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति का कोई मापदंड नहीं है। यहां प्रचलित कसौटी है तो परिवारवाद और जातिवाद।'

'कई न्यायाधीशों को सामान्य विधिक ज्ञान भी नहीं' : जस्टिस पांडेय ने लिखा है कि उन्हें 34 वर्ष के सेवाकाल में बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को देखने का अवसर मिला है जिनमें कई के पास सामान्य विधिक ज्ञान तक नहीं था। कई वकीलों के पास न्याय प्रक्रिया की संतोषजनक जानकारी तक नहीं है। कोलेजियम सदस्यों का पसंदीदा होने के आधार पर न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाते हैं। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोग्य जज होने के कारण किस प्रकार निष्पक्ष न्यायिक कार्य का निष्पादन होता होगा, यह स्वयं में विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने कहा, 'भावी न्यायाधीशों का नाम नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही सार्वजनिक किए जाने की परंपरा रही है। अर्थात कौन किस आधार पर चयनित हुआ है इसका निश्चित मापदंड ज्ञात नहीं है। साथ ही प्रक्रिया को गुप्त रखने की परंपरा पारदर्शिता के सिद्धांत को झूठा सिद्ध करने जैसी है।'

राष्ट्रीय न्यायिक चयन आयोग से जगी थी पारदर्शिता की आस पेज>>3

केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को कहा असंवैधानिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का फैसला वापस लेने के निर्देश
- केंद्रीय मंत्री गहलोत बोले- राज्य प्रक्रिया का पालन कर भेजे प्रस्ताव
- राज्यसभा में सभापति ने भी कहा- सिर्फ संसद को ऐसा करने का हक

थावर चंद गहलोत (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में सत्रह अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को केंद्र ने असंवैधानिक करार दिया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नेता सदन और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बसपा नेता के उठाये इस सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार सिर्फ प्रस्ताव भेज सकती है। इस तरह के प्रस्तावों पर फैसला करना संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है।

राज्यसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने यूपी सरकार से इस फैसले को वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला कानूनी रूप से उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने योगी सरकार को 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने से रोकने के निर्देश भी दिए हैं।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा, 'यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह संसद का विशेषाधिकार है। यह किसी भी विधि न्यायालय में मान्य नहीं है। हम योगी सरकार से इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध करेंगे। अन्यथा यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है।' राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था।

बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, 'यूपी सरकार ने 17 जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर करते हुए, अनुसूचित जाति का सर्टीफिकेट देने के लिए कहा है। यूपी सरकार का यह फैसला पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। इन 17 जातियों के साथ यह धोखा हुआ है। अब ये जातियां ओबीसी से भी हट गईं और अनुसूचित जाति के दायरे में बिना संविधान में बदलाव किए आ नहीं सकतीं हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से यूपी सरकार को आदेश वापस लेने के लिए एडवाइजरी जारी की जाए।' सतीश चंद्र मिश्रा के उठाए गए सवालों के जवाब में गहलोत ने कहा कि किसी जाति को किसी अन्य जाति के वर्ग में डालने का काम संसद का है। अगर यूपी सरकार 17 जातियों को ओबीसी से एससी में लाना चाहती है तो उसके लिए एक उचित प्रक्रिया है। राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव भेजेगी तो संसद उस पर विचार करेगी।

दरअसल, विगत 24 जून को यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 17 पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने के निर्देश दिए। इन जातियों में कश्यप, राजभर, धीवर, बिंद, कुम्हार, कहार, केवट, निषाद, भर, मल्लाह, प्रजापति, धीमर, मांझी, बाथम, तुरहा, गोदिया, मछुआ शामिल हैं। उसी दिन सभी डीएम और कमिश्नरों को उन्हें जाति प्रमाणपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया था। सदन के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने गहलोत से कहा है कि वह राज्य सरकार को प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दें। इससे पूर्व शून्यकाल के दौरान बसपा नेता सतीश मिश्रा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 की उपधारा(2) के तहत यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास भी जातियों के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है। (पेज-4 भी देखें)

बैंक घोटालेबाजों के खिलाफ सीबीआइ की कार्रवाई, 18 शहरों के 61 स्थानों पर छापे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 300 अफसरों ने एक साथ कार्रवाई को दिया अंजाम, 17 एफआइआर दर्ज
- इन सभी पर बैंकों से 1,139 करोड़ रुपये के घोटाले करने का है आरोप

कई सुबूत बरामद

जिन आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके पास से फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन लेने, राशि का दुरुपयोग करने व जानबूझकर बैंक को नहीं लौटाने के सुबूत मिले हैं।

इन शहरों में हुई छापेमारी

जिन शहरों में छापे मारे गए उनमें दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, ठाणे, वलसाद, पुणे, पलानी, गया, गुरुग्राम, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत और नोएडा शामिल हैं।

बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत सीबीआइ ने कुल 17 एफआइआर दर्ज करते हुए 18 शहरों में 61 स्थानों पर छापेमारी की। इन लोगों पर बैंकों के 1,139 करोड़ रुपये के गोलमाल का आरोप है। सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न बैंकों से मिल रही शिकायतों की गहन छानबीन के बाद सभी आरोपितों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई का फैसला किया गया। सीबीआइ के 300 अधिकारियों ने एक साथ आरोपितों के ठिकानों की तलाशी ली। यहां तक कि मुंबई की भारी बारिश और जलभराव भी सीबीआइ अधिकारियों को नहीं रोक सकी।

इनके खिलाफ हुई कार्रवाई : मुंबई में विल्सन डायमंड, सुपमद ट्रेडिंग, आसुति ट्रेडिंग के ठिकानों पर छापे मारे गए। जतिन मेहता की विल्डन डायमंड के खिलाफ सीबीआइ की यह 16वीं एफआइआर है। जतिन पर बैंकों से 6,500 करोड़ का लोन लेकर फरार होने का आरोप है। ताजा मामला जतिन पर एक्जिम बैंक के202 करोड़ रुपये नहीं चुकाने का है। वहीं, सुपमद ट्रेडिंग पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 57 और आसुति ट्रेडिंग पर 50 करोड़ डकारने का आरोप है। आसुति के दिल्ली ठिकाने की भी तलाशी ली गई। इसके साथ ही लुधियाना के सुप्रीम टेक्स मार्ट के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया से 143 करोड़, बेंगलुरु की एगन बैट्रीज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 99 करोड़, गया के रामनंदी होटल एंड रिसोर्ट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 131 करोड़, नोएडा के नाफटोगाज इंडिया पर कारपोरेशन बैंक के 93 करोड़ नहीं चुकाने का आरोप है। दिल्ली के एसएल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 55 करोड़, अलीगढ़ के संप्राश फूड के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ही 60 करोड़, चंडीगढ़ के इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क के खिलाफ सिडबी से 40 करोड़, भोपाल के रंजीत ऑटोमोबाइल के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा से 34 करोड़, सूरत के जलपा टेक्सटाइल पर 28 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर कार्रवाई की गई है। साथ ही भुवनेश्वर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के हाउसिंग लोन घोटाले के आरोपितों पर शिकंजा कसा है।

प्रलयंकारी बारिश के कारण पटरी से उतरी मुंबई

मुंबई : बारिश के प्रलयंकारी रूप लेने से मंगलवार को मुंबई बेबस हो गई। देश

की आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में जल जमाव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रविवार से लगातार हो रही वर्षा के कारण रेल, सड़क और हवाई सेवा पर बुरा असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रद कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 52 उड़ानों को रद और 54 को डाइवर्ट किया गया। दीवार ढह जाने से मुंबई में 22 लोगों की मौत हो गई। सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि मुंबईवासियों ने तीन घंटे में ही 400 मिलीमीटर वर्षा का सामना किया। यदि 26 जुलाई, 2005 की बाढ़ का दिन छोड़ दिया जाय तो 1974 के बाद यह दूसरा मौका है, जब कुछ ही घंटों में मुंबई में इतनी वर्षा हुई है। (पेज-7)

रोहित के रिकॉर्ड तोड़ शतक से भारत सेमीफाइनल में

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी ● बर्मिंघम

- भारत ने बांग्लादेश को 28 रनों से हराया
- विश्व कप के पिछले 19 मैचों में से भारत ने 17 में जीत हासिल की है

शतक लगाने के बाद दर्शकों का अभिवादन करते रोहित शर्मा। प्रेट्र

1983, 1987, 1996, 2003, 2011 और 2015 के बाद 2019 में भी भारत ने विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रोहित शर्मा के इस विश्व कप में रिकॉर्ड चौथे और ओवरऑल पांचवें विश्व कप के शतक की बदौलत दो बार की विश्व विजेता भारतीय टीम ने मंगलवार को एजबेस्टन क्रिकेट मैदान में पहले खेलते हुए 50 ओवर में 314 रन बनाए और जवाब में बांग्लादेश की टीम को 286 रनों पर ऑलआउट कर दिया।

एक समय लग रहा था कि मुहम्मद सैफुद्दीन (नाबाद 51) बांग्लादेश को जीत के करीब ले जाएंगे, लेकिन बुमराह ने अपने आखिरी ओवर की दो गेंदों पर दो विकेट लेकर बांग्लादेश की पारी समाप्त कर दी। उन्होंने मैच में कुल चार विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या को तीन विकेट मिले। बांग्लादेश पर 28 रनों की जीत के साथ भारत के आठ मैचों में 13 अंक हो गए हैं और वह अंकतालिका में दूसरे पायदान पर है।

भारत ने छह मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका मुकाबला बारिश के कारण रद हो गया था। भारत का आखिरी लीग मुकाबला शनिवार को लीड्स में श्रीलंका से होगा। ऑस्ट्रेलिया पहले ही आठ मैचों में 14 अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है। इस हार के साथ बांग्लादेश का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह गया। श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका पहले ही इस दौड़ से बाहर हो गईं थीं। अब सेमीफाइनल के बाकी दो स्थानों के लिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान में टक्कर है।

36 वनडे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने 30 और बांग्लादेश ने पांच में जीत दर्ज की है। एक मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ

04 विश्व कप मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए, इस दौरान भारत ने तीन (2011, 2015, 2019) जबकि बांग्लादेश (2007) ने एक जीता

11 पिछले मुकाबले जो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं उसमें नौ जीते हैं

2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने इसी मैदान पर बांग्लादेश को नौ विकेट से हराया था, जिसमें रोहित ने नाबाद 123 रन बनाए थे

विशेष कवरेज पेज>>12

सरकार की योजना

पानी बचाने के लिए पांच प्रकार के कार्यों की योजना है, जिसमें से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, ताल और अन्य जलाशयों की मरम्मत, बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर और वृक्षारोपण का काम मनरेगा के तहत होगा

मनरेगा के सहारे आगे बढ़ेगा जल शक्ति अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मनरेगा के तहत होने वाले 75 प्रतिशत काम होंगे जल संरक्षण से संबंधित
- बीते पांच साल में मनरेगा के तहत बन चुके हैं 38 लाख से अधिक तालाब

गांवों में रोजगार का जरिया है मनरेगा (फाइल फोटो)

सरकार के महत्वाकांक्षी जल शक्ति अभियान की नैया मनरेगा के सहारे पार होगी। इस अभियान के दौरान जल संरक्षण के अधिकांश काम मनरेगा के तहत ही कराए जाएंगे। मनरेगा के तहत बीते पांच साल में 38 लाख से अधिक तालाब और पांच लाख से अधिक चैक डैम बन चुके हैं, इसलिए अभियान के तहत यह सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा कि ये तालाब और चैक डैम बारिश के पानी से भर जाएं।

सूत्रों के अनुसार सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत पानी बचाने के लिए कुल पांच प्रकार के कार्यों की योजना बनाई है, जिसमें से चार काम मनरेगा के जरिये कराए जाएंगे। जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परंपरागत तालाबों और अन्य जलाशयों की मरम्मत, बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर और वृक्षारोपण का काम मनरेगा के तहत कराया जाएगा जबकि सिर्फ वाटरशेड डेवलपमेंट का काम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत कराया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि पानी की कमी का सामना कर रहे 256 जिलों के 1593 ब्लॉक में इस अभियान के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को इन कार्यों की सूची सौंप दी गई है।

नए तालाबों को भरने पर रहेगा जोर : ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2014 से 2019 के दौरान मनरेगा के तहत 20.03 लाख तालाब, 5.14 लाख कुएं, 5.22 लाख चैक डैम, 2.02 लाख तटबंध और 18.10 लाख खेत तालाब बनाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन तालाबों की संरचना तकनीकी रूप से ऐसी है कि जिसके चलते उन तक बारिश का पानी नहीं पहुंच पाता, उन्हें अब मनरेगा के तहत दुरुस्त किया जाएगा। कुल मिलाकर अब फोकस नए तालाब बनाने के बजाय, मौजूदा तालाबों को भरने पर होगा।

बीते पांच साल में 143 लाख हेक्टेयर जमीन को हुआ फायदा : मंत्रालय का कहना है कि 2014 में मनरेगा की पहली अनुसूची में बदलाव किया गया था। इसके तहत कम से कम 60 प्रतिशत राशि कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर खर्च करने का प्रावधान है। इसका परिणाम यह हुआ कि मनरेगा के तहत फिलहाल जितने प्रकार के काम करने की अनुमति है उसमें से 75 प्रतिशत काम जल सुरक्षा और जल संरक्षण के प्रयासों से संबंधित हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि बीते पांच साल में 143 लाख हेक्टेयर जमीन को फायदा हुआ है। मंत्रालय का कहना है कि मनरेगा जल शक्ति अभियान में एक प्रमुख भागीदार है और यह इसे सफल बनाने के लिए समर्पित है।

एनएमसी के लिए जल्द आएगा अलग विधेयक : हर्षवर्धन

नई दिल्ली : भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया (एमसीआइ) को निलंबित रखने और उसकी जगह बोर्ड आफ गवर्नर्स (बीओजी) को दो साल काम करने का वैधानिक दर्जा देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह देश में मेडिकल शिक्षा में सुधारों की शुरुआत भर है। आने वाले सालों में और भी क्रांतिकारी सुधार होंगे। (पेज-3)

करतारपुर कॉरिडोर पर भारत-पाक के बीच दूसरी बैठक 14 को

इस्लामाबाद : भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने संबंधी मसौदा समझौते और उससे जुड़े तकनीकी मसलों पर चर्चा के लिए दूसरी बैठक करेंगे। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच यह बैठक 14 जुलाई को बाघा में होगी। पाकिस्तान ने कहा है कि वह इस प्रक्रिया में तेजी लाने को प्रतिबद्ध है ताकि नवंबर में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती तक कॉरिडोर को शुरू किया जा सके। (पेज-4)

चुनावी रेवड़ियां बांटने के वादे न्यायिक समीक्षा के दायरे में

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग व पांच राज्यों को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले और चुनाव के दौरान सीधे धन हस्तांतरित करने और मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणा करने पर प्रतिबंध के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र, चुनाव आयोग और पांच राज्यों को नोटिस जारी किए।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पेंटापति पुल्ला राव की याचिका पर ये नोटिस जारी किए। राव ने हालिया लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की एलुरू सीट से जनसेना पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। याचिका में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों द्वारा घोषित अन्य कार्यक्रमों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि इन घोषणाओं की वजह से केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिली। पीठ ने इस तरह की घोषणाओं के बारे में दिशानिर्देश तैयार करने के अनुरोध पर विचार करने का निर्णय किया है। राव की ओर से अधिवक्ता संतोष पाल और श्रवण कुमार ने दलील दी कि चुनाव से पहले सीधे नकदी हस्तांतरित करने की योजनाएं और मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने जैसी घोषणा चुनावी कदाचार के दायरे में आती हैं। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए जाएं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले ऐसे कार्यक्रमों को सत्तारूढ़ दल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कम से कम छह महीने पहले लागू करने की अवधि निर्धारित करें। पेशे से अर्थशास्त्री राव ने कहा कि ऐसी सभी योजनाओं को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112 और 202 के खिलाफ घोषित किया जाए।

23,780 छात्रों के दाखिले हुए हैं डीयू में इस वर्ष स्नातक में पहले कटऑफ के तहत। पहले कटऑफ में इससे ज्यादा दाखिले पहले कभी नहीं हुए थे। यह जानकारी दाखिला समिति के अध्यक्ष प्रो. राजीव गुप्ता ने दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 3 जुलाई 2019

न्यूज गैलरी

नोएडा में दो टावरों के बीच मिला युवती का शव

नोएडा : नोएडा सेक्टर-76 स्थित सिलिकॉन सिटी में मंगलवार को दो टॉवरों के बीच युवती का शव मिला। युवती की पहचान 20 वर्षीय सोनामुनी निवासी मधेपुरा कटिहार बिहार के रूप में हुई है। बदबू आने पर मंगलवार सुबह साढ़े सात बजे लोगों ने एक टॉवर की छत पर जाकर देखा तो 17 फ्लोर की बहुमंजिली इमारत के 12वें फ्लोर पर दो टॉवरों के बीच 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा था। पुलिस के अनुसार शव चार से पांच दिन पुराना है। गाजियाबाद से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने दो घंटे कड़ी मशक्कत के बाद एक फ्लैट की बालकनी की दीवार काटकर शव बाहर निकाला। युवती की कमर में तार बंधा था। आशंका है कि हत्या के बाद उसे टॉवर के बीच में लटकाया गया था। कोतवाली प्रभारी अजय अग्रवाल ने बताया कि सिलिकॉन सिटी के टॉवर डी के फ्लैट नंबर 1802 में रहने वाले जय प्रकाश इंटीरियर वर्क का काम करते हैं। पत्नी की बीमारी की वजह से वह सोनामुनी को घरेलू सहायिका के रूप में पिछले एक वर्ष से साथ रखे हुए थे। वह उनके गांव की ही रहने वाली है। 25 मई को युवती इन लोगों के साथ घर गई थी और 18 जून को वापस लौटी। 28 जून से युवती लापता थी। (जासं)

दिल्ली में 90 पैसे महंगी हुई सीएनजी

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम में 90 पैसे से लेकर एक रुपये तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी 90 पैसे प्रति किलो महंगी हुई है। अब यह 46.60 रुपये में मिलेगी। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, रेवाड़ी व करनाल में 95 पैसे की वृद्धि हुई है। गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में अब सीएनजी 52.95 रुपये प्रति किलो में मिलेगी। गुरुग्राम व रेवाड़ी में इसकी दर 58.45 तथा करनाल में 55.45 रुपये प्रति किलो होगी। हालांकि इस वृद्धि का असर वाहनों पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) ने बताया कि ऑटो पर प्रति किलोमीटर तीन पैसा, टैक्सी पर पांच पैसा व बस पर 28 पैसा प्रति किलोमीटर का असर पड़ेगा। बढ़ोतरी के पीछे आइजीएल ने ट्रांसमिशन टैरिफ में हुए बदलाव को कारण बताया है। बढ़ी दरें बुधवार सुबह छह बजे से लागू हो जाएंगी। (जासं)

एंटी-रेबीज टीकों पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली : दिल्ली के अस्पतालों में एंटी रेबीज टीके उपलब्ध नहीं होने या कम आपूर्ति के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी। (जासं)

तालाब बनाकर यमुना के पानी का होगा संग्रह

बड़ा फैसला ▶ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यमुना जल संग्रहण परियोजना को दी गई मंजूरी

यमुना के साथ ही पल्ला से वजीराबाद तक के क्षेत्र में बनाए जाएंगे छोटे-छोटे तालाब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यमुना डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन) में बाढ़ जल संग्रहण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इससे यमुना के साथ-साथ पल्ला से वजीराबाद तक 20 किलोमीटर क्षेत्र में छोटे-छोटे तालाब बनाकर यमुना के पानी को संग्रहित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि एक साल के बाढ़ के पानी को संग्रहित करने पर दिल्ली में दो साल तक पानी की कमी नहीं होगी। इस परियोजना पर करीब 50 करोड़ की लागत आएगी।

अभी इस परियोजना का पायलट प्रोजक्ट शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक हजार एकड़ में जल संग्रहण किया जाएगा। कैबिनेट से इस परियोजना को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में हुई प्रेसवार्ता में कहा कि दिल्ली के बारे में सुनने को मिलता है कि यहां भूमिगत जल का स्तर धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना डूब क्षेत्र में यमुना के पानी को संग्रहित करने की बहुत बड़ी योजना बनाई है। इससे जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मानसून में यमुना डूब क्षेत्र में पानी संग्रहण का ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बार समय कम रह गया है फिर भी यह एक ठोस शुरुआत होगी। इससे यह भी पता चल जाएगा कि इस परियोजना की संभावनाएं कितनी हैं? सलाहकार और आइआइटी की रिपोर्ट इस ओर संकेत करती है कि इस परियोजना में व्यापक संभावनाएं हैं। यमुना का डूब क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें अत्यधिक पानी संग्रहण की क्षमता है। ऐसा करके दिल्ली का जल संकट दूर किया जा सकता है। इसके अध्ययन के आधार पर अगले साल इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया यह पूरी तरह से ईको फ्रेंडली होगा। इसमें कोई सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें छोटे-छोटे तालाब बनाए जाएंगे। बारिश के दिनों में जब यमुना ओवर फ्लो करती है, तब ये ओवर फ्लो वाला पानी इन तालाबों में जाएगा। जब ये पानी यहां ठहरेगा, तब जमीन में नीचे चला जाएगा। इस बार हमें जमीन में पानी के जाने के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद हमें जहां-जहां पानी होने का पता चलेगा, वहां हम बोरवेल करके पानी निकाल लेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को लेकर हमें केंद्र सरकार की कुछ मंजूरी चाहिए। पिछले हफ्ते हमने प्रस्ताव भेजा था। मैं खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिलकर आया था। वह इस परियोजना को लेकर बहुत सकारात्मक थे। हमें उम्मीद है कि इस परियोजना पर जल्दी ही केंद्र से मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा हमें जहां जल का संग्रहण करना है, वह जमीन किसानों की है। दिल्ली सरकार किसानों की जमीन को किराये पर लेगी। ये किराया तय करने के लिए हमने पांच अधिकारियों की एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी सोमवार तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

वर्षा जल संग्रहण करें या जुर्माना भरने को रहें तैयार

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

घरों में वर्षा जल संग्रहण यंत्र लगाकर पानी बचाने के लिए लंबे समय से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता रहा है। इस जागरूकता कार्यक्रम का खास फायदा दिल्ली को नहीं हुआ। इसलिए बड़े पैमाने पर हो रहे भूजल दोहन से चिंतित जल बोर्ड ने जल संग्रहण के लिए सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों के भवनों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था नहीं करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। इस क्रम में जल बोर्ड 11 हजार 635 उपभोक्ताओं पर 48.68 करोड़ जुर्माना लगाया है। जल बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि यदि उपभोक्ता जुर्माने से बचना चाहते हैं तो अपने भवनों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्षा जल संग्रहण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। जल संग्रहण की व्यवस्था नहीं करने पर आने वाले दिनों में और लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।

▶ **सख्त हुआ दिल्ली जल बोर्ड, 11,635 उपभोक्ताओं पर लगाया 48.68 करोड़ का जुर्माना**

जल संग्रहण यंत्र लगाना अनिवार्य : असल में दिल्ली में 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी संपत्ति में वर्षा जल संग्रहण यंत्र लगाना अनिवार्य है। इसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जल बोर्ड ने वर्षा जल संग्रहण करने वालों को पानी के बिल में 10 फीसद की छूट देने का प्रावधान पहले से है। इसके अलावा 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड के भवनों में वर्षा जल संग्रहण यंत्र नहीं लगाने पर पानी का डेढ़ गुना बिल वसूलने का प्रावधान है। जल बोर्ड जुर्माने के प्रावधान को लागू करने से बचता रहा, लेकिन कई इलाकों में भूजल स्तर हर साल चार मीटर तक नीचे गिरने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया।

अब आगे आ रहे लोग : बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जुलाई 2017 से जुर्माना शुरू किया गया है। इसके बाद से अब तक 11 हजार 635 उपभोक्ताओं पर जुर्माना किया गया। जिसमें व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा हजारों आवासीय श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल हैं। देखा जा रहा है कि इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग धीरे-धीरे वर्षा जल संग्रहण यंत्र लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। यही वजह है कि 1415 उपभोक्ताओं को पानी के बिल में 32.56 करोड़ की छूट दी गई है। पहले छूट पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या सौ से भी कम थी।

इसलिए जरूरी है वर्षा जल संरक्षण : भूजल स्तर गिरने से पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। दिल्ली में 13, 491 मिलियन क्यूसेक मीटर (एमसीएम) पानी उपलब्ध है। इसका 10,238 एमसीएम पानी खारा है। सिर्फ 3,207 एमसीएम साफ भूजल बचा है। फिर भी भूजल दोहन ज्यादा व रिचार्ज कम हो रहा है। जबकि वर्षा के 175 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी को संग्रहित कर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है।

राहुल को मनाने के लिए लिलोठिया बैठे अनशन पर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राहुल गांधी को मनाने के लिए दिल्ली के कांग्रेस नेता लिलोठिया कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार से अनशन पर बैठ गए हैं। 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पर अनशन पर बैठे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने राहुल से पार्टी हित में इस्तीफा वापस लेने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में हार के बाद से ही राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए वह अपना इस्तीफा वापस न लेने पर अड़े हुए हैं। इसी क्रम में राहुल से इस्तीफा वापस लेने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेता मंगलवार से अनशन पर बैठ गए।

कार्यकर्ता ने की खुदकशी की कोशिश : राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे से नाराज एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया। वह फंदा लगाने के लिए पेड़ पर लटक गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। फंदा लगाने जा रहे कार्यकर्ता ने बताया कि राहुल गांधी को इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। वहां ऐसे कांग्रेसी भी थे जो एकजुटता दिखाने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इसी बीच एक कार्यकर्ता पेड़ पर चढ़ गया और फंदा लगाने का प्रयास किया।

हौज काजी बवाल मामले में तनाव बरकरार, नाबालिग सहित तीन धरे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हौज काजी इलाके में दो संप्रदायों के बीच झड़प के बाद मंगलवार को भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। बवाल के दूसरे दिन भी एक संप्रदाय के लोगों ने नेराबाजी जारी रखी। इलाके में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद ज्यादातर बाजार बंद रहे। इक्का-दुक्का दुकानें कुछ देर के लिए खोली गईं। उधर, इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन को दबोचा है। बालिग आरोपित शाहगंज निवासी अनश और लाल कुआं निवासी जुबैर को जेल, जबकि नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं, हंगामा और तोड़फोड़ करने के आरोप में सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों पर भीड़ का फायदा उठाकर मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप है।

पुलिस उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि संवेदनशील होने के कारण मामला शांत हुए बगैर पुलिस और कड़ी कार्रवाई से बच रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभी भी मौके पर तैनात हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा के लिए पांच कंपनी अर्द्धसैनिक बल के जवानों के अलावा मध्य और उत्तरी जिले की पुलिस और रिर्जव बटालियन को भी लगाया गया है।

रविवार की रात हौज काजी के लाल कुआं इलाके में स्कूटी पार्क करने को लेकर दो संप्रदाय के लोगों में मारपीट के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। वहीं सोशल मीडिया पर उन्मादी हिंसा की अफवाह फैलने के बाद एक संप्रदाय को लोग भड़क गए थे। बाद में उन्होंने हौज काजी थाने में प्रदर्शन के बाद लाल कुआं स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की थी। कई घरों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद सोमवार को भी क्षेत्र में तनाव था।

मंगलवार को स्थिति में पहले से कुछ नरमी तो आई, लेकिन तनाव बरकरार रहा। एहतियात के तौर पर चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट, हौजकाजी, लालकुआं नई सड़क, बल्लीमारान व आसपास के इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। लेकिन शरारती तत्वों की नारेबाजी और हंगामे के कारण ज्यादातर कारोबारियों ने मंगलवार को भी दुकानें नहीं खोलीं।

पुलिस को मिली हंगामे की 264 कॉल : पुलिस के मुताबिक हौज काजी इलाके में रविवार रात से ही पुलिस को बवाल की सूचना मिलनी शुरू हो गई थी। रविवार को घटना के बाद 87 पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी। सोमवार को भी 177 लोगों ने पुलिस को फोन कर हंगामे की सूचना दी थी।

पीड़ितों से मिलने के लिए नेताओं का लगा रहा तांता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

लालकुआं इलाके में मंगलवार को नेताओं का तांता लगा रहा। केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के साथ ही विजय गोयल, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार व अन्य भाजपा नेता पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त मंदिर का भी जायजा लिया और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। हर्षवर्धन सुबह ही चावड़ी बाजार पहुंचे और वहां से घटनास्थल तक पैदल ही गए। उनके साथ दिल्ली भाजपा के कई नेता, व्यापारी व दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारी थे। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। लोगों से मुलाकात कर घटना का ब्योरा लेते हुए पुलिस से दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। इलाके के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात में उन्होंने सद्भावना बनाए रखने की अपील की।

विहिप ने किया हनुमान चालीसा का पाठ : क्षतिग्रस्त मंदिर के सामने दिनभर हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा। इसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस बीच विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए मंदिर को बनवाने की मांग की। यहां दिनभर लोगों के आने का क्रम जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन भी करते रहे। बीच-बीच में नारेबाजी से माहौल तनाव पूर्ण होता रहा।

लाल कुआं इलाके में दौरा करते केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन। फोटो सौजन्य- भाजपा

होती रही पुरानी दिल्ली के गंगा-यमुना तहजीब को बनाए रखने की अपील : तनाव के बावजूद आपसी भाईचारे की उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश में दिनभर लोगों द्वारा शांति की अपील की जाती रही। वर्षों से यहां की साझी विरासत को बचाए रखने को लेकर हर कोई चिंतित नजर आया। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक हाथों में छोड़ो अब ये लड़ाई, हिंदू मुस्लिम भाई-भाई, नफरत मुक्त भारत चाहिए, बंद करो ये नफरत प्लेकार्ड से शांति की अपील कर रहे थे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देते हुए भी प्लेकार्ड थे। स्थानीय निवासी आमिर अहमद राजा ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने मामले को संभाला है वह काबिले तारीफ है। अमन कमेटी रोदग्रान के जमील अहमद ने कहा कि हम अमन-शांति चाहते हैं। यहां की छतें साझी हैं। हम लोग हर त्योहार मिलजुलकर मनाते हैं। फराशखाना के अशद आजाद ने कहा कि शराब पीकर उपद्रव करने वालों की वजह से यह दरार पैदा हुई है। उसके लिए हम शर्मिंदा है।

ये हमारी साझी विरासत, आपसी प्यार, भाईचारे का इम्तेहान है। कुछ लोग हमारे आपसी विश्वास को चोट पहुंचा कर सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। शांति और आपसी विश्वास बनाए रखें। दिल्ली जीतेगी, नफरत हारेगी। जय हिंद।

-मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली

हौज काजी इलाके में दोनों समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मैंने आज पुलिस के साथ भी बैठक की। इस बैठक में दोनों समुदायों के लोग मौजूद रहे। सबने मिलकर इलाके में आज दुकानें भी खुलवाई हैं। अब इलाके में शांति है।

-इमरान हुसैन, मंत्री, दिल्ली सरकार

हड़ताल जारी, सड़क पर नहीं उतरीं 200 कैट्स एंबुलेंस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार की कैट्स एंबुलेंस सेवा के संचालन की जिम्मेदारी नई कंपनी के संभालने के बाद लगातार दो दिनों से अनुबंधित कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वजह से मंगलवार को करीब 200 एंबुलेंस सड़क पर नहीं उतर पाईं। इस वजह से राजधानी में इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा चरमारा गई। कर्मचारियों का तीन माह का वेतन बकाया है। इसलिए 1600 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसमें पैरामेडिकल कर्मचारी व एंबुलेंस चालक शामिल हैं। कैट्स एंबुलेंस सेवा का कहना है कि हड़ताली कर्मचारियों ने 52 एंबुलेंस को नुकसान पहुंचाया है। हड़ताल से निपटने के लिए कैट्स एंबुलेंस सेवा ने नई संचालक कंपनी को नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

एस्मा बेअसर : दिल्ली सरकार ने हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहीं स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर एस्मा लगा दिया है, जो तीन नवंबर तक लागू रहेगा। साथ ही एस्मा लागू करने की सूचना दिल्ली पुलिस को भी दे दी गई है। हालांकि यूनियन के पदाधिकारी के मुताबिक हड़ताली कर्मचारी अनुबंध पर हैं, पुरानी कंपनी ने जिन 1200 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, वे नियमानुसार अब कैट्स के कर्मचारी ही नहीं है। ऐसे में उन पर एस्मा लगाने का कोई मतलब नहीं। कैट्स कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी और मुख्यमंत्री आवास के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।

जुलाई 2017 से कैट्स एंबुलेंस सेवा का संचालन बीवीजी-यूकेएसएएस-ईएमएस कंपनी कर रही थी। उसका अनुबंध 30 जून, 2019 को खत्म हो गया। लेकिन कर्मचारियों का बकाया वेतन नहीं दिया। एक जुलाई से एंबुलेंस के संचालन की जिम्मेदारी जीवीके-ईएमआरआई नामक दूसरी कंपनी ने संभाल ली है। नई कंपनी ने भी बकाया वेतन पर बात नहीं की इसलिए कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए। कैट्स एंबुलेंस का दावा है हड़ताल के बावजूद करीब 63 एंबुलेंस का संचालन हो रहा है। कैट्स के कुछ स्थाई कर्मचारी हैं और नई कंपनी ने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है।

करीब 850 मरीजों को नहीं मिल पाई एंबुलेंस : कैट्स एंबुलेंस रोज करीब 1050 मरीजों को अस्पताल पहुंचाती है। हड़ताल की वजह से करीब 850 मरीजों तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाई।

केजरीवाल के खिलाफ पांच जुलाई को होंगे आरोप तय

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और चार अन्य आप नेताओं के खिलाफ अदालत पांच जुलाई को आरोप तय करेगी। दिल्ली की विशेष अदालत में आरोप तय करने पर बहस पूरी होने के बाद फैसला पांच जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया गया। सरकारी और लोक सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और प्रतिबंध के बावजूद धरना देने के मामले में आप नेता संजय सिंह, राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती और आशुतोष भी आरोपित हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पेशी से छूट देने की अर्जी को भी मंजूर किया।

अदालत में पुलिस की तरफ से दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं ने जनवरी 2014 में रेल भवन के बाहर धरना दिया था। यह धरना कथित ड्रग बेचने वालों पर रेड न करने के चलते पुलिस के खिलाफ दिया गया था। आरोपपत्र में कहा गया है कि धारा 144 लागू कर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद धरना देकर सरकारी और लोक सेवक के कार्य में बाधा पहुंचाई गई थी। रोकने के बावजूद भीड़ गृह मंत्री कार्यालय की ओर बढ़ने लगी तो किसी तरह हालात को काबू किया गया था।

मनोज तिवारी के आरोप पर सिसोदिया ने किया पलटवार

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

राजधानी के सरकारी स्कूलों के कमरों के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले के भाजपा के आरोप के बाद दिल्ली की सियासत में वार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अब उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा स्कूलों के कमरों के निर्माण के लिए तैयार किए गए एक प्रस्ताव को पेश किया है। इसके आधार पर सिसोदिया ने दावा किया है कि एसडीएमसी द्वारा भी कमरों की अनुमानित निर्माण लागत 24.95 लाख बताई गई है। ऐसे में आप सरकार द्वारा इसी लागत में तैयार कराए गए कमरों में भ्रष्टाचार का दावा भाजपा किस आधार पर कर रही है। मनोज तिवारी को अब बताना चाहिए कि यदि एसडीएमसी और दिल्ली सरकार के स्कूलों के कमरों के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग बराबर है, तो फिर घोटाला कैसे हुआ।

सिसोदिया ने मंगलवार को बताया कि उन्हें एसडीएमसी के निर्माण अनुमान से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले हैं। इसमें सिद्ध होता है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार द्वारा बनवाए गए स्कूलों के कमरों की निर्माण लागत का अनुमान लगभग समान हैं। उन्होंने बताया कि निगम की स्थायी समिति के एक प्रस्ताव के मुताबिक पिछले साल एसडीएमसी ने 10 करोड़, 73 लाख, 80 हजार की लागत से 43 कमरे बनाने के लिए एक अनुमानित प्रस्ताव तैयार किया था। इसमें प्रत्येक कमरे का खर्च 24.95 लाख रुपया बताया गया है। इसमें वर्षा जल संचयन प्रणाली, फर्नीचर, सीलिंग, पंखे, रोशनी आदि शामिल नहीं थे। भाजपा ने काल्पनिक गणित के आधार पर एक बेबुनियाद आरोप लगाया है, इसका कोई आधार नहीं है। दरअसल, भाजपा दिल्ली में शिक्षा पर हो रहे काम से बौखला गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने सोमवार को एक आरटीआइ का हवाला देते हुए दावा किया था कि दिल्ली सरकार 2892 करोड़ रुपये में 12748 कमरों का निर्माण करवा रही है। इसमें एक कमरे की लागत 25 लाख रुपये आ रही है। यही नहीं तिवारी ने इसमें करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने का आरोप लगाया था।

सिसोदिया ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम निर्माण लागत के रूप में प्रति कमरा 25 लाख का अनुमान लगाती है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं है। दिल्ली सरकार 25 लाख में फर्नीचर, अग्नि सुरक्षा उपकरण, विद्युत उपकरण आदि सुविधाओं वाला कमरा बनवाती है तो इसमें भ्रष्टाचार है। तिवारी को अब बताना होगा कि एसडीएमसी ने निम्न गुणवत्ता के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार के समान आंकड़े का अनुमान क्यों लगाया है।

'निगम स्कूल की निर्माण लागत को बता रहे एक कमरे का खर्च'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दावे के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे गुमराह करने वाला बयान करार दिया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप नस्ली घोड़े की तुलना खच्चर से कर रही है। सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार कमरे का निर्माण करा रही है और निगम स्कूल का। कमरे बनाने की अपेक्षा पूरा स्कूल बनाने में ज्यादा खर्चा होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में एक कमरे का निर्माण कराने के लिए 24.95 लाख रुपये खर्च करने का दावा किया है। सच्चाई यह है कि निगम 12 लाख रुपये में यह कार्य कर रहा है और दिल्ली सरकार के एक कमरे में निर्माण का खर्च 24.86 लाख रुपये है। आप ने जो आरोप लगाए हैं, वे भी अनुमानित राशि के हैं। इनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार केवल कमरों का निर्माण करवा रही है, जबकि निगम द्वारा प्रस्तावित स्कूल में इमारत नींव से बनाई जाएगी। इमारत दो मंजिला होगी। इसमें भूकंपरोधी तकनीक, ढांचागत स्टेबिलिटी, वर्षा जल संरक्षण, सीवेज तथा ड्रेनेज, बाउंड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित हैं। यही नहीं दिल्ली सरकार पहले से स्थापित स्कूलों में 25 लाख रुपये में एक कमरा बना रही है। वहां पर इन सब की आवश्यकता नहीं है। निगम जिस स्कूल का निर्माण कराएगा उसमें 30 कमरे, दो स्टोररूम, दो कार्यालय कक्ष, दो लाइब्रेरी कक्ष, तीन कमरों के बराबर एक बड़ा हाल, दो विज्ञान कक्ष आदि होंगे। केजरीवाल सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि चार साल में सरकार ने एक भी नया स्कूल नहीं खोला। इतना ही नहीं स्कूल खोलने के लिए 29 खाली प्लाट में सरकार ने एक ईंट भी नहीं लगवाई। आज केजरीवाल सरकार यह कहकर जनता को गुमराह नहीं कर सकती कि उन्होंने जितने क्लास रूम बनवाए हैं, वे एक हजार स्कूलों के बराबर हैं।

मिशन एडमिशन

पांच घंटे देर से शुरू हुए खेल कोटे के ट्रायल

छात्र सुबह साढ़े सात बजे तक पहुंच गए थे स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में, नौ बजे तक दिया गया प्रवेश, ट्रायल के लिए कई विशेषज्ञ व अधिकारी 11 बजे के बाद पहुंचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्नातक में दाखिले के लिए खेल कोटे के ट्रायल मंगलवार से शुरू हो गए हैं। सुबह साढ़े सात बजे तक छात्र ट्रायल के लिए डीयू के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में पहुंचे, लेकिन उन्हें नौ बजे तक प्रवेश दिया गया। प्रवेश के बाद भी वे इंतजार करते रहे। ट्रायल के लिए कई विशेषज्ञ व अधिकारी 11 बजे के बाद पहुंचे। अभिभावकों ने कहा कि डीयू प्रशासन ने यह जानकारी नहीं दी थी कि ट्रायल कब तक शुरू होंगे और कब खत्म होंगे। ट्रायल करीब पांच घंटे की देरी से शुरू हुए।

मंगलवार को स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में ताइक्वांडो में पुरुष एवं महिला वर्ग, फुटबॉल में महिला और बास्केटबॉल में पुरुष वर्ग के विद्यार्थियों के ट्रायल होने थे। ताइक्वांडो और बास्केटबॉल के ट्रायल के लिए छात्र एवं छात्राएं सुबह 7.30 बजे तक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में पहुंच गए थे। फुटबॉल महिला वर्ग के ट्रायल के लिए सुबह 7 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन छात्राओं को एक घंटे की देरी से कॉम्पलेक्स में प्रवेश दिया गया और ट्रायल भी पांच घंटे की देरी से शुरू हुआ।

फुटबॉल महिला वर्ग का ट्रायल 11.30 बजे के बाद और ताइक्वांडो महिला वर्ग का ट्रायल 12.30 बजे के बाद शुरू हुआ। ताइक्वांडो पुरुष वर्ग में आवेदन कर रहे छात्रों की सिर्फ हाइट और वेट की जानकारी ली गई। उन्हें बुधवार को फिर बुलाया गया। बास्केटबॉल का ट्रायल 12.30 बजे के बाद शुरू तो हुआ, लेकिन मुख्य ट्रायल नहीं लिया गया। छात्रों को सिर्फ कुछ एक्सरसाइज कराई गईं। इन छात्रों को भी बुधवार को सुबह बुलाया गया। ताइक्वांडो में 173 छात्र व करीब 153 छात्राएं पहुंची थीं। फुटबॉल में 36 छात्राएं और बास्केटबॉल में करीब 290 छात्र ट्रायल देने पहुंचे थे। खेल कोटे के ट्रायल 6 जुलाई तक चलेंगे।

डीयू के खेल के निदेशक अनिल कलकल से खेल कोटे के ट्रायल के दौरान हुई विभिन्न अव्यवस्थाओं के बारे में सवाल किया गया, उन्हें मैसेज व फोन भी किया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

अंकों के आधार पर ही होगा आंध्र प्रदेश के छात्रों का दाखिला

जासं, नई दिल्ली : डीयू में आंध्र प्रदेश के शिक्षा बोर्ड के छात्रों के दाखिले ग्रेड के बजाय अंकों के आधार पर लिए जाएंगे। डीयू के कुलपति प्रो. योगेश त्यागी और दाखिला समिति के अध्यक्ष प्रो. राजीव गुप्ता ने यह जानकारी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी। आंध्र प्रदेश के छात्रों ने पहले कटऑफ के तहत डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजों में स्नातक में ग्रेड के आधार पर दाखिले ले लिए थे। प्रो. गुप्ता ने कहा कि आंध्र प्रदेश शिक्षा बोर्ड से अंकों के आधार पर मार्कशीट जारी करने का पत्र हमें मिला है। ग्रेड के आधार पर दाखिला देने से एक विशेष राज्य के छात्रों का दाखिला ही कॉलेजों में हो रहा था। डीयू के कांफ्रेंस सेंटर में आंध्र प्रदेश बोर्ड के छात्र समस्या लेकर पहुंचे। छात्र विजय ए ने कहा कि मार्कशीट ग्रेड के आधार पर है। ग्रेड के अंकों को 10 से गुणा करके कॉलेज प्रशासन ने दाखिला दिया। 12वीं में 9.92 सीजीपीए ग्रेड था, जिससे 99.2 फीसद अंक हो गए थे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स में दाखिला हो गया था, अब दाखिला रद हो गया है, क्योंकि ग्रेड के बजाय अंकों के आधार पर दाखिले होंगे।

डीयू में खेल कोटे से दाखिला लेने के लिए मंगलवार को डीयू के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में ताइक्वांडो का ट्रायल देती छात्रा। ध्रुव कुमार

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को मिला कॉलेज का दर्जा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई और मंगलवार सुबह 11 बजे तक चली। डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिषद के सदस्यों ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को कॉलेज का दर्जा देने के एजेंडे को पास कर दिया। डीयू में दो नए केंद्र स्थापित करने के एजेंडे को भी पास किया गया। इसके तहत दो केंद्र सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज और स्कूल ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस (एसपीपीजी) स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए नया केंद्र तैयार होने से इस श्रेणी के विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा। उनके लिए कई कोर्स शुरू होंगे। बैठक में यह एजेंडा भी पास हो गया कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी - मूक) के तहत ही डीयू में कई नए ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएं।

एसएओल को कॉलेज का दर्जा मिलने से यह होगा फायदा : 1999 से पहले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) को कॉलेज का दर्जा प्राप्त था। बाद में इसका नाम स्कूल ऑफ करेसपांडेंस कर दिया गया था। 2004 तक इसका नाम यही रहा, बाद में इसका नाम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग किया गया। एसओएल में 2004 तक सेमेस्टर प्रणाली लागू थी, जिसे बाद में वार्षिक परीक्षा में बदल दिया गया। फिर से कॉलेज का दर्जा मिलने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो भी छात्र एसओएल में दाखिला लेंगे, अगर उनके नंबर बहुत अच्छे होंगे तो उन्हें अन्य रेगुलर कॉलेज में दाखिले का अवसर मिलेगा। एसओएल में सेमेस्टर प्रक्रिया फिर लागू की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से भी अतिरिक्त फंड मिलेगा। इससे एसओएल के शिक्षकों व छात्रों को फायदा होगा। डीयू प्रशासन की तरफ से इसकी मुख्य रूपरेखा भी नए सिरे से तय किए जाने की उम्मीद है।

2000 कर्मचारी काम करते हैं रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया कि इसके निगमीकरण से पहले कर्मचारियों को विश्वास में नहीं लिया।

सुधार का कदम ▶ मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया में संशोधन का विधेयक लोकसभा से पारित

एनएमसी के लिए आएगा अलग बिल : हर्षवर्धन

दो साल के लिए बीओजी के गठन का प्रावधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) को निलंबित रखने और उसकी जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) को दो साल तक काम करने का वैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। चर्चा के दौरान विपक्ष की आशंकाओं को निराधार बताते हुए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह देश में मेडिकल शिक्षा में सुधारों की अभी शुरुआत भर है और आगे आने वाले सालों में और भी क्रांतिकारी सुधार होंगे।

लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए हर्षवर्धन ने बताया कि किन परिस्थितियों में पिछले साल सितंबर में सरकार को एमसीआइ भंग कर बीओजी के गठन का फैसला करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि एमसीआइ देश में मेडिकल शिक्षा में सुधार और विकास का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था और भ्रष्टाचार का पर्याय माने जाने लगा था। एमसीआइ में सुधार की सुप्रीम कोर्ट की कोशिशें भी सफल नहीं हो सकी।

हर्षवर्धन फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ओवरसाइट कमेटी के सदस्यों के इस्तीफे के बाद सरकार के पास अध्यादेश के जरिये एमसीआइ को निलंबित कर बीओजी का गठन करना पड़ा था। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि बीओजी की व्यवस्था केवल दो साल के लिए की गई है और सरकार इस बीच एनएमसी के गठन के लिए अलग से विधेयक लेकर आएगी।

चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदन दल के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई विपक्षी नेताओं ने अध्यादेश के जरिये एमसीआइ को निलंबित करने और बीओजी के हाथ में उसका कामकाज दिये जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि सरकार की कोशिश बीओजी की अंतरिम व्यवस्था को बनाने के बजाय सीधे राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) गठन का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से बीओजी के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में सुधार का सुझाव दिया।

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि एमसीआइ की जगह बीओजी को कामकाज सौंपने का फैसला नया नहीं है। 2010 में भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह घिरने और एमसीआइ के कई पदाधिकारियों के गिरफ्तार होने के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने भी बीओजी का गठन किया था, जो 2013 तक काम करता रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने देश में मेडिकल शिक्षा में सुधारों पर राय देने के लिए प्रोफेसर रंजीत राय चौधरी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने एनएमसी बनाने का फैसला किया था। लोकसभा में आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया गया। लोकसभा में पास होने के बाद इस विधेयक को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। देखना यह है कि सरकार में राज्यसभा में संख्याबल में भारी विपक्ष को इसके लिए मनाने में कितना कामयाब होती है।

बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करने वाले भुगतेंगे छह माह जेल की सजा

- संबंधित कानून मजबूत करने जा रही है सरकार
- दत्तक, सौतेले, बेटी-दामाद एवं अन्य भी माने जाएंगे बच्चे

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब अपने बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करना संतान के लिए महंगा साबित होगा। अपने बुजुर्ग माता-पिता का परित्याग करने वाले बच्चों के लिए जुर्माना और जेल की सजा के मौजूदा प्रावधान में सरकार बदलाव करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने बच्चों की परिभाषा का दायरा विस्तृत करने का मन बनाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कामकाज में बुजुर्गों की सुरक्षा और कल्याण संबंधी कानून को मजबूत बनाने को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत मंत्रालय ने अपने बुजुर्ग माता-पिता का परित्याग करने वाले या उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए मौजूदा तीन महीने जेल की सजा को बढ़ाकर छह महीने करने का प्रस्ताव किया है। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष इसमें सुधार का प्रस्ताव पेश करेगा।

दामाद, बहू भी माने जाएंगे बच्चे: मंत्रालय ने इसमें बच्चों की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें दत्तक पुत्र/पुत्री या सौतेले बच्चे, दामाद और बहू, नाती-पोतों और अपने कानूनी अभिभावक द्वारा पालन पोषण किए गए नाबालिग बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा समय में बच्चों की परिभाषा में माता-पिता की सिर्फ अपनी संतान और नाती-पोते ही आते हैं। प्रस्तावित मसौदा में माता-पिता के भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह की राशि की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव है। अधिकारी ने बताया, 'अच्छी नौकरी और अच्छी कमाई करने वाले बच्चों को माता-पिता की देखभाल के लिए अधिक पैसे देने चाहिए।'

संसद प्रश्नोत्तर

सोनिया ने रायबरेली कोच फैक्ट्री के निजीकरण का लगाया आरोप

मंगलवार को लोकसभा में बोलतीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

- संप्रग अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया मजदूर यूनियनों को विश्वास में न लेने का आरोप
- निजी कंपनियों को सरकारी संपत्तियां बेचने की दिशा में पहला कदम बताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे की उत्पादक इकाइयों के कॉरपोरेटाइजेशन (निगमीकरण) के सरकार के प्रस्ताव का संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कड़ा विरोध किया। शून्यकाल शुरू होते ही रायबरेली से कांग्रेस सांसद गांधी ने अपने क्षेत्र की मॉडर्न कोच फैक्ट्री के कॉरपोरेटाइजेशन के प्रस्ताव को निजीकरण की दिशा में पहला कदम करार दिया। सदन में बहुत कम अपनी बात रखने वालीं सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले फैक्ट्री के कर्मचारियों और मजदूर यूनियनों तक को विश्वास में नहीं लिया।

कार्यवाही की शुरुआत में स्पीकर ने सोनिया गांधी का नाम पुकारा। जब वह बोलने के लिए उठीं तो समूचे विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं। उन्होंने रायबरेली की कोच फैक्ट्री का हवाला देते हुए रेलवे की उत्पादन इकाइयों के कॉरपोरेटाइजेशन का मामला उठाया और कहा कि सरकार करोड़ों रुपये की संपत्ति को निजी कंपनियों को सौंपने की शुरुआत कर रही है। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संप्रग सरकार ने मेक इन इंडिया की भावना के तहत इसकी शुरुआत की थी। इस पर काफी निवेश भी हुआ है। कर्मचारियों की मेहनत की वजह से यह एक अच्छी इकाई बनकर उभरी है। सरकार के इस कदम से अब 2000 कर्मचारियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, 'क्या हमें ऐसे फैसलों की संसदीय जांच की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।'

सोनिया गांधी ने कहा, 'मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि उसका काम लोक कल्याण है, निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना नहीं।' देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। संप्रग अध्यक्ष ने कहा कि अब एचएएल, एमटीएनएल और बीएसएनएल के साथ क्या हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। गांधी ने राजग सरकार द्वारा अलग रेल बजट की प्रथा को समाप्त किए जाने की भी आलोचना की।

न्यूज गैलरी

पीएमएलए संशोधन पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) को मनी बिल के जरिए लाने को चुनौती देने की एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की इस याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) को केवल मनी बिल कके जरिए पारित किया जाता था, इसलिए उसमें नया संशोधन संविधान का उल्लंघन है। जस्टिस एसए बोबडे और बीआर गवाई की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें रमेश ने दिल्ली हाईकोर्ट के उनकी ऐसी ही एक याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से खंडपीठ के समक्ष पेश वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने अदालत को बताया कि पीएमएलए को वर्ष 2015 से मनी बिल के जरिए पारित किया जा रहा है। जबकि पीएमएलए संशोधनों को वर्ष 2013 तक साधारण बिलों के जरिए ही पारित किया जाता था। 2015 से 2018 के बीच उन्हें बतौर मनी बिल पारित किया गया, जो संविधान का उल्लंघन है। (प्रेट्र)

विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग

नई दिल्ली : द्रमुक ने अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि इन विधायकों ने 2017 में विश्वास प्रस्ताव के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी के खिलाफ मतदान किया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम समेत 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली द्रमुक की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी। मद्रास हाई कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका अप्रैल में खारिज कर दी थी। (प्रेट्र/एएनआइ)

दिल्ली व विजयवाड़ा में पहले आधार सेवा केंद्र की शुरुआत

नई दिल्ली : यूआइडीएआइ ने दिल्ली व विजयवाड़ा में अपने पहले आधार सेवा केंद्र की शुरुआत कर दी है। साल के अंत तक ऐसे 114 केंद्रों की स्थापना की योजना है। इन केंद्रों पर आधार पंजीकरण व सूचनाओं में परिवर्तन आदि कार्य किए जाएंगे। ये केंद्र यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) के अधीन होंगे और वही इनका संचालन भी करेगा। बैंक, पोस्टऑफिस और अन्य सरकारी परिसरों में संचालित हजारों आधार केंद्रों पर भी काम जारी रहेगा। (प्रेट्र)

सिंगापुर में नीरव मोदी के बहन-बहनोई के बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश

- हाई कोर्ट ने दिए आदेश, ईडी ने दी जानकारी,खाते में जमा हैं 44.41 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : पीएनबी बैंक घोटाले के भगोड़े आरोपित नीरव मोदी की बहन पूर्वी और उसके बहनोई मयंक मेहता के सिंगापुर में बैंक खाते को वहां के हाई कोर्ट ने फ्रीज करने का आदेश दिया है। इस बैंक खाते में 61.22 लाख डॉलर (44.41 करोड़ रुपये) की राशि जमा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि यह बैंक खाता ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित कंपनी 'पैविलियन प्वाइंट कॉरपोरेशन' के नाम पर है और इस कंपनी का स्वामित्व पूर्वी और मयंक मेहता के पास है। सिंगापुर हाई कोर्ट ने उक्त आदेश ईडी के अनुरोध पर दिया है, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि उसने यह आदेश कब दिया। बहरहाल, हाई कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है जब पिछले ही हफ्ते स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने नीरव मोदी और पूर्वी के चार स्विस बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें कुल 283.16 करोड़ रुपये की राशि जमा थी।

बता दें कि सिंगापुर के उक्त बैंक खाते और स्विस बैंक के चारों खातों को ईडी ने पिछले साल सितंबर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत प्रोविजनल ऑर्डर जारी कर अटैच कर लिया था। इस साल मार्च में न्यायिक प्राधिकारी ने ईडी के ऑर्डर की पुष्टि भी कर दी थी। ईडी के मुताबिक तब इन

नीरव मोदी फाइल फोटो

बैंक खातों में करीब 278 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद ईडी ने सिंगापुर के अधिकारियों से खाते को फ्रीज करने का अनुरोध किया था, साथ ही अटैचमेंट ऑर्डर से संबंधित दस्तावेज भी उन्हें भेजे थे। मालूम हो कि नीरव मोदी इस समय ब्रिटिश जेल में बंद है और भारत उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा है।

ज्ञातव्य है कि पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपित नीरव मोदी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने उसे भारत लाने के प्रयास में जुटी है।

ईडी ने सिंभावली चीनी मिल पर की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हापुड़ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंभावली शुगर्स लिमिटेड की इकाई हापुड़ स्थित सिंभावली चीनी मिल के खिलाफ किसानों को भुगतान के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) से 148.59 करोड़ का ऋण लेकर धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत सिंभावली चीनी मिल की डिस्टिलरी इकाई की जमीन, इमारत, संयंत्र और मशीनरी जैसी 109.80 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

ईडी ने मंगलवार को बताया कि उसने बैंक ऋण लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग नियम के तहत जांच करने के सिलसिले में सिंभावली चीनी मिल की करीब 110 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने कहा कि डिस्टिलरी इकाई की जमीन, इमारत, संयंत्र और मशीनरी आदि संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के अंतर्गत प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया था। सिंभावली चीनी मिल पर आरोप है कि उसने गन्ना मूल्य के भुगतान के बहाने किसानों और ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की थी।

राज्यसभा में प्रश्न काल में दिए गए सभी सवालों के जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। प्रश्नकाल में सभी तारांकित सवालों के जवाब दिए गए और इस कामयाबी पर सदस्यों ने सभापति एम. वेंकैया नायडू को बधाई दी। इसके पहले इसी साल तीन और चार जनवरी को सदन में सभी सूचीबद्ध सवाल उठ सके थे, जबकि इसके पहले दो जनवरी 2018 को उच्च सदन में सभी तारांकित सवालों के जवाब दिए गए थे। तब 15 साल बाद सभी तारांकित सवालों के जवाब दिए जाने का रिकार्ड कायम हुआ था। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक 2018 के पहले आखिरी बार 2002 में सदन के 197वें सत्र में प्रश्नकाल में निर्धारित एजेंडा पूरा हुआ था। मंगलवार को प्रश्नकाल के लिए 15 सवाल सूचीबद्ध थे, जिनके जवाब दिए गए। हालांकि सभी सवालों के पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके। प्रश्नकाल में 13 राजनीतिक दलों के कुल 36 सदस्यों और एक नामित सदस्य ने मुख्य और पूरक प्रश्न उठाए। एमपी वीरेंद्र कुमार (निर्दलीय), वाईएस चौधरी (भाजपा) और माजिद मेनन (एनसीपी) तीन ऐसे सदस्य हैं जिनके नाम से सवाल सूचीबद्ध थे, लेकिन वे प्रश्नकाल के दौरान अनुपस्थित थे। चौधरी के सवाल के संदर्भ में पूरक प्रश्न जरूर उठाए गए। अन्य दो सवालों को सदन में रखा हुआ मान लिया गया।

लोकसभा में भिड़े भाजपा और तृणमूल सदस्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: भाजपा सांसद दिलीप घोष द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार पर पार्टी सदस्यों पर हमला करने का आरोप लगाए जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में शोरगुल शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध किया। एक समय दोनों पार्टियों के सदस्य आमने-सामने आ गए।

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, अर्जुन सिंह और उन पर हमला किया गया। तृणमूल द्वारा किए गए हमले में 150 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए। वहीं कई अन्य कार्यकर्ताओं को नशीले पदार्थों के मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने राज्य की पुलिस पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इतना सुनते ही तृणमूल सांसद चिल्लाने लगे। इस पर कुछ भाजपा सांसद घोष के समर्थन में आवाज उठाते दिखे।

पश्चिम बंगाल में एक करोड़ कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य : भाजपा पश्चिम बंगाल में एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को राज्य के प्रमुख नेताओं की एक बैठक के बाद कहा कि पार्टी के 42 लाख से अधिक सदस्य हैं। सदस्यता अभियान के दौरान इसे एक करोड़ से अधिक करने के लिए काम करेंगे। भाजपा छह जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के दौरान राज्य की 42 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की थी। उसे इन चुनावों में 2.3 करोड़ से अधिक वोट मिले थे।

आम जनजीवन से जुड़े शोध कार्यों को मिलेगा बढ़ावा

- यूजीसी शुरू करेगी 'स्ट्राइड' नाम की एक नई शोध योजना
- पचास लाख से पांच करोड़ तक की मिलेगी वित्तीय मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आम जनजीवन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने स्ट्राइड नाम की एक नई शोध योजना शुरू करने का एलान किया है। इसमें अलग-अलग विषयों और क्षेत्र से जुड़े नए शोध कार्यों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पचास लाख से लेकर पांच करोड़ तक वित्तीय मदद दी जाएगी। यूजीसी की इस पहल को देश में शोध की एक नई संस्कृति को विकसित करने से जोड़कर देखा जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मुताबिक इस नई पहल से विश्वविद्यालय सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को काफी मजबूती मिलेगी। इस योजना को आठ जुलाई को लांच किया जा सकता है। इसके बाद शोध से जुड़े प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। योजना के तहत मंजूर किए जाने वाले सभी शोध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे। यह देश को आर्थिक मजबूती देने के साथ विकास में मदद देंगे। यूजीसी ने इसे लेकर एक सलाहकार कमेटी का भी गठन किया है, जो यूजीसी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्द्धन की अध्यक्षता में काम करेगी। कमेटी इस दौरान आने वाले शोध प्रस्तावों को जांचेगी और अंतिम रूप देगी।

शोध कार्यों के आधार पर तय होगी वित्तीय मदद

योजना के वित्तीय मदद का निर्धारण शोध कार्यों के स्वरूप पर तय होगा। इसमें सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान और विकास को गति देने वाले शोध कार्यों को प्रमुखता से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत ऐसे शोध कार्यों को पचास लाख से लेकर एक करोड़ तक की वित्तीय मदद दी जाएगी। योजना के दूसरे चरण में विवि और कालेजों की नई प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए मदद दी जाएगी। इन्हें एक करोड़ तक की वित्तीय मदद दी जाएगी। योजना का जो तीसरा पहलू होगा, उसके तहत इतिहास, दर्शनशास्त्र, पत्रकारिता सहित जन सामान्य से जुड़े अलग-अलग विषयों में शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत पांच करोड़ तक की वित्तीय मदद दी जाएगी।

इनर लाइन परमिट अनिवार्यता के कानून के खिलाफ अर्जी खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड जैसे राज्यों में दूसरे राज्य से प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य करने का अधिकार देने वाले कानून को चुनौती देने वाली अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, 'हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।'

याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य के भीतर ही नागरिकों के आवागमन को सीमित करने का अधिकार राज्यों को देने वाला यह कानून मनमाना और अनुचित है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 और 21 का उल्लंघन होता है। उपाध्याय का तर्क था कि नगालैंड में सिर्फ आठ फीसद हिंदू आबादी है और राज्य में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता का नियम संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। पीठ जब सारा काम खत्म करके उठ रही थी तो उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस लेने और सक्षम मंत्रालय में इस संबंध में प्रतिवेदन करने की अनुमति मांगी, लेकिन पीठ ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। पीठ ने कहा कि वह इस पर विचार करने को इच्छुक नहीं है।

लोकपाल ने किया 480 शिकायतों का निस्तारण

- लोकपाल को भ्रष्टाचार से जुड़ीं शिकायतें ही भेजने की अपील
- लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए सर्वोच्च संस्था है

नई दिल्ली, प्रेट्र : भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल ने इस साल मई तक मिली 480 शिकायतों का निस्तारण कर दिया है। इनमें से कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं थीं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि लोकपाल लोगों को यह सूचित करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग उन मामलों की शिकायतें उन्हें नहीं भेजें जो भ्रष्टाचार से जुड़ी नहीं हों। बता दें कि केंद्र ने अभी भी लोकपाल को शिकायतें भेजने के लिए एक फॉर्म के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है।

एक अधिकारी ने लोकपाल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, 'लोकपाल के कार्यालय में मिली सभी शिकायतों की छंटनी करने का फैसला किया गया है चाहे वे जिस भी रूप में भेजी गई हों। 31 मई 2019 तक मिली 480 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।' उन्होंने बताया कि छंटनी के बाद जो शिकायतें लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं उनका निस्तारण कर दिया गया और शिकायतकर्ताओं को सूचित कर दिया गया है। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए सर्वोच्च संस्था है। उसे समयबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करनी होती है। लोकपाल ने कहा, 'नागरिकों को सलाह दी जाती है कि

न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। (फाइल फोटो)

पेंशन, सेवा संबंधी मुद्दों और सार्वजनिक शिकायतें संबंधित विभागों के आधिकारिक पोर्टलों या वेबसाइटों पर दी जानी चाहिए न कि लोकपाल को।' राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को 23 मार्च को पद की शपथ दिलाई थी। लोकपाल का मुख्य काम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना है। इस वर्ष तक निपटाए गए मामलों में कई भ्रष्टाचार से जुड़ी नहीं थीं।

राष्ट्रीय न्यायिक चयन आयोग से जगी थी पारदर्शिता की आस

प्रथम पृष्ठ से आगे

जस्टिस पांडेय ने प्रधानमंत्री से कहा है, 'जब आपकी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक चयन आयोग स्थापित करने का प्रयास किया था तब पूरे देश को न्यायपालिका में पारदर्शिता की आशा जगी थी, परंतु दुर्भाग्यवश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायिक चयन आयोग के गठन से न्यायाधीशों में अपने पारिवारिक सदस्यों की नियुक्ति में बाधा आने की संभावना बलवती होती जा रही थी।'

न्यायसंगत और कठोर निर्णय लेने का किया अनुरोध : जस्टिस पांडेय ने लिखा है कि पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का विवाद बंद कमरों से सार्वजनिक होने का प्रकरण हो, हितों के टकराव का विषय हो अथवा सुनने के बजाय चुनने के अधिकार का विषय हो, न्यायपालिका की गुणवत्ता एवं अक्षुण्णता लगातार संकट में पड़ने की स्थिति रहती है। उन्होंने स्वयं के बारे में कहा है, 'मैं बेहद साधारण पृष्ठभूमि से अपने परिश्रम और निष्ठा के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होकर पहले न्यायाधीश और अब हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूं। अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त विषय पर विचार करते हुए आवश्यकतानुसार न्यायसंगत और कठोर निर्णय लेकर न्यायपालिका की गरिमा पुनःस्थापित करने का प्रयास करेंगे। जिससे किसी दिन हम यह सुनकर संतुष्ट हो सकें कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति अपनी योग्यता, परिश्रम और निष्ठा के कारण भारत का प्रधान न्यायाधीश बन पाया।'

कह के रहेंगे — माधव जोशी

उलझन

कांग्रेस नेतृत्व के संकट से दो चार है, इसी के कारण अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति नहीं बना पा रहा संयुक्त विपक्ष

कांग्रेस के 'त्यागपत्र संकट' से बाकी विपक्ष परेशान

- कांग्रेस की उलझन के कारण अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति नहीं बना पा रहा संयुक्त विपक्ष

संजय मिश्र, नई दिल्ली

राहुल गांधी के 'त्यागपत्र संकट' से जूझ रही कांग्रेस की अंदरूनी चुनौती संसद के बजट सत्र में बाकी विपक्षी दलों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। संसद में सरकार की घेरेबंदी के लिए छोटी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का बार-बार दरवाजा खटखटा रही हैं। मगर कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर संकट में इस कदर उलझी है कि संसद में मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने का एजेंडा ही भूल गई है।

कांग्रेस की संसद में फिलहाल इस ठहरी सियासत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सत्र शुरू हुए तीन सप्ताह हो गए हैं। मगर सरकार की घेरेबंदी तो दूर अभी तक सदन से एक बार भी विपक्ष का वाक आउट तक नहीं हुआ है। संसद में आपसी समन्वय के सहारे सरकार को विपक्षी दलों की साझी ताकत का अहसास कराने के लिए कांग्रेस की सक्रिय अग्रणी भूमिका की जरूरत बताते हुए एक वामपंथी नेता ने कहा कि सरकार दोनों सदनों में सरपट दौड़ रही है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पर तगड़ा वार कर सरकार को असहज किया जा सकता था।

वामपंथी नेता का यह भी कहना था कि इस

राहुल गांधी फाइल फोटो

सत्र के दौरान पिछले दो सप्ताह में कई बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से विपक्षी खेमे के नेताओं ने चर्चा की। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, अहमद पटेल आदि से वाम नेताओं के अलावा तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और राकांपा नेताओं ने बात की। इस दौरान कांग्रेस से झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामले, आर्थिक विकास दर में आई सुस्ती, बेरोजगारी दर के 45 सालों में सबसे अधिक पर पहुंचने, जम्मू एवं कश्मीर मसले से लेकर दल बदल के सहारे राज्यसभा में संख्या बढ़ाने की भाजपा की सियासत जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों की एकजुट रणनीति बनाने के लिए कहा गया। इन नेताओं ने पार्टी नेतृत्व से चर्चा कर इस दिशा में कदम उठाने की बात भी कही। मगर आलम यह है कि रणनीति बनाना तो दूर संसद में कांग्रेस के रणनीतिकार अपने नेतृत्व के संकट के जाल से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

संसद में तृणमूल के भी एक वरिष्ठ नेता ने सत्र के दौरान विपक्षी दलों का एजेंडा आगे नहीं बढ़ पाने के लिए कांग्रेस की मौजूदा उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि सरकार धुआंधार तरीके से बिल पारित कराने में जुट गई है। सत्ता पक्ष अपने हिसाब से मुद्दों पर बहस भी करा रहा है और विपक्षी दलों की स्थिति फिलहाल मूकदर्शक जैसी हो गई है। इसीलिए अपने संकट में उलझी कांग्रेस के रुख से परेशान अन्य छोटे विपक्षी दल सरकार पर सवालों की बौछार करने के लिए आपसी मशविरे और समन्वय की रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर शीघ्र ही अन्य छोटे विपक्षी दल कोई निर्णय ले सकते हैं।

19 फीसद नकदी बढ़ी है देश में नोटबंदी के बाद। डिजिटलीकरण के प्रयासों के बावजूद वर्तमान में प्रचलन में मौजूदा नोटों का मूल्य 21,137.64 अरब रुपये है। नोटबंदी से पहले चार नवंबर, 2016 को 17,741 अरब रुपये के नोट प्रचलन में थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 3 जुलाई 2019

बंगाल सरकार भी देगी आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसद आरक्षण

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी, विधेयक पर लिखित आदेश आना बाकी
- सरकारी नौकरी व शिक्षा संस्थानों में दाखिले के मामले में मिलेगा आरक्षण

केंद्र सरकार की तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसद आरक्षण देने का एलान किया है। यह आरक्षण नौकरी व शिक्षा संस्थानों में दाखिले के मामले में उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें पहले से किसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मंगलवार को विधानसभा में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा की गई। हालांकि, इससे संबंधित विधेयक पर लिखित आदेश आना अभी बाकी है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की थी। आठ लाख रुपये से कम की सालाना आय वालों को इसका लाभ देने की घोषणा की गई थी। जानकारों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका लाभ भी मिला था। तब मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी केंद्र के इस कदम की सराहना की थी, हालांकि इस आरक्षण की तुलना केंद्र के आरक्षण से किए जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जाहिर की है।

नियम व शर्तें स्पष्ट नहीं : आरक्षण का लाभ पाने के लिए नियम व शर्तें क्या होंगी, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जब अधिसूचना जारी की जाएगी, तब नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पार्थ ने आगे कहा कि अब से राज्य में सरकारी नौकरी व सरकारी शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10 फीसद आरक्षण मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में इस बार राज्य में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजनीतिक विश्लेषक बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार के इस निर्णय को काफी अहम बता रहे हैं।

इन्हें मिलेगा आरक्षण

आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, जो पहले से ही आरक्षण का लाभ पा रहे हैं यानी पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

स्थिति अनुकूल होती तो बांग्लादेश को देते तीस्ता का पानी : मुख्यमंत्री

जागरण संवाददाता, कोलकाता

ममता बनर्जी फाइल फोटो

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि अगर स्थिति अनुकूल होती तो वह मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश के साथ नदी का जल साझा करतीं। विधानसभा में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे (बांग्लादेशी) आहत हैं, क्योंकि हम उनके साथ तीस्ता के पानी का बंटवारा नहीं कर सके। अगर मुझमें क्षमता होती तो मैं उनके साथ निश्चित तौर पर तीस्ता का पानी साझा करती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश हमारा मित्र है और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी फरक्का बैराज से बांग्लादेश के साथ पानी साझा किया था।

उल्लेखनीय है कि तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर सितंबर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बांग्लादेश दौरे के दौरान हस्ताक्षर होने थे, लेकिन ममता बनर्जी की आपत्तियों के कारण आखिरी क्षण में इस समझौते को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बटवारा समझौते का विरोध करते हुए कहा था कि उत्तर बंगाल के लोगों को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। उन्होंने 2017 में कहा था, तीस्ता सूख रही है। अगर हम इसके पानी का बंटवारा करेंगे तो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के लोगों को दिक्कत होगी, किसान खेती नहीं कर पाएंगे। तीस्ता बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर से दिसंबर से मार्च की अवधि के दौरान जब पानी का बहाव 5,000 क्यूसेक से घटकर 1,000 क्यूसेक पर पहुंच जाता है।

ममता ने नए लोकसभा अध्यक्ष को भेजा 'संदेश'

जेएनएन, कोलकाता : मोदी सरकार व भाजपा के खिलाफ लगातार आक्रामक रहने वालीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़वाहट भरे माहौल के बीच हाल में नए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला को बधाई देते हुए उनके लिए बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई भेजी है। तृणमूल सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर पार्टी अध्यक्ष ममता की ओर से भेजे गए प्रसिद्ध बंगाली मिठाई 'संदेश' का एक डिब्बा और पत्र भेंट किया। इस पत्र के जरिये ममता ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। साथ ही उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा के नए अध्यक्ष ने पद संभालने के साथ ही लोकसभा में कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव करने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत नए सासंदों को संसद में बोलने के लिए भरपूर मौका देना शामिल है। बिरला राज्य विधानसभाओं की बैठकों की कम होती संख्या से भी चिंतित हैं। वह इसको लेकर सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक भी बुलाने वाले हैं।

सनी ने दी सफाई, प्रतिनिधि नहीं पीए किया है नियुक्त

सुनील थानेवालिया, गुरदासपुर

- ट्वीट कर कहा, बेवजह मुद्दे को तूल दे विवाद को जन्म देने की कोशिश

पंजाब के गुरदासपुर में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को लेकर विवाद में आए भाजपा सांसद सनी देयोल ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि बड़े दुख की बात है कि बिना किसी बात के इस मामले को उछाला गया है। विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैंने पीए नियुक्त किया है प्रतिनिधि नहीं। वह मेरे गुरदासपुर स्थित कार्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा। जब मैं गुरदासपुर से बाहर संसद में या काम के सिलसिले में सफर पर रहूंगा तो हलके में काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। पीए की नियुक्ति इसलिए की गई है कि कोई काम प्रभावित न हो। इससे मैं रोजमर्रा के काम से अवगत रहूंगा।

गौरतलब है कि मोहाली के फिल्म निर्माता गुरप्रीत सिंह पलहेड़ी को अपना प्रतिनिधि बनाए जाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने सनी देयोल की काफी आलोचना की थी। आप के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी ने सनी द्वारा प्रतिनिधि बनाने पर आपत्ति जताई थी।

सनी ने आगे लिखा, 'पार्टी लीडरशिप हलके में कामकाज देखने के लिए मौजूद है। उनका पूरा समर्थन है। मैं चुना हुआ सांसद होने के नाते सही अर्थ में गुरदासपुर के मुद्दों के प्रति समर्पित हूं। अपनी ओर से बेस्ट देने और लोगों की सेवा की पूरी कोशिश करूंगा।' सनी देयोल ने ट्वीट में कहीं भी गुरप्रीत पलहेड़ी के नाम का जिक्र नहीं किया।

खन्ना और जाखड़ ने नहीं किया था ऐसा : इस विवाद के पीछे एक वजह यह भी रही कि पूर्व सांसद विनोद खन्ना और सुनील जाखड़ ने कभी इस तरह से अपना प्रतिनिधि घोषित नहीं किया था। पीए जरूर नियुक्त होते रहे हैं। गुरप्रीत को प्रतिनिधि बनाते ही विरोधियों को एक और मौका मिल गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सनी देयोल हलके में आना ही नहीं चाहते।

स्थानीय नेता बोले, इसमें कोई बुराई नहीं : गुरदासपुर के जिला भाजपा अध्यक्ष बालकृष्ण मित्तल का कहना है कि गुरप्रीत पलहेड़ी ने चुनाव में बहुत मदद की थी। इसलिए उन्हें सनी देयोल ने पीए बनाया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। पठानकोट के जिला भाजपा अध्यक्ष विपिन महाजन का कहना है कि वे स्थानीय नेताओं को साथ लेकर इस मुद्दे पर हाईकमान से बात करेंगे। सांसद को स्थानीय नेताओं से तालमेल रखना चाहिए।

15 साल बाद द्रमुक की मदद से संसद में लौटेंगे वाइको

चेन्नई, प्रेट्र : एमडीएमके महासचिव वाइको 15 साल बाद द्रमुक की मदद से संसद में लौटेंगे। मंगलवार को पार्टी ने उन्हें 18 जुलाई को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बता दें कि श्रीलंकाई तमिलों के कट्टर समर्थक रहे 75 वर्षीय वाइको द्रमुक की तरफ से 1978 से 1996 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वह दो बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। आखिरी बार वह 1999-2004 तक लोकसभा के सदस्य रहे।

दरअसल, चुनाव पूर्व समझौते के तहत द्रमुक ने राज्यसभा की तीन सीटों में से एक सीट एमडीएमके को देने का फैसला किया था। दो अन्य सीटों पर द्रमुक ने सोमवार को प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। द्रमुक ने ट्रेड यूनियन नेता एम षणमुगम और तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट जनरल पी विल्सन को प्रत्याशी बनाया है। विस में संख्या बल के हिसाब से राज्य में रिक्त हो रही छह राज्यसभा सीटों के लिए अन्नाद्रमुक और द्रमुक तीन-तीन सीटों पर अपने प्रत्याशी आसानी से जिता सकेंगे। 234 सदस्यीय विस में 123 सदस्य अन्नाद्रमुक के हैं जबकि द्रमुक के 100 सदस्य हैं। द्रमुक की सहयोगी कांग्रेस के सात और आइयूएमएल का एक विधायक है। अन्नाद्रमुक गठबंधन की बात करें तो उसने पार्टी के वरिष्ठ नेता केपी मुनुसामी और मगन हुसैन को प्रत्याशी बनाया है जबकि चुनाव पूर्व समझौते के तहत पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट पीएमके को दी है।

शिवराज के 'तीर्थ दर्शन' पर कमलनाथ सरकार की कैंची

फैसला ▶ 200 करोड़ का बजट छह करोड़ में सिमटा

अब तक सवा सात लाख से अधिक लोग कर चुके हैं सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

कमलनाथ फाइल फोटो

मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की छवि निखारने में अहम भूमिका निभाने वाली 'तीर्थ दर्शन योजना' के पहिए थम गए हैं। कमलनाथ सरकार ने इसे लाल झंडी दिखा दी है। दरअसल, 2018 के बजट में बुजुर्ग और दिव्यांगों को तीर्थ कराने के लिए भाजपा सरकार ने दो सौ करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने मात्र छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

कमलनाथ सरकार ने इस साल प्रयागराज में कुंभ के दौरान प्रदेश के चार शहरों से तीर्थ दर्शन ट्रेन चलाई, लेकिन उसके बाद से कोई ट्रेन नहीं चली। आर्थिक तंगी और किसान कर्जमाफी के लिए रकम का इंतजाम करने के लिए सरकार पिछली सरकार की तीर्थदर्शन जैसी कई योजनाओं के बजट में कटौती कर चुकी है।

तत्कालीन शिवराज सरकार ने यह योजना 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए तीन सितंबर 2012 से शुरू की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका लाभ भी मिला था। इस मुफ्त तीर्थ यात्रा का लाभ सिर्फ उन लोगों के लिए था, जो करदाता नहीं हैं। योजना की लोकप्रियता देखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 'तीरथ बरत' नामक योजना शुरू की थी। केंद्र सरकार ने भी 'प्रवासी भारतीय तीर्थदर्शन योजना' प्रारंभ की है। लेकिन, प्रदेश में अब बद्रीनाथ, रामेश्वरम्, द्वारकाधाम और जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ की चारधाम यात्रा अब सरकारी खर्च पर नहीं हो पाएगी।

तीर्थ दर्शन योजना पर राज्य सरकार पिछले आठ साल में सवा 700 करोड़ रुपये खर्च कर सात लाख से अधिक बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुकी है। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत हर धर्म के तीर्थ स्थानों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही थी। अब तक हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णोदेवी, शिर्डी, गया, काशी, अमृतसर, तिरपति, सम्मेद शिखर, श्रवण बेलगोला वेलगणि चर्च (नागपट्टम), गंगासागर कामाख्या देवी, गिरनारजी, पटना साहिब, उज्जैन, चित्रकूट, महेश्वर सहित अजमेर शरीफ के लिए लोगों को तीर्थ यात्रा का लाभ सरकार दिला चुकी है।

सिर्फ छह ट्रेन चली इस साल : कमलनाथ सरकार के वजूद में आने के बाद मात्र छह ट्रेन चलाई गईं। खासतौर से प्रयागराज में आयोजित कुंभ के दौरान सरकार ने चार शहरों से तीर्थयात्रियों को कुंभ स्नान के लिए भेजा था। हरदा, गुना, जबलपुर और बुरहानपुर से चार ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई गई थीं। ट्रेन में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भोजन, बीमा, उपचार सहित सारी सुविधाएं सरकारी खर्च पर मुहैया कराई जाती हैं। सूत्रों का मानना है कि जुलाई में एक ट्रेन चलाई जा सकती है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

मप्र में सवर्ण आरक्षण लागू

नईदुनिया, भोपाल : कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में सवर्ण आरक्षण मंगलवार से लागू कर दिया। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जिन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां अगले सत्र से यह नियम प्रभावी होगा। कोटा का लाभ लेने के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से निचले स्तर के अधिकारी से बनवाना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण लागू किए जाने के निर्देश जारी करते हुए बताया कि अब राज्य लोक सेवा आयोग व अन्य एजेंसी के माध्यम से जो भी सीधी भर्ती होगी, उसमें यह आरक्षण लागू होगा।

17 जातियों के फैसले को लेकर घिरी उप्र सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट
- दिया तर्क, हाई कोर्ट के आदेश पर लिया फैसला
- केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद विपक्ष हुआ आक्रामक

उत्तर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का राज्य सरकार का फैसला हवन में हाथ जलाने जैसा साबित हो रहा है। सरकार का तर्क है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया लेकिन, सवाल उठने लगा है कि 2017 के कोर्ट के आदेश की सुध इतनी लंबी अवधि के बाद क्यों आई।

विपक्षी दलों ने इस मामले में राज्य सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। जबकि केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलौत ने इसे अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के अधिकार के दायरे से बाहर का बताकर और फजीहत कर दी। हालांकि, गहलौत ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार प्रक्रिया के तहत यह प्रस्ताव भेजेगी तो इस पर विचार होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। राज्य सरकार का तर्क है कि कोर्ट की अवमानना न हो, इसलिए उसके आदेश का पालन करने की मंशा से सत्रह अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का फैसला लिया गया।

हालांकि, यह मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि सरकार के मंत्री भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री तो इस सवाल पर कन्नी काट गये। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा कि न्यायालय के निर्णय के क्रम में समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी किया है। यह तो सभी जानते हैं कि आरक्षण में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार का है। केंद्रीय मंत्री थावर चंद के बयान के संदर्भ में कहा कि बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने राज्यसभा में सवाल ही भ्रामक किया था। यह संदर्भ ही नहीं दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में आदेश जारी किया गया है।

सरकार की खुल गई पोल : ओपी राजभर : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उप्र सरकार की मंशा उप चुनाव में वोट लेने की थी लेकिन जल्द ही पोल खुल गयी। अब केंद्र सरकार ने भी माना कि राज्य की योगी सरकार का 17 ओबीसी जातियों को एससी सूची में शामिल करने का कदम असंवैधानिक है।

हाई कोर्ट ने 29 मार्च, 2017 को दिया था आदेश : 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के लिए सपा की सरकार ने 21 दिसंबर 2016 को एक आदेश जारी किया। इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने डा. बीआर आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 29 मार्च 2017 को आदेश पारित किया। इस आदेश के अनुपालन में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने 24 जून को इन जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया।

युवा अफसर अपनाएं जन-केंद्रित दृष्टिकोण : मोदी

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के युवा अफसरों से कहा है कि उन्हें सहायक सचिवों के रूप में मिले लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नए नजरिए और विचारों को अपनाने की जरूरत है। पीएम ने अफसरों से यह भी कहा कि नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर ही वे अपने काम को कहीं अधिक प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। 2017 बैच के करीब 160 अफसरों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के क्रम में फील्ड ट्रेनिंग के दौरान अपने अनुभव बांटे। इन अफसरों को हाल ही में केंद्र सरकार में कुछ समय के लिए सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। युवा अफसरों ने फील्ड ट्रेनिंग के दौरान मिले अनुभवों को मसूरी में क्लासरूम प्रशिक्षण के दौरान सिखाए गए पाठों से भी जोड़ा। इन अफसरों ने आकांक्षी जिलों में भी काम किया है।

पीएम ने कहा, आपको तीन महीनों के लिए केंद्र सरकार में काम करने का जो मौका मिला है वह बेहद अहम है और यह एक सुविचारित प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके पास इस दौरान नीति निर्धारण में दखल देने का मौका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार के कामकाज में नवीनता और ताजगी लाना है। पीएम ने कहा, अफसरों को अपने सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में साफ-सुथरे समाधान के साथ आगे आना चाहिए।

सिद्दरमैया ने कहा, विधायकों के इस्तीफों के लिए मोदी, शाह और भाजपा जिम्मेदार

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में अपने दो विधायकों के इस्तीफ के दो दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती दिखी। पार्टी के असंतुष्ट विधायकों से संपर्क करने की कोशिशों के बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने उसके दो विधायकों के इस्तीफों के लिए भाजपा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग 13 महीने पुरानी एचडी कुमारस्वामी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरकार के पूरी तरह सुरक्षित होने की बात भी कही।

दरअसल, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई और विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और इस्तीफा दे चुके विधायक आनंद सिंह और रमेश जरकोहली द्वारा उठाए गए कदमों का अनुकरण कर सकते हैं। इन संभावनाओं के मद्देनजर ही सिद्दरमैया ने मंगलवार को कई असंतुष्ट विधायकों से संपर्क किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'भाजपा किसी भी तरह से राज्य सरकार को गिराकर सत्ता पाना चाहती है। विधायकों का इस्तीफा उसी का षड्यंत्र है। उन्हें सत्ता की भूख है इसलिए वह इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इस सबके पीछे अमित शाह हैं। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हैं।

पिछले एक साल के दौरान वह प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। अब वह फिर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। वह जद-एस नेता और उच्च शिक्षा मंत्री जीटी देवेगौड़ा के उस बयान के बारे में बयान दे रहे थे, जिसमें उन्होंने विधायकों के इस्तीफे के मामले में मोदी और शाह को क्लीन चिट दी थी। खास बात यह है कि जद-एस मंत्री ने ऐसा बयान तब दिया है जब मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार को अस्थिर करने का दिवास्वप्न देख रही है।

येद्दयुरप्पा बोले, हमारे विधायक एकजुट

कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा ने कहा कि वह भाजपा पर आरोप लगाकर पार्टी में मतभेदों की बात छिपा रहे हैं। कई कांग्रेस नेताओं द्वारा इसी तरह का अभियान भाजपा के खिलाफ चलाने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह बात वह पिछले तीन महीनों से कह रहे हैं। हमारे सभी 105 विधायक एकजुट हैं।

छह करोड़ में आज बिकेगा डॉ. जोशी का बंगला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बंगला। जागरण

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी का प्रयागराज स्थित टैगोर टाउन का बंगला 'अंगिरस' लगभग छह करोड़ में बिकेगा। पांच लोग इसे खरीदेंगे। मंगलवार को रजिस्ट्री प्रक्रिया नहीं हो सकी। अब यह बुधवार को पूरी की जाएगी। बंगले के सौदे के लिए डॉ. जोशी पत्नी के साथ चार दिन के प्रयागराज प्रवास पर हैं। बेटी प्रियंवदा भी मंगलवार को प्रयागराज आ गईं। बताते हैं कि तकरीबन छह करोड़ रुपये में कुल सौदा हुआ है। लगभग 1200 वर्ग गज क्षेत्रफल में 1000 वर्ग गज का बंगला है। इसे डॉ. जोशी के पड़ोसी हृदय रोग विशेषज्ञ डा. आनंद मिश्र तथा उनके भाई अनुपम मिश्र खरीदेंगे। अनुपम दिल्ली स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में महाप्रबंधक हैं। शेष सौ वर्ग गज जमीन विद्युत विभाग के अधिकारी धरनीधर द्विवेदी खरीदेंगे। शिक्षिका संध्या कुशवाहा और प्रियंका कुशवाहा 50-50 वर्ग गज जमीन खरीदेंगी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया डॉ. जोशी के बंगले पर ही होगी।

दिल्ली ट्रांसफर कराए बैंक एकाउंट : भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी का प्रयागराज से नाता अब लगभग टूट ही जाएगा। उन्होंने तीनों बैंक एकाउंट का भी दिल्ली ट्रांसफर करा लिया है। उनका एक खाता भारतीय स्टेट बैंक की विश्वविद्यालय शाखा में था जहां उन्हें पेंशन मिलती थी। एक खाता भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में था। इसमें जन कल्याण समिति नामक उनकी संस्था का भी खाता था। मंगलवार को डॉ. जोशी बैंक में खुद गए और खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की। स्टेटमेंट भी लिया।

भुगतान नहीं करने पर चीनी मिल मालिकों को जेल भेज सकती हैं राज्य सरकारें

नई दिल्ली, प्रेट्र : गन्ना किसानों को बकाया देने में अगर चीन मिल मालिक विफल रहते हैं तो केंद्र ने राज्य सरकारों को उन्हें सलाखों के पीछे डालने की शक्तियां प्रदान की हैं। लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 2017-18 में किसानों का बकाया 85,179 करोड़ रुपये था और यह गन्ने के सीजन के अंत तक घटकर 303 करोड़ रुपये पर आ गया।

मौजूदा सीजन में 85,355 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसमें से 67,706 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि साल के अंत तक अधिकांश भुगतान किसानों को कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकारों के पास मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने की शक्तियां हैं।

टकराव

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर नहीं चाहते कि अकाली दल ले जाए श्रेय, प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे शिरकत, 12 नवंबर को होना है समारोह

प्रकाशोत्सव पर छिड़ी श्रेय लेने की लड़ाई, कौन संभालेगा स्टेज

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को लेकर कैप्टन सरकार और शिरोमणि अकाली दल के बीच श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल, यह लड़ाई 12 नवंबर को सुल्तानपुर लोधी में मनाए जाने वाले मुख्य समारोहों की स्टेज को संभालने को लेकर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से इन समारोहों को लेकर सक्रिय हैं, उसे देखकर लगता है कि इतने बड़े समारोह का क्रेडिट वह अकाली दल को नहीं लेने देना चाहते।

सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला) में इन दिनों जितनी तेजी से विकास कार्य हो रहा है, उससे मुख्यमंत्री की सक्रियता साफ दिखाई पड़ रही है। उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार लगातार विकास कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। तीन दिन पहले सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पर्यटन मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रधान जत्थेदार गोबिंद सिंह लोंगोवाल से मुलाकात की और कहा कि ये समारोह मिलकर मनाने चाहिए। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में लोंगोवाल ने कहा कि सरकार सारे बाहरी प्रबंध देख ले। चूंकि समारोह पूरी तरह से धार्मिक है, इसलिए स्टेज की जिम्मेदारी एसजीपीसी संभालेगी। एसजीपीसी के जरिए अकाली दल भी पंथ में अपनी गिर रही साख को फिर से बहाल करना चाहता है। इसी कारण दल के प्रधान सुखबीर बादल, एसजीपीसी प्रधान लोंगोवाल, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा और पटना साहिब बोर्ड के प्रधान अवतार सिंह हित की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। उनसे इन समारोहों में शिरकत करने का आग्रह किया, जिसे प्रधानमंत्री ने मान लिया है। साफ है कि अगर प्रधानमंत्री समारोह में आते हैं तो एनडीए का घटक होने के कारण अकाली दल भी अपना दबदबा बनाए रखेगा। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे?

सीएमओ के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इन समारोहों को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मिलेंगे। दो मंत्रियों पर आधारित जिस कमेटी ने तीन दिन पहले तख्त साहिब के जत्थेदार और एसजीपीसी के प्रधान से मीटिंग की थी, अभी उसकी रिपोर्ट सीएम को दी जानी है। मुख्यमंत्री की ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मिलने की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है।

पाकिस्तान भी इसी दिन खोलेगा कॉरिडोर : पाकिस्तान भी भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुरुपर्व वाले दिन ही करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा। दोनों ओर से कॉरिडोर को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में अक्टूबर तक इसके पूरा होने की संभावना है।

करतारपुर कॉरिडोर पर भारत-पाक के बीच दूसरी बैठक 14 जुलाई को

- भारत ने ही सुझाई थीं 11 से 14 जुलाई की तारीखें

इस्लामाबाद, प्रेट्र : भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने संबंधी मसौदा समझौते और उससे जुड़े तकनीकी मसलों पर चर्चा के लिए दूसरी बैठक करने का फैसला किया है। यह बैठक 14 जुलाई को बाघा में होगी। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि भारतीय पक्ष से इस वार्ता के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल का ब्योरा देने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि नवंबर, 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती तक कॉरिडोर को शुरू किया जा सके। बयान के मुताबिक भारत ने ही वार्ता के लिए 11-14 जुलाई की तारीखें प्रस्तावित की थीं। नई दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित तारीख को स्वीकार कर लिया है। इस मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच पहली बैठक पुलवामा आतंकी हमले के बाद मार्च में अटारी में हुई थी। मालूम हो कि यह कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर के जरिये सिख श्रद्धालु बिना वीजा वहां आ-जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ परमिट लेना होगा।

सांसद एसटी हसन और आजम पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, रामपुर : पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी के आरोप में रामपुर सांसद आजम खां और मुरादाबाद सांसद डॉ. एसटी हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कई अन्य सपा नेताओं को भी नामजद किया गया है। आजम पर 24 घंटे में यह दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा जयाप्रदा के करीबी व पूर्व मंत्री हाजी निसार हुसैन के बेटे मुस्तफा हुसैन ने कराया है।

सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 30 जून को मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में रामपुर के सांसद आजम, उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला, मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन, रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां, सम्भल के सपा जिलाध्यक्ष फिरोज आदि शामिल हुए थे। इसमें पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक, अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। मुरादाबाद के सांसद ने भी पूर्व सांसद के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दोनों के भाषण का वीडियो वायरल हो गया।

2000 की जाएंगी एमबीबीएस की सीटें हरियाणा में अगले साल से। पंचकूला में डॉक्टर्स-डे पर स्टेट लेवल प्रोग्राम में यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। वर्तमान में राज्य में एमबीबीएस की 1710 सीटें हैं।

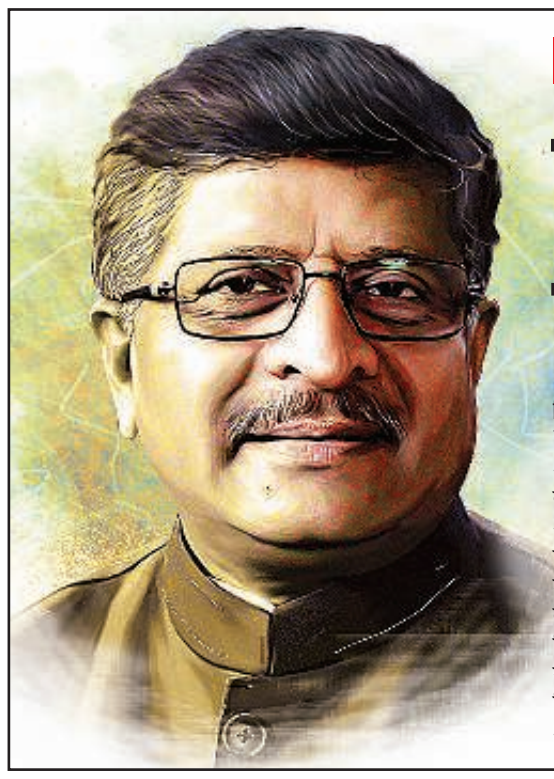

हमारी सरकार रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय विधि व न्याय, संचार तथा इलेक्टॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

जीवन के मूल मानकों से समझौता नहीं

नितिन प्रधान ● नई दिल्ली

अनुशासन, बेबाकी और निडरता केंद्रीय कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व के तीन ऐसे पहलू हैं, जिसने उनका बचपन भले ही छोटा कर दिया हो, लेकिन उसमें संघर्ष की ऐसी क्षमता भरी जिसने उन्हें जिंदगी में मजबूत बनाया। सुविधा संपन्न होने के बावजूद तीन किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने की आदत ने जीवन में संघर्ष करने की क्षमता विकसित की। यही संघर्ष आगे चलकर राजनीति में अपने बूते नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। व्यक्तित्व में चारित्रिक दृढ़ता आई, जिसने राजनीतिक जीवन के तमाम झंझावातों का सामना करने की शक्ति दी।

भाजपा में ऐसे नेताओं की भरमार है, जिन्होंने संघ से अनुशासन सीखा। रविशंकर ने तभी से शाखा जाना शुरू कर दिया था, जब वह बालक थे- यानी बाल स्वयंसेवक। घर में पिता का अनुशासन और बाहर संघ की नजर। बचपन से ही मन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का था। लेकिन पिता ने एक बार मना किया तो अनुशासन के इतने पक्के कि उसके बाद कोई बहस नहीं। पटना के कदमकुआं स्थित स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत हुई। बचपन में अनुशासन का जो मंत्र सीखा वो अभी तक उनके जीवन का हिस्सा है। हालांकि बचपन में होली से पहले ही होली खेलने की शरारत के चलते एक बार उन्हें पिता की मार का स्वाद चखने का भी मौका लगा। चाहे छात्र राजनीति रही हो या फिर जेपी का आंदोलन, अनुशासन का यह भाव उन्हें हर बार आगे बढ़ाने में काम आया। जेपी उनके आदर्श रहे हैं और उनके सानिध्य में उन्होंने अनुशासन का पाठ भी कड़ाई से पढ़ा। आंदोलन के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब युवा मन ने उत्साहित होकर गर्मी दिखा दी। लेकिन जेपी की डांट ने युवा मन के उस उत्साह को दिशा दी और मन को अनुशासन में बांधना सीखा।

यह वो दिन थे जब प्रसाद ने बिहार में छात्र राजनीति में प्रवेश किया ही था। इंटर पास करके कॉलेज में प्रवेश करने के साथ ही उन्हें छात्र राजनीति में सुशील कुमार मोदी और लालू प्रसाद यादव का साथ मिला। इन दोनों नेताओं का साथ जेपी आंदोलन में भी मिला। जेपी के अलावा अटल और आडवाणी से भी उनके राजनीतिक जीवन को दिशा मिली। यही वजह है कि प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले इन दोनों नेताओं को भी अपना रोल मॉडल मानते हैं। यही नहीं लाल बहादुर शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व पर पड़ा है। बचपन से युवा और उसके बाद राजनीतिक करियर को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में सीखे गीतों का असर भी उनके चरित्र पर खासा पड़ा। इन गीतों को प्रसाद आज भी उतने की उत्साह से गाते हैं।

रविशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व में बेबाकी एक बड़ी विशेषता है। उनके चरित्र की यह खासियत बचपन से ही रही है। 1972 में जब जेल जाने की नौबत आई तो पिता ने पूछा, 'क्या इरादा है? पढ़ाई नहीं करनी क्या।' बेबाक इतने कि पिता को जवाब दिया 'फर्स्ट क्लास दूंगा। रेस्ट इज नन ऑफ योर कंसर्न।' जेल गए लेकिन वापस आने के बाद इम्तिहान दिए और पिता को दिया वचन भी निभाया। सक्रिय जीवन के साथ-साथ प्रसाद ने पढ़ाई को भी उतना ही महत्व दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि परीक्षा से तीन महीने पहले कड़ी मेहनत और एक दिन में 18 घंटे की पढ़ाई ने उन्हें शैक्षणिक योग्यता में कभी पीछे नहीं रहने दिया।

युवा मन के जुनून ने प्रसाद को बेबाक तो बनाया ही, सामाजिक मूल्यों का निर्वाह करने में भी कभी पीछे नहीं रहे। विद्यार्थी परिषद के दिनों में अपने एक दलित मित्र को घर लाए, भोजन कराया। इस पर पिता की बहन यानी बुआ ने एतराज जताया। लेकिन प्रसाद पीछे नहीं हटे। जीवन के मूल मानकों से समझौता न करने की इसी प्रवृत्ति ने उनके राजनीतिक जीवन को भी दृढ़ता प्रदान की। उनकी इसी सोच ने उन्हें बेबाक के साथ-साथ निडर भी बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद प्रसाद के मन में कोयले की तस्करी रोकने का जुनून इस हद तक सवार हुआ कि वो धनबाद में कोयला खदान से ट्रकों पर होने वाली लदाई का मुआयना करने जा पहुंचे और ट्रक पर चढ़ गए। कोयला खदानों पर ट्रकों में तय सीमा से अधिक कोयला लोड कर उसे चोरी कर लिया जाता था।

बेबाकी, निडरता और अनुशासन में बंधे प्रसाद एक गंभीर अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी हैं। रामजन्मभूमि का मुकदमा लड़ने वाले प्रसाद ने भारत की सनातन परंपरा का भी विस्तार से अध्ययन किया है। भारत को वह एक व्यापक रूप में देखते हैं। यह दृष्टि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ-साथ विवेकानंद से लेकर महर्षि अरविंद के अध्ययन से मिली।

हिमाचल प्रदेश में दागी अधिकारियों को किया जाएगा जबरन सेवानिवृत्त

सख्ती ▶ ओडीआइ की सूची में शामिल अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

कुछ अधिकारी सूची से बाहर हुए, तो कई की जांच है लंबित

रमेश सिंगटा, शिमला

हिमाचल सरकार संदिग्ध आचरण वाले अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने की तैयारी में है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी (ओडीआइ) सूची में शामिल दागियों को बख्शने के मूड में नहीं है। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में कड़ा फैसला लेकर कई अधिकारियों को घर बैठाया जाएगा।

हिमाचल में अफसरशाही पर 66 दाग लगे हैं। हालांकि, विभागीय जांच के बाद कुछ अधिकारी ओडीआइ सूची से बाहर हो गए हैं और कुछ को जांच में क्लीनचिट मिल गई है, लेकिन डिसिप्लेनरी अथॉरिटी के पास ये मामले लंबित हैं। विभागीय जांच में कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के पास 16 मामले लंबित हैं। वहां से न तो आरोपितों के पक्ष में और न ही विरुद्ध कोई फैसला आया है। ऐसा हाल तब है जब राज्य के हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए समयसीमा तय कर रखी है।

कोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट : जिन अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस और पुलिस केस चल रहे हैं, उनकी कोर्ट ने सरकार से अलग से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि कितने मामलों में विजिलेंस व पुलिस केस लंबित हैं। क्या इन केसों के आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं? किस कोर्ट में कितने केस लंबित है। इनके संबंध में स्पीडी ट्रायल के निर्देश दिए जा सकते हैं।

27 को होगी सुनवाई

प्रदेश हाई कोर्ट में ओडीआइ सूची वाले अधिकारियों के मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से उन सभी अधिकारियों की सूची तलब की थी, जिनके खिलाफ उनकी दागी छवि के कारण एक जनवरी 2010 के बाद या तो आपराधिक मामले दायर किए गए या उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है।

27 जुलाई को शिमला हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई। फाइल

संवेदनशील पदों पर नहीं होगी तैनाती

दागी अधिकारियों को सरकार संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं करेगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि आरोपित अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मौका न मिल पाए। उनकी ऐसी जगह तैनाती होगी जिससे वे गवाहों को प्रभावित न कर पाएं।

28 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच

ओडीआइ सूची के मुताबिक, 28 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। वहीं, 16 अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों के समक्ष या तो आपराधिक मामले लंबित हैं या उन्हें सजा होने के कारण बड़ी अदालतों में अपीलें लंबित हैं।

उत्तराखंड में भी लटकी भ्रष्ट अफसरों पर तलवार

विकास धूलिया, देहरादून : उत्तराखंड में भ्रष्ट और नकारा अफसरों पर जबरन सेवानिवृत्ति की तलवार लटक गई है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी ऐसे अफसरों को समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने जैसा सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में इस सूची में 50 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकारियों को शामिल करने को कहा गया है। शासन के बाद विभिन्न महकमों में भी ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा।

सत्ता संभालने के पहले दिन से ही हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का पालन किया है। तमाम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में की गई कार्रवाई इसका प्रमाण है। अब उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भ्रष्ट और नकारा अधिकारियों व कर्मचारियों पर नकेल डाली जाएगी। मैंने मुख्य सचिव को ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।-त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

क्या केरल कानून से ऊपर है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने चर्चों के प्रशासन और प्रार्थनाओं के संचालन के अधिकार पर दो गुटों के बीच विवाद पर 2017 में एक फैसला दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसले को लागू नहीं करने पर केरल सरकार की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने कहा, 'क्या केरल कानून से ऊपर है?' शीर्ष अदालत ने उसके फैसले को लागू नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को सलाखों के पीछे डालने की चेतावनी भी दी।

बता दें कि ऑर्थोडॉक्स समूह के मलांकारा चर्च के तहत 1100 'पेरिश' और उनके गिरिजाघरों का नियंत्रण देने पर शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने से संबंधित एक मामले की जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की पीठ सुनवाई कर रही थी। पीठ ने चेतावनी दी कि वे केरल के मुख्य सचिव को 'न्याय प्रणाली का मजाक बनाने' के लिए तलब करेंगे। पीठ ने राज्य की ओर से पेश वकील से कहा, 'अपने मुख्य सचिव से कहें कि अगर वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने का इरादा रखते हैं, तो हम यहां सभी को बुलाएंगे। क्या केरल कानून से ऊपर है? आप न्याय प्रणाली का मजाक बना रहे हैं।'

राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए पीठ ने कहा, 'आप मामले की गंभीरता को नहीं समझते हैं। हमने आप लोगों को इतना बर्दाश्त किया है। आपके खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है। देश में क्या हो रहा है? यदि उन्हें लगता है कि वे इस तरह की चीजें कर सकते हैं, तो हम सभी को यहां बुलाएंगे। शीर्ष अदालत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता है।' न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को उसके आदेशों को लागू करना होगा। शीर्ष अदालत ने 2017 में दिए गए अपने फैसले में कहा था कि 1934 के मलांकारा गिरिजाघर के दिशानिर्देशों के अनुसार मलांकारा गिरजाघर के तहत 1,100 'पेरिश' और उनके गिरिजाघरों को ऑर्थोडॉक्स गुट द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर रेलवे में वंदे भारत राजधानी और शताब्दी ट्रेनें चलाने की तैयारी

- गोरखपुर के रास्ते बाराबंकी से छपरा तक बढ़ाई जाएगी ट्रैक की क्षमता
- 110 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

वंदे भारत ट्रेन का फाइल फोटो।

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे के रूटों पर भी वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी ट्रेनें चलाने की तैयारी है। अधिकतम 110 से 130 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने वालीं इन ट्रेनों के लिए बाराबंकी से छपरा (425 किमी) तक रेल लाइन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी पूरी होते ही इन ट्रेनों के संचालन को मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है।

तैयारी के क्रम में रेल लाइन और स्लीपर बदले जाएंगे। लाइनों के बीच के गैप समाप्त किए जाएंगे। लूप लाइनों को जोड़ने वाले प्वाइंट पर मजबूत थिक वेब स्विच लगाए जाएंगे। रफ्तार बढ़ाने और उसे नियंत्रित करने के लिए डिस्टेंट सिग्नल से पहले डबल डिस्टेंट सिग्नल लगाए जाएंगे। इससे अन्य ट्रेनों की भी रफ्तार 19 फीसद बढ़ जाएगी। दो वर्ष पहले गोरखपुर रूट पर रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद भी समग्र तैयारी के अभाव में राजधानी नहीं चल पाई थी।

60 किलो वजन की रेल लाइन

बाराबंकी से छपरा तक 52 किग्रा वजन की जगह 60 किग्रा की रेल लाइन लगाई जाएगी। एक मीटर रेल लाइन का वजन 60 किलोग्राम होगा। इससे पटरी की वजन सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। फ्रैक्चर की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। नीचे पत्थर कम होने पर भी रेल लाइन का आकार नहीं बदलेगा।

ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी

एनई रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी और इलाहाबाद के बीच 80 किमी रूट पर वंदे भारत ट्रेन 110 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने लगी है। अन्य रेल मार्गों पर भी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे में भी इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।

कोलकाता के पूर्व सीपी राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर 22 तक रोक

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक की समयसीमा 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब इस मामले में कोर्ट 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 22 जुलाई तक सीबीआइ चिटफंड मामले में कथित तौर पर साक्ष्यों को मिटाने के मामले में पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।

सारधा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार पर सुबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। इससे पहले सीबीआइ ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उसके सामने पेश होने को कहा था। नोटिस के बावजूद राजीव कुमार पेश नहीं हुए। उन्होंने सीबीआइ को पत्र भेजकर पेश होने के लिए और समय मांगा था। पत्र में कहा गया था कि वह निजी काम से उत्तर प्रदेश में अपने घर गए हैं और फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं। इसलिए पेश नहीं हो सकते।

तमिलनाडु में उड़ान के दौरान तेजस का फ्यूल टैंक खेत में गिरा

- हादसे में कोई हताहत नहीं, लड़ाकू विमान ने वायुसेना के सुलुर स्टेशन पर की सुरक्षित लैंडिंग

कोयंबटूर, प्रेट्र/एएनआइ : स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का फ्यूल टैंक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मंगलवार की सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर के बाहर एक खेत में अचानक गिर गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे की जांच की जा रही है।

पुलिस ने कहा कि 1200 लीटर का फ्यूल टैंक आसमान से गिरता देख खेत में काम कर रहे मजदूर हतप्रभ रह गए। टैंक गिरने से खेत में तीन फीट गहरा गड्ढा हो गया और मामूली आग भी लग गई। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वायुसेना ने एक बयान में कहा, 'मंगलवार की सुबह करीब 8:40 बजे कोयंबटूर के करीब सुलुर एयरबेस से सामान्य प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरने के बाद तेजस का एक फ्यूल टैंक गिर गया। हालांकि, इस हादसे के बाद विमान ने एयरबेस पर वापस सुरक्षित लैंडिंग कर ली। किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की सूचना नहीं है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।'

2016 को वायुसेना के स्क्वाड्रन में किया गया था शामिल

तेजस सुपरसोनिक, एक सीट और एक इंजन वाला बहुद्देश्यीय हल्का लड़ाकू विमान है। इसे वर्ष 1983 में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने विकसित किया था। एक जुलाई, 2016 को इसे भारतीय वायुसेना के 45 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया और मिग-21 का विकल्प बना। तेजस के वायुसेना में शामिल होने के बाद शायद यह पहला हादसा है। पिछले सप्ताह अंबाला एयरबेस से एक जगुआर के उड़ान भरने के बाद उससे पक्षी टकरा गया था। इससे उसके इंजन में आग लग गई थी और फ्यूल टैंक तथा प्रशिक्षण बमों को गिराना पड़ा था।

कुएं में गिरे तेंदुए को चारपाई से निकाला

नईदुनिया, कांकेर

भोजन की तलाश में पहुंचा एक तेंदुआ सोमवार की रात कांकेर के नरहरपुर क्षेत्र के ग्राम झलियामारी के एक कुएं में गिर गया। पांच घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग के कर्मचारी उसे निकालने में सफल हो पाए। खास बात यह रही कि इसके लिए चारपाई की मदद ली गई।

मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर के ग्राम झलियामारी का है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह लोगों ने कुएं में गिरे तेंदुए को देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी। सुबह आठ बजे वन विभाग के कर्मी पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंच गया। चूंकि तेंदुआ पूर्ण वयस्क था, इसलिए रेस्क्यू के दौरान पूरी सतर्कता बरती गई। पहले कुएं में सीढ़ी डाली गई। इससे तेंदुआ सीढ़ी को पकड़कर तैरने लगा।

इस तरह निकाला गया : वन विभाग के कर्मचारी उसके ऊपर चढ़ने का इंतजार करने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद भी तेंदुआ ऊपर नहीं आया। काफी इंतजार के बाद भी तेंदुए के न निकलने पर रस्सी के सहारे चारपाई कुएं में डाली गई। जैसे ही तेंदुआ चारपाई पर बैठा, काफी दूर सुरक्षित स्थानों पर खड़े लोग रस्सी खींचने लगे। ऊपर आते ही तेंदुआ चारपाई से छलांग मारकर बाहर जमीन पर कूदा और जंगल की ओर भाग निकला।

छत्तीसगढ़ के कांकेर के एक गांव में कुएं में गिरे तेंदुए को चारपाई डालकर बाहर निकाला गया। जागरण

बिहार का हलफनामा स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत बयां करता है

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुए चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत 12,206 पदों के लिए सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं। शीर्ष कोर्ट में दिए गए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत क्षमता 19,155 के मुकाबले सिर्फ 5,634 नर्सें ही तैनात हैं। कोर्ट ने 24 जून को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और साफ-सफाई को लेकर एक हफ्ते में मौजूदा स्थिति से उसे अवगत कराए। बीमारी के संदर्भ में राज्य सरकार ने कहा कि कुल 824 मामले सामने आए हैं और कुल 157 मौत हुई हैं। इसमें हालांकि कहा गया कि यह नहीं पता कि इंसेफलाइटिस से हुई मौत के 215 मामलों में से 24 इस बीमारी से हुई हैं या नहीं। बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य में डॉक्टरों और नर्सों के क्रमशः 57 और 71 फीसद पद खाली हैं।

प्रयास

चमोली में पहली बार घाटी के पर्यटकों के लिए खुलते ही शुरू हुआ खरपतवारों को हटाने का अभियान, घाटी की जैवविविधता के लिए अभिशाप बन चुके हैं पॉलीगोनम और ब्राउन फर्न के पौधे

फूलों की घाटी में 15 हेक्टेयर क्षेत्र पॉलीगोनम से मुक्त

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

ऐसा पहली बार हो रहा है, जब विश्व धरोहर फूलों की घाटी की जैवविविधता के लिए अभिशाप बन चुके पॉलीगोनम व ब्राउन फर्न के पौधों को प्राइमरी स्टेज में ही हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मजदूर लगाए गए हैं और पहले चरण में 15 हेक्टेयर क्षेत्र को पॉलीगोनम के पौधों से मुक्त किया जा चुका है। विदित हो कि खरपतवार प्रजाति के ये दोनों ही फूल घाटी में रक्तबीज की तरह फैल रहे हैं और बीते एक दशक में 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कब्जा जमा चुके हैं।

उत्तराखंड के चमोली जिले में 87.5 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली फूलों की घाटी में पॉलीगोनम व ब्राउन फर्न के फूल सैकड़ों प्रजाति के दुर्लभ फूलों का अस्तित्व संकट में डाल रहे हैं। बीते एक दशक में घाटी के 65 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पॉलीगोनम और 35 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ब्राउन फर्न फैल चुका है। इसके चलते इन खरपतवारों के पौधों के नीचे दुर्लभ प्रजाति के फूल व जड़ी-बूटियों के पौधे नहीं पनप पा रहे। बीते वर्षों में वन विभाग इन दोनों पौधों को हटाता तो रहा था, लेकिन तब, जब इन पर फूल खिल जा रहे थे। फूल खिलने बाद के बीज झड़ने पर इनके पौधों का तेजी से विस्तार होता है। इसी को देखते हुए वन विभाग ने इस बार इनके उगते ही इन्हें हटाने की योजना पर कार्य शुरू किया, ताकि इनके प्रसार को रोका जा सके।

फूलों की घाटी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन भारती बताते हैं कि घाटी में पॉलीगोनम व ब्राउन फर्न का प्रसार गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। वर्तमान में यहां पॉलीगोनम की चार प्रजातियां पनप चुकी हैं। इन खरपतवार के पौधों की लंबाई ज्यादा होने के कारण इनके नीचे छोटी प्रजाति के फूलों के पौधे नहीं पनप पाते। इसलिए इस बार प्राइमरी स्टेज में ही इनके उन्मूलन का कार्य शुरू कर दिया गया।

भेड़-बकरियों के चुगान पर रोक बनी अभिशाप : राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग में वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. विश्वपति भट्ट कहते हैं कि घाटी में खरपतवारों के पनपने की मुख्य वजह वहां भेड़-बकरियों के चरान-चुगान पर रोक लगाया जाना है। पहले घाटी में भेड़-बकरी चुगान प्रतिबंधित नहीं था। पसंदीदा आहार होने के कारण भेड़-बकरियां पॉलीगोनम को चट कर जाते थे। इससे फूलों के पौधों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता था, लेकिन छह नवंबर, 1982 को फूलों की घाटी को नंदा देवी बायोस्फियर का हिस्सा घोषित कर दिया गया। साथ ही यहां भेड़-बकरियों के चुगान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे घाटी में पॉलीगोनम का तेजी से फैलता चला गया। डॉ. भट्ट के अनुसार घाटी में खरपतवारों के उन्मूलन के लिए वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया जाता। अकुशल मजदूर पॉलीगोनम व ब्राउन फर्न को हटाने का काम करते हैं, जिससे दुर्लभ प्रजाति के फूलों को भी नुकसान पहुंचता है।

चमोली स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी में फैली पॉलीगोनम साफ करता श्रमिक। जागरण

ऐसी घाटी, जहां खिलते हैं 500 से अधिक प्रजाति के फूल

विश्व धरोहर फूलों की घाटी अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया की यह इकलौती जगह है, जहां प्राकृतिक रूप में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। इसके अलावा कई दुर्लभ प्रजाति की जड़ी-बूटियां भी यहां पाई जाती हैं।

मरीज से भावनात्मक रूप से जुड़े व्यक्ति को किडनी दान की अनुमति

- बिहार विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, पटना

किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अब बिहार के तीन बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। किडनी के मरीज को भावनात्मक रूप से जुड़ा व्यक्ति किडनी दान कर सकता है।

सरकार ने आइजीआइएमएस (इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान) पटना, पारस हॉस्पिटल पटना और रूबन हॉस्पिटल पटना को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस मंजूर कर लिया है। यह जानकारी मंगलवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में दी। यह लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है।

इनका हो सकता है भावनात्मक जुड़ाव : किसी मरीज को किडनी देने के लिए उसका रक्त संबंधी होना जरूरी नहीं है। कोई आदमी किसी से भावनात्मक तौर से जुड़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार के इसी प्रावधान के चलते दूसरे राज्य के मरीज वहां ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाते हैं। यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से राज्य के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार देगी ट्रांसप्लांट का खर्च

सालाना 2.50 लाख रुपये से कम आय वालों को सरकार किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च देगी। फिलहाल तीन से चार लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। दवाओं का खर्च भी सरकार वहन करेगी।

दो लाख में हो सकेगा ट्रांसप्लांट

आइजीआइएमएस में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को दो लाख रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। प्रदेश का यह पहला अस्पताल है, जहां यह सुविधा उपलब्ध है। यह ऐसी सर्जरी है, जिसमें क्रोनिक किडनी फेल्योर के मरीज को एक स्वस्थ किडनी लगा दी जाती है। इससे मरीज को डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं होती है।

45 सदस्यीय दूसरा दल कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा पूरी कर भारत लौट आया है। दल मंगलवार शाम को पिथौरागढ़ के गुंजी पहुंचा। तीसरा दल कैलास की परिक्रमा कर रहा है जबकि चौथा दल तिब्बत में प्रवेश कर तकलाकोट पहुंचा है।

न्यूज गैलरी

बदरी-केदार में पूजा-आरती की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

चमोली : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा, पाठ भोग और आरती सहित डोनेशन की बुकिंग अब ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। समिति ने पहली बार यह प्रक्रिया ऑनलाइन की है। इसका लाभ देश ही नहीं विदेशों से बदरी-केदार धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने बताया कि अभी तक भू-बैकुंठ बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा-पाठ, भोग और आरती समेत डोनेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन थी। लेकिन, अब समिति ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही जल्द मंदिर समिति की धर्मशाला और आवासों की भी ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जाएगी। (जासं)

सज्जाद गुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी

श्रीनगर : जम्मू- कश्मीर पुलिस ने पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के साजिशकर्ता लश्कर आतंकी सज्जाद गुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए मंगलवार को सीबीआइ से संपर्क किया। सज्जाद गुल 2017 से पाकिस्तान में छिपा बैठा है। भारत में सीबीआइ ही इंटरपोल के लिए एक नोडल संस्था है। सीबीआइ के जरिए ही किसी के खिलाफ विश्वव्यापी अलर्ट के लिए इंटरपोल को आग्रह भेजा जाता है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भेजे गए दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए हैं। ऐसे में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें इंटरपोल के मुख्यालय भेज दिया जाएगा। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की 14 जून 2017 को आतंकियों ने लालचौक के साथ सटे प्रेस एनक्लेव में उनके कार्यालय के नीचे हत्या कर दी थी। उनकी हत्या में लश्कर आतंकी नवीद जट्ट, मुजफ्फर और आजाद अहमद मलिक शामिल थे। यह तीनों आतंकी बाद में सुरक्षाबलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए थे। (राब्यू)

पुलिस को उड़ाने की साजिश नाकाम, तीन केन बम बरामद

सगालीम (पलामू) : पुलिस को उड़ाने की उग्रवादियों की मंशा पर पलामू पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस ने जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के जमुनियाडीह नाला से तीन और आइईडी बम बरामद किए हैं। अब तक पुलिस यहां से पांच आइईडी बम बरामद कर चुकी है। मालूम हो कि रविवार को इसी स्थान से दो आइईडी बम मिले थे। सभी पांचों आइईडी बम सड़क किनारे एक नाले में लगाए गए थे। सभी आइईडी बम पांच-पांच किलो के थे। बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को नष्ट कर दिया। (जासं)

पश्चिम बंगाल से जेएमबी इंडिया का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

सफलता ▶ 2013 में बोधगया में हुए विस्फोट कांड के बाद से फरार था अब्दुल रहीम

25 जून को भी गिरफ्तार किए गए थे चार आतंकी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता पुलिस ने पूर्व बर्धमान से जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) इंडिया के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। वह 2013 में हुए बोधगया विस्फोट कांड के बाद से फरार था। सूत्रों के अनुसार मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने गत सोमवार रात पूर्व बर्धमान के एक बस स्टैंड की घेराबंदी कर अब्दुल रहीम नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के अनुसार रहीम जेएमबी इंडिया का सक्रिय सदस्य है। वह मुर्शिदाबाद के धुलियान मॉड्यूल का मुखिया भी है। दावा है कि उक्त मॉड्यूल ने ही बोधगया विस्फोट को अंजाम दिया था। विस्फोट के बाद से ही रहीम फरार चल रहा था। रहीम, जेएमबी आंतकी अब्दुल वहाब और मौलाना युसूफ का बेहद करीबी था। एसटीएफ उक्त दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि रहीम मुर्शिदाबाद के पिछड़े इलाकों में रहने वाले युवकों को दावत पर बुलाता था। इसके बाद जिहाद के नाम पर गुमराह कर उनको आतंक के रास्ते पर उतार देता था।

बता दें कि बोधगया विस्फोट के बाद एसटीएफ को पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन जेएमबी के सक्रिय होने की भनक लगी थी, लेकिन बाद में पता चला कि जेएमबी नहीं बल्कि भारत में जेएमबी इंडिया के नाम से मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इसके बाद भारत सरकार ने जेएमबी इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्रीय एजेंसियों ने भी भारत में जेएमबी के सहारे इस्लामिक स्टेट (आइएस) के पैर पसारने की जानकारी दी थी। बताया गया था कि दक्षिण भारत समेत पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा आइएस के निशाने पर है। इसके बाद ही एसटीएफ ने गत 25 जून को हावड़ा और सियालदह स्टेशन परिसर से चार जेएमबी इंडिया के आतंकियों को गिरफ्तार कर किया था।

युवकों को गुमराह करने के लिए मदरसों का इस्तेमाल कर रहा जेएमबी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- मुर्शिदाबाद, वर्धमान, नदिया, मालदा के मदरसों पर नजर
- भारत-बांग्लादेश की सीमा के पास हैं कई आतंकी शिविर

आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) संगठन में नई भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बर्धमान के मदरसों का प्रयोग कर रहा है। मदसरों के जरिए ही युवक युवतियों को जिहाद के लिए गुमराह किया जा रहा है। इस तरह की चेतावनी गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार जेएमबी द्वारा भारत-बांग्लादेशी सीमा के पास कई आतंकी शिविर चलाए जा रहे हैं। उक्त शिविरों में लश्कर ए तैयबा के खूंखार आतंकियों का भी जाना जाना लगा रहता है। उक्त इलाकों से संगठन में नई भर्ती भी की जाती है। इसके लिए वहां के मदरसों और मस्जिदों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जेएमबी की खासकर नदिया, मुर्शिदाबाद, बर्धमान और मालदा जिले के मदरसों पर नजर है। इसके अलावा असम के मुस्लिम बहुल जिलों में भी एक ही तरीके से जिहाद के नाम पर युवकों को गुमराह कर संगठन में जोड़ा जा रहा है।

आतंकी संगठनों में खूनी संघर्ष की आशंका से घबराया सलाहुद्दीन

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- आइएसजेके ने अपने कमांडर की हत्या का बदला लेने की दी है धमकी
- पिछले हफ्ते हिज्ब और लश्कर के आतंकियों ने कर दी थी उसकी हत्या
- सलाहुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा गलतफहमी में हुई हत्या

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के बिजबेहाड़ा में आतंकी कमांडर आदिल दास की हिजबुल के आतंकियों द्वारा हत्या ने पूरे कश्मीर का माहौल बदल दिया है। आदिल का शव सेब के बागों में मिला था। वहीं, उसका साथी जख्मी हालत में मिला था। ऐसे में स्थानीय लोगों को आतंकी संगठनों में फिर से खूनी संघर्ष की आशंका सता रही है। वहीं, अपना कैडर खिसकने के डर से हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सलाहुद्दीन ने एक तरह से माफी मांगते हुए हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं, घायल मिले आदिल ने कबूलनामे में आतंकी बनने पर दुख जताया था। उसने कहा था कि काश वह वर्दी पहनकर बंदूक उठाता। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां भी बदलते घटनाक्रम पर अलर्ट हैं।

इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर (आइएसजेके) के कमांडर आदिल की 26 जून को हिज्ब और लश्कर के आतंकियों ने धोखे से हत्या कर दी थी। उस समय इन संगठनों ने फैलाने का प्रयास किया कि आदिल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। वहां जख्मी मिले आतंकी ने भी हिज्ब व लश्कर के झूठ की पोल खोल दी।

इसके बाद आइएसजेके के कमांडर ने वीडियो जारी कर लश्कर और हिज्ब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके साथ ही लश्कर और हिज्ब पर पाकिस्तान परस्त नीतियों के कारण हत्या का आरोप लगाया था। वीडियो में चेताया गया था कि इन लोगों ने 30 सालों तक कश्मीरियों को तंग किया है, अब इनका अंत नजदीक है।

इसके बाद कश्मीर में सनसनी फैल गई और फिर से आतंकी संगठनों में खूनी जंग तेज होने की आशंका पैदा हो गई। अब घबराए हिजबुल के चीफ कमांडर सलाहुद्दीन ने लगभग माफी मांगने के अंदाज में वीडियो जारी किया है। इसमें आदिल की हत्या की बात कबूलते हुए कहा कि यह हत्या गलतफहमी में हुई है। उसने कहा कि भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए एक संयुक्त जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। सलाहुद्दीन ने इस वीडियो में पहली बार कश्मीर में अल-कायदा और आइएस की उपस्थिति को स्वीकारा। हालांकि पहले वह इन दोनों संगठनों की मौजूदगी को नकारता रहा है।

गिलानी के नाती से टेरर फंडिग के मामले में फिर होगी पूछताछ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नौ जुलाई को दिल्ली तलब किया
- अनीस के पिता अल्ताफ शाह पहले से ही हैं हिरासत में

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने टेरर फंडिंग के सिलसिले में कट्टरपंथी सईद अली शाह गिलानी के नाती अनीस-उल-इस्लाम शाह को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है।

कश्मीर में वर्ष 2016 के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों के लिए पाक व अन्य जगहों से वित्तीय मदद का संज्ञान लेते हुए एनआइए ने वर्ष 2017 में मामला दर्ज किया था। इस मामले में गिलानी के बड़े दामाद अल्ताफ शाह उर्फ अल्ताफ फंतोश, नेशनल फ्रंट के नईम खान, जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह, बिट्टा कराटे, शाहिद-उल-इस्लाम व जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक समेत एक दर्जन प्रमुख अलगाववादी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। उदारवादी हुर्रियत प्रमुख मीरवाइज मौलवी उमर फारुक से भी एनआइए पूछताछ कर चुकी है। गिलानी के दोनों बेटों से भी एनआइए ने तीन से चार बार पूछताछ की है। अनीस के पिता अल्ताफ शाह जुलाई 2017 से एनआइए की हिरासत में हैं और इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआइए द्वारा अनीस को भेजे गए समन में कहा गया है कि आप कश्मीर में आतंकी व अलगावावादी गतिविधियों के लिए पाक समेत विभिन्न विदेशी मुल्कों से फंडिंग संबंधी मामले से अवगत हैं। इसलिए आपको पूछताछ के लिए नौ जुलाई को लोधी रोड नई दिल्ली स्थित एनआइए कार्यालय में सुबह 10 बजे बुलाया जाता है।

अनीस से पहले भी एनआइए पूछताछ कर चुकी है। यह वही अनीस हैं, जिन्हें वर्ष 2016 में कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार ने नियमों में अनदेखी कर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर तैनात किया था।

कांवड़ मेले में सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की नजर

जागरण संवाददाता, देहरादून

- अंतरराज्यीय समन्वय समिति की बैठक में उत्तराखंड के डीजीपी ने दिए निर्देश
- कांवड़ यात्रियों से हाईवे से अलग वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने पर अफसरों ने दिया जोर

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि इस बार तीन करोड़ कांवड़ियों के देवभूमि आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी निगरानी होगी। डीजीपी ने अन्य राज्यों से आए पुलिस अधिकारियों से भी सोशल मीडिया सेल को एक्टिव करने को कहा है। ताकि सोशल मीडिया में गलत संदेश, अफवाह आदि पर पुलिस की नजर बनी रहे। वहीं, अंतरराष्ट्रीय और अंतराज्यीय सीमाओं पर भी कड़ी चेकिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा।

देहरादून के किशनपुर स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में मंगलवार को आयोजित 15वीं इंटर स्टेट और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बैठक में कांवड़ मेले के सफल और सुरक्षित संचालन पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आइटीबीपी, एसएसबी, रेलवे सुरक्षा बल, अभिसूचना ब्यूरो और कांवड़ ड्यूटी से जुड़े प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीजीपी रतूड़ी ने कहा कि सभी एजेंसियों के पारस्परिक सहयोग से शांति और कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है। वहीं, सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए कांवड़ रूट से लेकर शिविर और मंदिरों की विशेष सुरक्षा की जाएगी। इस बार तीन करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की संभावना के चलते हाईवे से इतर वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं।

अपराधियों पर रहेगी पैनी नजर : पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए रूट के हर प्वाइंट पर गहन चेकिंग की जाएगी। इसकी सूचनाएं सभी संबंधित राज्य एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

- अंतरराज्यीय बैरियर और चेकपोस्ट चिड़ियापुर बैरियर, नारसन चेकपोस्ट, लखनौता, काली नदी, गोवर्द्धन चेकपोस्ट पर सीमावर्ती प्रदेशों के साथ संयुक्त चेकिंग की जाएगी।
- कांवड़ यात्रियों के जुगाड़ वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- कांवड़ियों को नहर पटरी मार्ग का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए मार्ग बताने वाले होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे।
- सात फीट से ऊंची कांवड़ बनाने पर रोक रहेगी।
- कांवड़ मेले में नशा, तेज आवाज में संगीत और लाठी-डंडे पूर्व की भांति नियंत्रित किए जाएंगे।
- मेला स्थल और रूट पर अपील वाले होर्डिंग्स लगाकर कांवड़ियों से सहयोग की अपील की जाएगी।
- सोशल मीडिया में पुलिस को सहयोग देने और अपराध करने पर सजा के संदेश प्रसारित होंगे।
- नेपाल और चीन सीमा पर सभी पुलिस संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- वैधानिक व अवैधानिक रास्तों, वाहनों की चेकिंग और महत्वपूर्ण पुलों व स्थलों की सुरक्षा की जाएगी।

माखी दुष्कर्म पीड़िता के पैरोकार चाचा को दस साल की कैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव

- अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल और कैद की सजा काटनी होगी
- प्रधानी चुनाव के दौरान 19 साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
- वर्षों से फरार रहने की वजह से मामले में अटकी थी सुनवाई, गिरफ्तारी पर पूरा हुआ ट्रायल

बांगरमऊ से भाजपा विधायक के भाई पर जानलेवा हमले में दोषी साबित हो चुके माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता के पैरोकार चाचा को कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल और कारावास की सजा काटनी होगी। बता दें, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर माखी दुष्कर्म कांड में आरोपित हैं।

माखी गांव में प्रधान पद के लिए हो रहे चुनाव के दौरान वर्ष 2000 में पूर्व प्रधान और वर्तमान में बांगरमऊ विधायक कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर उर्फ अतुल सिंह पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें दुष्कर्म पीड़िता के पिता और दो चाचा भी आरोपित थे। बरी होने के बाद पीड़िता के पिता और एक चाचा की हत्या हो चुकी है। दूसरा चाचा सुनवाई के बीच ही फरार हो गया था, जिससे उस पर फैसला नहीं हो पाया था। वारंट जारी होने पर माखी पुलिस उसे दिल्ली से पकड़ कर लाई थी। वह रायबरेली जेल में है। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट के जज प्रह्लाद टंडन ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित चाचा को दोषी करार दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव के मुताबिक कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

चाचा पर दर्ज हो चुके 19 मामले : दुष्कर्म पीड़िता के चाचा पर कुल 19 मामले दर्ज हो चुके हैं। आठ में वह दोषमुक्त हो चुका है जबकि एक में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। अभी भी माखी थाना में सात, सदर कोतवाली में एक, जीआरपी में दो मामले दर्ज हैं। तीन मामले दुष्कर्म मामले की पैरवी के दौरान हुए हैं।

हाई कोर्ट में करेंगे अपील : पीड़िता के चाचा के वकील अजेंद्र अवस्थी और महेंद्र सिंह ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। बताया कि इसी मामले में उसके दो भाइयों को अदालत पहले बरी कर चुकी है तो उसे सजा कैसे हो सकती है।

4823 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था पहलगाम व बालटाल रवाना

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- पहलगाम रूट से बाबा अमरनाथ की गुफा की ओर गए 2584 श्रद्धालु
- **2239** श्रद्धालु बालटाल रूट से निकले बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए
- 3759 पुरुष, 936 महिलाएं और 128 साधु शामिल हैं इस जत्थे में

बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा अमरनाथ यात्रा के जम्मू स्थित आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर से मंगलवार सुबह 4823 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। तीसरे जत्थे में कुल 3759 पुरुष, 936 महिलाएं और 128 साधु शामिल थे जो 223 वाहनों पर सवार होकर यात्रा के लिए निकले। पहलगाम रूट से 2584, जबकि बालटाल रूट से 2239 श्रद्धालु अमरनाथ की गुफा में पहुंचेगे। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यात्रा के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी है।

अब तक डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु ने एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा ली है। बाबा बर्फानी पूरे आकार में पवित्र गुफा में विराजमान हैं। यात्रा के अगले जत्थे में शामिल होने के लिए यात्री निवास भगवती नगर में दो हजार के करीब श्रद्धालु पहुंच गए हैं। कुछ श्रद्धालु यात्री निवास आए बिना सीधे ही बालटाल और पहलगाम पहुंच कर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष रूप से कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है।

पवित्र अमरनाथ गुफा के बाहर ग्लेशियर पर लगा बाजार। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग दुकानों में प्रसाद रखते हैं और यहीं से श्रद्धालु पूजा का सामान खरीदकर बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाते हैं। जागरण

नेपा मिल के नवीनीकरण का काम जल्द कराने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद

नईदुनिया, बुरहानपुर: एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल मध्य प्रदेश की नेपा मिल का वर्तमान में नवीनीकरण हो रहा है। इसके लिए सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने नेपा मिल के श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत से मुलाकात की। मंत्री से सांसद चौहान ने नेपा मिल के नवीनीकरण कार्य को समय अवधि में पूरा कराने का आग्रह किया।

मंत्री अरविंद सावंत से करीब 45 मिनट की चर्चा में सांसद चौहान ने मिल के कार्य की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि समयावधि में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो क्षेत्र के लिए बेहतर होगा। साथ ही मिल के कर्मचारियों एवं श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान करने का मिल प्रशासन को निर्देश दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री सांवत ने आश्वस्त कि या कि नेपा मिल का कार्य समयावधि में पूर्ण कराएंगे। वहीं, मंत्री ने खुद भी नेपा मिल के भ्रमण पर आने का आश्वासन दिया। सावंत ने नेपा मिल की देखरेख कर रही अधिकारी को निर्देशित किया कि मिल की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। उल्लेखनीय है कि नेपा मिल के नवीनीकरण के लिए 469 करोड़ रुपये का रिवाइवल पैकेज केंद्र सरकार से दिलवाया गया है।

रखी बात

बीबीसी को दिए साक्षात्कार में कहा था, मेरी उत्तराधिकारी महिला भी हो सकती है, लेकिन उसे आकर्षक होना चाहिए, अब कहा- महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत किए जाने का विरोधी रहा हूं

आकर्षक महिला वाले बयान पर दलाई लामा ने मांगी माफी

जागरण संवाददाता, धर्मशाला

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 'आकर्षक महिला उत्तराधिकारी' वाले बयान पर क्षमायाचना करनी पड़ी है। दलाई लामा कार्यालय से जारी करीब पौने आठ सौ शब्दों के पत्र में उन्होंने सबसे क्षमा मांगते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। दलाई लामा कार्यालय से जारी इस स्पष्टीकरण को निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री डॉ. लोबसांग सांग्ये ने भी फेसबुक पर शेयर किया है।

दरअसल बीते दिनों, बीबीसी की संवाददाता ने उनसे पूछा था कि क्या उनका उत्तराधिकारी कोई महिला भी हो सकती है? इस पर उनका कहना था, 'हां, हो सकती है, लेकिन उसे आकर्षक होना चाहिए।' दलाई लामा ने हार्दिक खेद व्यक्त किया है कि इस बात से लोगों को ठेस लगी।

दलाई लामा कार्यालय के अनुसार, दलाई लामा ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि लोग मानवीय संबंधों में सतही या बाहरी आवरण देख कर नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर उतरें। अगला अवतार महिला के रूप में लेने और उसकी सुंदरता के प्रश्न पर उन्होंने साफ किया है कि इस प्रसंग की जड़ें 1992 से जुड़ी हैं। उन्होंने 'वो' पत्रिका के पेरिस संपादक के साथ इस प्रकार की चर्चा की थी जब दलाई लामा को पत्रिका का अतिथि संपादक बनाया गया था। उस महिला संपादक ने दलाई लामा से पूछा था, 'क्या अगला दलाई लामा कोई महिला भी हो सकती है?' दलाई लामा ने जवाब दिया था, 'यकीनन, अगर इससे और अधिक मदद होती हो तो...।' साथ ही मजाक में यह जोड़ा था, '...उसे आकर्षक होना चाहिए।' दलाई लामा कार्यालय के मुताबिक, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वह हाई फैशन से जुड़े लोगों से चर्चा कर रहे हैं।

दलाई लामा कार्यालय के अनुसार, भिक्षु के रूप में जीवन जीने वाले दलाई लामा अब 85 वर्ष के आसपास हैं, वह अपनी यात्राओं के अनुसार, भौतिक और ग्लोबल हो चुकी दुनिया के विरोधाभासों की समझ रखते हैं। उन्हें पता है कि एक संस्कृति के संदर्भ में जो बात मजाक के लायक है, वह किसी और स्थान पर ठेस भी पहुंचा सकती है। इसीलिए वह हार्दिक खेद व्यक्त करते हैं। उनके कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि दलाई लामा ने हमेशा महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत किए जाने का विरोध किया है और उनके नेतृत्व में ही तिब्बती बौद्ध भिक्षुणियां 'गेशे-मा' डिग्रियां पाने में सफल हुई हैं। ये पढ़ाई पहले केवल पुरुषों के लिए समझी जाती थी। दलाई लामा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यदि विश्व में महिला नेता अधिक होती तो शांति भी अधिक होती।

दलाई लामा कार्यालय के मुताबिक, इसी साक्षात्कार में शरणार्थियों के विषय में दलाई लामा की बात को भी ठीक से नहीं समझा गया है और हो सकता है कि कुछ लोग वतन वापस न लौटना चाहते हों या जहां बस गए हों, वहीं रहना चाहते हों लेकिन तिब्बतियों के मन में घर लौटने का सपना है।

दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु हैं। फाइल

पहले भी फंस चुके हैं विवाद में

इससे पूर्व दलाई लामा पंडित जवाहर लाल नेहरू के विषय में टिप्पणी करके विवाद में फंस गए थे कि वह स्वयं किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि उसे भी खारिज किया गया था। आमतौर पर दलाई लामा सहज रहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मिलने पर उनकी दाढ़ी को भी छू दिया था।

'शहाबुद्दीन की हिटलिस्ट में राजदेव का भी नाम था शामिल'

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

- सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में चौथे गवाह के रूप में राजदेव के बड़े भाई को किया पेश
- कालीचरण ने अदालत में कहा, जेल से ही राजदेव को धमकी दे रहा था पूर्व सांसद

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने मंगलवार को माननीयों (एमपी/एमएलए) की विशेष अदालत में उनके भाई कालीचरण प्रसाद को पेश किया। उन्होंने कहा, अखबार में खबर छपी थी कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की ओर से हिटलिस्ट जारी की गई है। इसमें उनके भाई पत्रकार राजदेव रंजन का भी नाम था। उनके भाई राजदेव रंजन ने बताया था कि शहाबुद्दीन जेल से उन्हें धमकी दे रहा है। सीबीआइ की ओर से इस मामले में यह चौथी गवाही है। इससे पहले राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन, पत्रकार दुर्गाकांत ठाकुर व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही हुई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

कालीचरण ने कहा कि 2014 में वह महुआवरी गांव के गब्बर सिंह के एक परिजन के श्राद्धकर्म में भाग लेने गए थे। वहां चर्चा चल रही थी कि जेल से शहाबुद्दीन ने एक हिटलिस्ट जारी की है। उसमें राजदेव रंजन का भी नाम है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के अखबार में एक खबर छपी है। 2016 में राजदेव रंजन ने पिता राधा चौधरी को बताया था कि जेल से शहाबुद्दीन धमकी दे रहा है। उस वक्त मैं वहां मौजूद था।

यह है मामला : 13 मई 2016 की शाम सिवान में राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था।

20 जुलाई से शुरू होगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मेघालय की राजधानी शिलांग के बीच विमान सेवा। यह सेवा इंडिगो एयरलाइंस मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही है।

प्रलयंकारी बारिश के कारण पटरी से उतरा मुंबई का जनजीवन

मुंबई में मूसलधार बारिश से जनजीवन बेहाल है। मंगलवार को यहां लोगों की मदद के लिए नौसेना को लगाया गया। एएनआइ

आफत ▶ जल जमाव के कारण कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात

रेल, हवाई सेवा और सड़क परिवहन पर पड़ा बुरा असर

राज्य ब्यूरो, मुंबई

बारिश के प्रलयंकारी रूप लेने के कारण मंगलवार को मुंबई बेबस सी हो गई। देश की आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में जल जमाव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रविवार से लगातार हो रही वर्षा के कारण रेल, हवाई सेवा एवं सड़क परिवहन पर बुरा असर पड़ा है। कई ट्रेनों और उड़ानों को रद कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 52 उड़ानों को रद और 54 को डाइवर्ट किया गया। दीवार ढह जाने से मुंबई में 22 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के शेष हिस्से में वर्षा जनित घटनाओं में पिछले 24 घंटे के दौरान 14 लोगों की जान गई है।

मौसम के बिगड़े हुए रुख को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को स्कूल-कॉलेज बंद रखने की घोषणा की थी। सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि मुंबईवासियों ने तीन घंटे में ही करीब 400 मिलीमीटर बरसात का सामना किया। यदि 26 जुलाई, 2005 की बाढ़ का दिन छोड़ दिया जाय तो 1974 के बाद यह दूसरा मौका है, जब कुछ ही घंटों के भीतर मुंबई में इतनी अधिक बरसात हुई है। मंगलवार दोपहर तक 48 घंटों के दौरान मुंबई में 550 मिलीमीटर बरसात हुई है।

मालाड के पिंपरीपाड़ा क्षेत्र में एक दीवार गिर जाने से कई लोग दब गए। इस घटना में 19 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। कल्याण में एक उर्दू स्कूल की दीवार ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई। चांदीवली इलाके में पानी के तेज बहाव के कारण 90 फुट चौड़ी सड़क गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई। क्रांति नगर कुर्ला में 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।

दोपहर तक ठप रही उपनगरीय रेल सेवा : ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण मध्य और पश्चिम रेलवे की उपनगरीय रेल सेवाएं मंगलवार दोपहर तक लगभग ठप रहीं। बरसात का ज्यादा असर मध्य रेलवे पर देखा गया, जहां सायन रेलवे स्टेशन की पटरियां थोड़ी बरसात के बाद ही डूब जाया करती हैं। बेस्ट की डेढ़ सौ से अधिक बसें भी जलभराव के कारण जगह-जगह खड़ी कर दी गईं।

मातोश्री के बाहर जलजमाव : मुंबई में हुई बारिश शिवसेना के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई है। मुंबई महानगरपालिका की सत्ता पर काबिज पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर जलजमाव हो गया है। उपनगरीय बांद्रा में कलानगर कॉलोनी में स्थित शिवसेना प्रमुख के आवास के बाहर घुटनों तक पानी भर गया है।

पुणे में मजदूरों की झोंपड़ी पर दीवार गिरी, छह की मौत : पुणे के अंबेगांव क्षेत्र में पिछले चार दिन के अंदर दूसरी बार चहारदीवारी मजदूरों की झोपड़ी पर गिर गई। दीवार के नीचे दबकर दो महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गई। सभी मजदूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे।

नासिक में वाटर टैंक ढहने से चार मजदूरों की जान गई : नासिक में एक निर्माणाधीन वाटर टैंक ढह जाने से चार मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गंगापुर रोड पर सोमेश्वर कालोनी में सुबह करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ।

मानसून चिंता का विषय नहीं, बोआई पकड़ेगी रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जून में कम बारिश के बावजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा, 'फिलहाल मानसून चिंता का विषय नहीं है।' मानसून को लेकर मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर सरकार नजर रख रही है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की रोपाई समय पर होगी। जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होने वाली है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण जल्द ही हो जाएगा, जिससे फसलों की बोआई और जोर पकड़ेगी। दरअसल, एमएसपी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। संभावना है कि बुधवार होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला हो जाएगा। तोमर ने कहा कि भारत में सूखा और बाढ़ जैसे मुद्दे कोई नए नहीं हैं। मौसम विभाग का ताजा अनुमान इस तरह की चिंता का कोई विषय नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश जून में 33 फीसद कम हुई है। इसी के चलते खरीफ फसलों की बोआई केवल 1.46 करोड़ हेक्टेयर में हो सकी है। पिछले साल इसी अवधि में 1.62 करोड़ हेक्टेयर में बोआई हो चुकी थी। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने माना कि जून में कुछ कम बोआई हो सकी है, जिसकी भरपाई जुलाई में हो जाएगी। अग्रवाल एक समारोह में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

सबवे में कार फंसने से दो की मौत : मलाड में सबवे में कार फंस जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया सोमवार रात 11:30 बजे दोनों मलाड में स्थित अपने घर लौट रहे थे। भारी बारिश के कारण सबवे में पानी भर गया था जिसमें उनकी कार फंस गई और वे बाहर नहीं आ सके। बाद में लोगों ने पानी में फंसी कार को खींच कर बाहर निकाला जिसमें दोनों बेहोश मिले। दोनों को समीप के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों की पहचान इरफान खान और गुलशाद शेख के रूप में की गई है।

रनवे से फिसला स्पाइसजेट का विमान

राज्य ब्यूरो, मुंबई

मुंबई में मंगलवार को एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। जयपुर से आ रहा स्पाइसजेट का विमान बारिश के चलते हवाई अड्डे के मुख्य रनवे से फिसलते हुए नीचे उतर गया। एएनआइ

मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय जयपुर से आया स्पाइसजेट का विमान मेन रनवे से फिसलकर घास के मैदान में जा पहुंचा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह घटना सोमवार रात 11:45 बजे हुई। घटना के बाद मेन रनवे पर विमानों की आवाजाही ठप हो गई है। स्पाइसजेट का विमान हटाए जाने के बाद गुरुवार तक इसे चालू किया जा सकेगा। फिलहाल वैकल्पिक रनवे का उपयोग किया जा रहा है।

डीजीसीए ने सुरक्षा निर्देश जारी किए : भारतीय विमानन निगरानी नियामक डीजीसीए ने खराब मौसम में लैंडिंग के बाद विमानों के रनवे पर फिसलने की कई घटनाओं के मद्देनजर एयरलाइनों को सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने एक सर्कुलर में कहा कि मानसून के दौरान विमानों के संचालन में चुनौतियां आती हैं जिसके कारण लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं। सर्कुलर में कहा गया है, 'विमान के क्रू सदस्यों को विपरीत मौसम में संचालन के दौरान विमान की रुकावटों और उड़ान भरने/लैंडिंग के बारे में अच्छी तरह परिचित होना चाहिए।' इसमें कहा गया है कि न्यूनतम कॉकपिट अनुभव का पालन करते हुए एयरलाइनों को विपरीत मौसम परिस्थितियों के दौरान विमानों का संचालन करने से पहले खुद खतरे का आकलन करना चाहिए।

मंगलुरु हवाई अड्डे पर विमान फिसलने की जांच शुरू : डीजीसीए की एक टीम ने दुबई से आए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिसल जाने की जांच शुरू कर दी है। रविवार शाम 186 यात्रियों और छह क्रू के साथ पहुंचा विमान मेन टैक्सीवे से फिसल कर कच्चे हिस्से में फंस गया था। सोमवार को विमान को पार्किंग एरिया में पहुंचाया गया। कथित रूप से तेज गति और गीले रनवे के कारण टर्मिनल की ओर बढ़ने के दौरान विमान फिसल गया।

कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे भी पर फिसला विमान

जासं, कोलकाता : बारिश की वजह से कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट का रनवे गीला होने के कारण जेट स्पाइस का एक विमान मंगलवार को लैंडिंग के समय फिसल गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। एयरलाइंस की ओर से बताया गया कि विमान को हल्की क्षति पहुंची है। विमान के फिसलने से रनवे के किनारे लगी चार लाइटों को भी नुकसान पहुंचा है। यह विमान पुणे से यहां पहुंचा था।

मोदी के 'बाउंसर' से बैकफुट पर आकाश विजयवर्गीय

नईदुनिया, इंदौर

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बाहर निकलते पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। प्रेट्र

कम उम्र में विधायक बने आकाश विजयवर्गीय ने 'बल्लेबाजी' तो कर दी, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। आवेदन, निवेदन, दनादन की लाइन ऑफ एक्शन अपनाने वाला आकाश खेमा दिल्ली से नजरें टेढ़ी होने के बाद सन्न रह गया। संसदीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों के 'बाउंसर' से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश बैकफुट पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री के सख्त रवैए के बाद कांग्रेस अब बल्लेबाजी मामले में आकाश और भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि मप्र के इंदौर में नगर निगम अफसर की बल्ले से पिटाई के बाद कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश की छवि उनके समर्थक एक हीरो जैसी पेश करने में जुटे थे। शहरभर में 'सैल्यूट आकाश' के होर्डिंग लगाए गए थे। रिहाई के बाद जश्न मना। इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों पर दिल्ली से नजर रखी जा रही थी और मंगलवार को उसका पटाक्षेप भी हो गया। आकाश ने अपने राजनीतिक शत्रु के रूप में मंत्री सज्जनसिंह वर्मा को चुना और उनके परिवार पर खतरनाक मकान खरीदने के आरोप लगाए। वर्मा का कहना है कि आकाश ने चर्चाओं में रहने के लिए अफसर को बल्ला मारा है। उनके पिता की कार्यशैली भी ऐसी रही है। वे अपने से बड़े कद के नेता से राजनीतिक शत्रुता रखते हैं। अब वैसी ही राजनीति आकाश अपना रहे हैं।

हाई कोर्ट ने कहा, अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के बाद कार्रवाई कर सकता है निगम : गंजी कंपाउंड के जिस मकान को लेकर हंगामा हुआ, उसका टूटना तय हो गया। मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि मकान में रह रहे लोगों को दो दिन के भीतर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के बाद निगम मकान तोड़ने की कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने जर्जर मकानों के खिलाफ निगम द्वारा चलाई जा रही मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुंबई, पुणे जैसे हादसे होंगे तो हम ही निगम को कोसेंगे। मकान में किराए से रह रहे भेरूलाल जोशी ने निगम की कार्रवाई को चुनौती देते हुए पूर्व उप महाधिवक्ता पुष्पमित्र भार्गव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि मकान मजबूत है। मंगलवार को जस्टिस रोहित आर्य की बेंच में सुनवाई हुई।

> प्रधानमंत्री का कथन देश के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने सभी को संदेश दिया है कि जो काम सौंपा है, उसे अपने दायरे में पूरा करें। जो हुआ है, वह नहीं होना चाहिए।
>
> – धीरेंद्र बायस, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, नगर निगम

> मैं तो यही कहूंगा कि हमें न्याय मिला है और कुछ नहीं चाहिए। देश के मालिक ने हमारे पक्ष में ऐसा कहा तो यह गर्व की बात है। भविष्य में मैं दोगुने उत्साह से काम करूंगा।
>
> – असित खरे, बिल्डिंग ऑफिसर, नगर निगम

आकाश की राजनीति पर यह सब पड़ा भारी

अफसर को बल्ला मारने की घटना राष्ट्रीय चैनलों और अखबरों में सुर्खियां बनी। इसमें विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपना लाइन ऑफ एक्शन आवेदन, निवेदन फिर दनादन बताया। उनके इस बयान को पार्टी लाइन के खिलाफ माना गया।

कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक न्यूज चैनल के एंकर से उसकी औकात पूछने पर भी उनकी तीखी आलोचना हुई। एंकर से उलझते कैलाश का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

जेल जाने के कोर्ट आदेश और धरने के दौरान समर्थकों के आत्मदाह के प्रयास को भी राजनीतिक हलकों में अलग अंदाज में लिया गया।

शहर में आकाश के पोस्टर्स लगाकर भी उनकी रिहाई को महिमामंडित किया गया।

रिहाई के आदेश के बाद उनके एक समर्थक ने विधायक कार्यालय के नीचे पांच गोलियां चलाईं। यह घटना भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसे खूब भुनाया।

आइएएस अफसर को प्रताड़ित करने पर बिहार सरकार को फटकार

जागरण सवांददाता, नई दिल्ली

- ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ आइएएस जितेंद्र गुप्ता ने की थी कार्रवाई
- कैट के आदेश को बिहार सरकार ने दी थी हाई कोर्ट में चुनौती

ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले आइएएस अधिकारी जितेंद्र गुप्ता का निरादर करने और उन्हें परेशान व प्रताड़ित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 2013 बैच के आइएएस अधिकारी की इंटर-कैडर ट्रांसफर की कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए और उन्हें बिहार कैडर से बाहर शिफ्ट करने का आदेश जारी हो। यह कार्रवाई चार सप्ताह में पूरी की जाए। पीठ ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह अन्य भुगतान के साथ पांच लाख रुपये मुआवजे के रूप में जारी करे। पीठ ने कहा कि वह आइएएस अधिकारी के दु:ख को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन इस आदेश से उन्हें राहत मिलेगी।

कोर्ट ने कहा कि माफिया और सरकारी मशीनरी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करने वाले अधिकारी को सुरक्षा देने में अदालत नाकाम रही तो गलत काम करने वालों के खिलाफ कोई अधिकारी नहीं खड़ा होगा। आइएएस अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने हरियाणा तबादला करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण उनकी जान को खतरा है। इस पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल (कैट) ने केंद्र सरकार को तबादला करने पर विचार करने के निर्देश दिए थे। कैट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर बिहार सरकार ने दावा किया था कि आइएएस अधिकारी के कैडर ट्रांसफर के पीछे की मंशा को समझने में ट्रिब्यूनल नाकाम रहा है। दावा किया था कि आइएएस अधिकारी आपराधिक मामले से बचना चाहते हैं, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन टीम के अन्य सदस्य आरोपित हैं। सुनवाई के दौरान जितेंद्र गुप्ता के वकील ने अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल को जुलाई 2017 से वेतन नहीं दिया जा रहा है।

पटना हाई कोर्ट ने रद की थी एफआइआर : जितेंद्र गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने तीन जुलाई 2016 को तीन ट्रक जब्त किए थे और उन्हें छोड़ने के बदले रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। एक महीने जेल में रहने के बाद वह जमानत पर छूटे थे। एफआइआर रद करने के खिलाफ गुप्ता ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ दर्ज एफआइआर 28 अक्टूबर 2016 को रद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश का बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय तबादले पर विचार करने का आदेश दिया था।

दुष्कर्म मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली को राहत

मुंबई, प्रेट्र : दुष्कर्म से जुड़े मामले में स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को 19 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए ढिंडोसी सत्र न्यायालय में अपील की थी।

अभिनेता की जमानत की मांग करते हुए उनके वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत में झूठ बोला था। शिकायत और पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि अलग-अलग हैं और इस तरह की विसंगति दिखाती है कि उसका इरादा झूठ बोलने का था। वकील ने कहा कि कथित अपराध के 15 वर्षों तक महिला चुप रही। उसने तब शिकायत दर्ज कराई जब महिला द्वारा दर्ज कराए गए अवमानना मामले में जज ने पंचोली के पक्ष में फैसला सुना दिया।

उधर, पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। जज एचबी गायकवाड़ ने सुनवाई को 19 जुलाई तक स्थगित कर दिया और पंचोली को अंतरिम राहत प्रदान कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस दौरान पंचोली को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अगले आदेश तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि पंचोली ने उसके निजी फोटो रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजने की धमकी देकर उससे 50 लाख रुपये भी ऐंठे हैं। जबकि पंचोली का कहना है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

विधायक को जारी होगा कारण बताओ नोटिस

नईदुनिया, भोपाल

भाजपा में पहले आवेदन, फिर निवेदन और उसके बाद दनादन का फॉर्मूला नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैए के बाद मध्य प्रदेश भाजपा भी इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय को बख्शने के मूड में नहीं है। संगठन ने साफ कर दिया कि आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस जारी कर अमर्यादित आचरण पर जवाब मांगा जाएगा। हालांकि, पार्टी के अधिकांश नेताओं ने मामला कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ा होने के कारण मौन धारण कर लिया है।

किसने-क्या कहा : नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि फिलहाल प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है। सांसदों से भी संसद चलने के कारण बात नहीं हो पा रही है। एक बार सही बात पता चले तो कुछ बोलें। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि सुबह साढ़े नौ बजे हमारी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी। संसदीय दल की बैठक में जा नहीं पाया। बैठक में क्या हुआ, कुछ पता नहीं।

भाजपा संसदीय दल के सचिव और सतना सांसद गणेश सिंह से कई बार बात करने की कोशिश की, एक बार उनके पीए दिनेश कुशवाह ने फोन उठाया और कहा कि साहब बंगले में हैं और व्यस्त हैं। वहीं, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई। निजी सहायक ने व्यस्तता का हवाला देकर बात नहीं कराई।

जवाब मांगा जा सकता है: भाजपा सूत्रों के मुताबिक, संगठन आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस जारी कर अमर्यादित आचरण पर जवाब मांग सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि हाईकमान से चर्चा के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कहा कि अभी प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह दिल्ली में हैं। वहां क्या बात हुई है, किन आधार पर क्या एक्शन पार्टी को लेना है, ये सब चर्चा के बाद तय किया जाएगा। भगत ने कहा कि जैसे दिशा-निर्देश केंद्र से मिलेंगे, संगठन वैसा कदम उठाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने चार दिन पहले दिए बयान में कहा था कि कमलनाथ सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अधिकारी सोच समझकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं।

अज्ञातवास पर आकाश : बल्ला कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आने के बाद आकाश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वे अज्ञातवास पर चले गए। उनके समर्थकों को भी नहीं मालूम कि वे कहां हैं। मीडियाकर्मी भी उनके निवास पर दोपहर में पहुंचे, लेकिन वे घर पर नहीं थे। आकाश को मंगलवार को भाजपा की सदस्यता अभियान की बैठक में शामिल होना था, लेकिन वे वहां भी नहीं पहुंचे।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ सैल्यूट मोदी: प्रधानमंत्री के बयान के बाद मंगलवार को इंदौर का बल्ला कांड और विधायक आकाश फिर से सोशल मीडिया पर पसंदीदा विषय बन गए। मोदी को अंपायर करार देते हुए सोशल मीडिया पर आकाश के आउट और समर्थक खेमे के आउट होने के मीम्स प्रसारित होने लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग सैल्यूट मोदी ट्रेंड करने लगा। बल्लेबाजी करते मोदी की तस्वीरें भी नजर आने लगीं।

पीएम को आकाश के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी : कांग्रेस

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी को कांग्रेस ने आइ वॉश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री को आकाश विजयवर्गीय के बारे में बोलने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।

कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने मंगलवार को कहा, 'यह सिर्फ आइ वॉश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? भाजपा में ऐसे नेताओं को पुरस्कृत करने का रिवाज है। जब प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे के समर्थन में बयान दिया था तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उस समय भी प्रधानमंत्री ने सिर्फ टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।'

बदला रूप

जागरण की मुहिम रंग लाई, कैराना के सुखनखेज अतीत की होगी वापसी, किराना घराना के लिए सोशल मीडिया व देश-दुनिया में उठी आवाज

पलायन नहीं, किराना घराना से होगी कैराना की पहचान

जागरण संवाददाता, शामली

> किराना घराने को सम्मान देने वाले लोगों का आभार। उम्मीद है कि केंद्र व राज्य सरकार किराना घराने की विरासत को सहेजने का प्रयास करेगी।
>
> – संगीतज्ञ इकबाल सोनी, उस्ताद करीम खां के प्रपौत्र

पलायन को लेकर देशभर में चर्चा में आए उप्र के शामली स्थित कैराना को खोई प्रतिष्ठा दोबारा वापस मिलने की उम्मीद परवान चढ़ रही है। इसके तहत संगीत के महान किराना घराना की धरोहर सहेजने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिले के नेताओं और प्रशासन ने इस बाबत कई घोषणाएं भी कर दी हैं। सोशल मीडिया और देश-दुनिया में संगीत-साहित्य के क्षेत्र से भी कैराना की पहचान प्रतिष्ठित संगीत घराना से कराने की आवाज उठ रही है।

दैनिक जागरण में रविवार को 'किराना घराना से कैराना का किनारा' शीर्षक से खबर प्रकाशित होते ही शामली के प्रशासन, राजनीतिज्ञों और संगीतज्ञों ने किराना घराना की धरोहर सहेजने का बीड़ा उठा लिया है। सपा विधायक नाहिद हसन ने कहा कि राज्य सरकार से किराना घराने की विरासत को सहेजने, स्मारक बनाने व उस्ताद अब्दुल करीम खां के आवास का अधिग्रहण कर वहां म्यूजियम बनाने की मांग की जाएगी। यहां हर वर्ष उस्ताद करीम खां संगीत महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। उस्ताद के नाम पर कचहरी में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। राज्य सरकार से मांग की जाएगी कि पानीपत-खटीमा मार्ग का नाम उस्ताद के नाम पर रखा जाए। कैराना-कांधला तिराहा पर उस्ताद का स्मारक बनाया जाए। नगरपालिका के हाल में उस्ताद का चित्र लगाया जाएगा। राज्यमंत्री सुरेश राणा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले दिनों उनसे किराना घराना के बाबत बात की थी। राणा ने मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत करने की बात कही है।

यह है किराना घराना : कैराना में 1872 में सारंगी वादक उस्ताद काले खां के यहां अब्दुल करीम खां का जन्म हुआ। इन्होंने बीस साल की उम्र में कैराना से छोड़ दिया था और जयपुर के राजघराने में बतौर शास्त्रीय गायक नियुक्त किए गए। करीम खां को कैराना की मिट्टी से इतनी मोहब्बत थी कि इन्होंने अपनी संगीत की नर्सरी का नाम किराना घराना रखा। इस घराने ने उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत शैली के बीच सेतु का काम किया। यह घराना विशिष्ठ ख्याल गायकी, ठुमरी, दादरा, भजन और मराठी नाट्य संगीत गायन के लिए जाना जाता है। भारत रत्न भीमसेन जोशी, मोहम्मद रफी, बेगम अख्तर, खय्याम और रूपकुमार राठौड़ समेत कई दिग्गजों ने इसी घराने में संगीत का ककहरा सीखा।

भीम आर्मी के पदाधिकारी ने दी परिवार संग पलायन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, बागपत : चौबीस घंटे में पुलिस सुरक्षा न मिलने पर भीम आर्मी के बागपत विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुरेंद्र ने परिवार समेत गांव से पलायन की चेतावनी दी है। बागपत के बड़ौत में बीते 16 अप्रैल को आधा दर्जन बदमाशों ने हसनपुर-मसूरी गांव निवासी सुरेंद्र को गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले में सात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पांच लोग जेल भेजे गए थे। पुलिस ने केस से दो आरोपितों के नाम निकाल दिए थे। आरोप है कि हमलावर पक्ष के लोग समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुरेंद्र को अभी सिर्फ दिन के समय पुलिस सुरक्षा दी जा रही है लेकिन वह अधिकारियों से 24 घंटे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुरेंद्र ने सुरक्षा न मिलने पर परिवार समेत पलायन करने की चेतावनी दी है। परिजनों ने बताया कि जान बचाने के लिए सुरेंद्र मंगलवार सुबह अपने रिश्तेदार के यहां चले गए। सीओ आरपी सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी लेंगे।

ससुर से संबंध बनाने से इन्कार किया तो पति ने दिया तीन तलाक

जागरण संवाददाता, यमुनानगर

- हरियाणा के यमुनानगर का मामला
- स्थानीय पुलिस ने नहीं की सुनवाई

ससुर से संबंध बनाने से इन्कार किया, तो पति ने तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाल दिया। मामला शहर थाना जगाधरी एरिया की कॉलोनी का है। जब स्थानीय पुलिस ने महिला की सुनवाई नहीं की, तो उसने एसपी कुलदीप यादव से गुहार लगाई। एक पखवाड़े में तीन तलाक का ये दूसरा मामला है।

एसपी को दी शिकायत में यमुनानगर निवासी पीड़िता ने कहा 15 जनवरी 2005 को उसका निकाह जगाधरी के युवक से हुआ। पिता ने हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया। इसमें पांच लाख रुपये खर्च हुए। उसके एक बेटा और बेटी हैं। निकाह के करीब दो साल बाद उसके ससुर ने उस पर गलत नीयत रखते हुए जोर जबदस्ती शुरू कर दी। जब इस बारे में पति को बताया, तो उसने उसका ही कसूर निकल दिया। जब सास को बात बताई, तो उसने भी यकीन नहीं किया। इसके बाद उसे घर से निकालकर चौबारे पर बने टीन के छप्पर में भेज दिया, जिसमें न तो दरवाजा था और न ही दीवार थी। पति के काम पर जाने के बाद ससुर ताक-झांक करता था। उसने माता-पिता को इस बारे में बताया तो वे उसे अपने साथ ले गए। बाद में बिरादरी पंचायत में ससुरालियों ने गलती मानी और वह वापस आ गई।

सास की मौत के बाद की जबरदस्ती : पीड़िता के मुताबिक सास की मृत्यु के बाद ससुर उसके कमरे में आया और जबरदस्ती करने लगा। कहने लगा कि 50 गज का प्लॉट उसके नाम करा देगा और खर्च भी उठाएगा। यदि वह उसकी बात मान जाए तो पति को इस बारे में पता नहीं लगेगा। इस बात को पति और देवर को बताया, तो उन्होंने लात और घूसों से पीटा। 25 जून को उन्होंने पीड़िता को बच्चों सहित घर से निकाल दिया। जब उसने 100 नंबर पर मदद के लिए फोन किया, तो पति ने तैश में आकर उसे तीन तलाक दे दिया।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 3 जुलाई 2019

दैनिक जागरण

आत्मविश्लेषण सुधार की दिशा में पहला कदम होता है

न्यायसंगत सवाल

न्यायपालिका के अंदर से ही जवाबदेही और पारदर्शिता की आवाजें उठना स्वागतयोग्य है। पहले मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपने कामकाज का विवरण सार्वजनिक करते हुए न्यायपालिका में जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित किया। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कोलेजियम व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करते हुए साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में परिवारवाद और जातिवाद का बोलबाला है। यह पहली बार नहीं जब कोलेजियम व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अब ऐसे सवाल उच्चतर न्यायपालिका के जज ही उठा रहे हैं। देखना है कि इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट गौर करता है या नहीं? वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोलेजियम व्यवस्था का विकल्प बनने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना था कि इस व्यवस्था में खामियां हैं, लेकिन उन्हें दूर करने का काम अब तक नहीं हो सका है। यह न्यायसंगत नहीं कि जिस कोलेजियम व्यवस्था की खामियों को खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया हो उसके आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती रहें। ऐसा होना इसलिए भी ठीक नहीं, क्योंकि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते। आखिर जैसा दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता वैसा भारत में क्यों होना चाहिए? यह वह सवाल है जो न तो सुप्रीम कोर्ट का पीछा छोड़ने वाला है और न ही सरकार का।

जरूरी केवल यही नहीं है कि न्यायाधीशों की ओर से अपने साथियों की नियुक्ति की अलोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो, बल्कि यह भी है कि न्यायिक क्षेत्र में इस तरह के सुधार बिना किसी देरी के किए जाएं कि समय पर न्याय मिलना संभव हो सके। न्याय में देरी और लंबित मुकदमों के बोझ का उल्लेख एक अर्से से अवश्य किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि लोगों को समय पर न्याय कब सुलभ होगा? न्याय में देरी के सिलसिले के कारण करोड़ों लोग न्याय से ही वंचित नहीं हैं, बल्कि विकास के काम भी बाधित हैं। न्याय में देरी से भारतीय समाज कानून के शासन के प्रति वैसा प्रतिबद्ध नहीं दिखता जैसा उसे दिखना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, न्याय में देरी की समस्या समाज को अनुशासित बनाने में भी बाधक बन रही है। बेहतर होगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और साथ ही विधायिका यह महसूस करें कि न्यायिक तंत्र की मौजूदा स्थिति देश के अपेक्षित विकास में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। आज चाहे आम लोग हों या खास, वे इस पर भरोसा नहीं कर पाते कि अदालतों से उन्हें समय पर न्याय मिलेगा। भरोसे की यह कमी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और गरिमा पर एक सवाल ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जो कुछ कहा उस पर केवल चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे कदम भी उठाए जाने चाहिए जिससे न्यायपालिका भरोसे की कमी के संकट से मुक्त हो। बेहतर होगा कि न्यायिक नियुक्त आयोग के गठन की पहल नए सिरे से की जाए।

नारी सशक्तीकरण

उत्तराखंड में आधी आबादी यानी महिलाएं नित सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं। किसी भी राज्य के लिए यह न केवल खुशी का विषय है, बल्कि उसकी तरक्की का बड़ा आधार भी है। उत्तराखंड तो मातृशक्ति के बूते ही वजूद में आया है। यहां अलग राज्य के लिए चले आंदोलन की अगुआ महिलाएं ही रहीं। दिलचस्प यह कि उन्हें किसी ने जिम्मेदारी सौंपी नहीं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए खुद-ब-खुद महिलाओं ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली और पुरुषों ने इसे सहर्ष स्वीकारा। महिलाओं ने शहादतें दीं, प्रताड़ना सही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, नतीजा अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड सभी के सामने है। इतना ही नहीं, सेना के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की नारी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। दो दशक के अंतराल में लगभग हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी बढ़ी है। यह अलग बात है कि सियासी मोर्चे पर महिलाओं को अभी बराबरी का हक नहीं मिल पाया है। राजनीतिक दलों के एजेंडे में यह बात दिखाई जरूर पड़ती है, लेकिन इस पर अमल में उनकी हिचकिचाहट पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस सबके बीच, सकारात्मक पहलू यह कि मातृशक्ति में आगे बढ़कर नेतृत्व करने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। हालिया दिनों में सामने आई उपलब्धियां इसका प्रमाण हैं। जन्मलिंगानुपात में उत्तराखंड की बत्तीस अंकों की उछाल यह बताने के लिए काफी है कि यहां 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को कितनी संजीदगी से लिया गया। बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने संबंधी संसद में रखी गई हालिया रिपोर्ट नारी सशक्तीकरण की गवाही दे रही है। इसमें उत्तराखंड अव्वल रहा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को पछाड़कर उत्तराखंड इस मामले में पंजाब, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों की बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने को लेकर राज्यों के रुख पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी।

बिखराव की ओर बढ़ता पाकिस्तान

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

भारत के लिए यह सबसे बेहतर समय है कि वह पाकिस्तान की खस्ताहाल स्थिति का लाभ उठाए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे

पाकिस्तान हमेशा से भारत को परेशान करता आया है जबकि उसके प्रति भारत का रवैया अक्सर ही नरम रहा। भारत ने उसके प्रति नरम रवैया अपनाते हुए यही सोचा कि पड़ोस में अमन-चैन कायम होना उसके हित में रहेगा, मगर यह धारणा गलत साबित हुई। वास्तव में एकजुट के बजाय विभाजित पाकिस्तान ही भारत के हित में है। इस्लामाबाद को अलग-थलग करने के लिए अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने कई मोर्चों पर दबाव बनाए रखा। आज पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बदहाल है। वह एक और राहत पैकेज के लिए गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के पास केवल सात अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार शेष है। इसकी तुलना में वर्ष 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बना बांग्लादेश 33 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ सहज स्थिति में है। पाकिस्तान के जीडीपी की विकास दर चार प्रतिशत रहने का अनुमान है और कुछ अनुमानों के अनुसार यह तीन प्रतिशत ही रह सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग घटाकर बी निगेटिव कर दी है। इस्लामाबाद को हाल में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और चीन से आर्थिक मदद मिली है, लेकिन यह काफी नहीं। बीते दिनों एफएटीएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया, क्योंकि वह आतंकी गतिविधियों को वित्तीय मदद रोकने में नाकाम रहा। इस वैश्विक निगरानी संस्था ने इस्लामाबाद को अक्टूबर तक मोहलत दी है कि वह आतंकी गतिविधियों को वित्तीय मदद पर रोक लगाए, अन्यथा उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। इस्लामाबाद के लिए ऐसे हालात बनाने में भारत के कूटनीतिक करिश्मे ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल पाक नस्लीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक आधार पर बुरी तरह विभाजित है।

इस्लामाबाद आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर अमेरिका को बरगलाता आया है। एक तरफ उसने यह छलावा पेश किया कि वह आतंक के खिलाफ लड़ाई में जुटा है तो वहीं तालिबान से लेकर कश्मीर में आतंकियों की मदद भी करता रहा। अमेरिका अब पाकिस्तान का मित्र नहीं रहा और उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सैन्य-असैन्य मदद रोक दी है। पाकिस्तान अब चीन के रहमोकरम पर है और चीन उसे अजगर के माफिक शिकंजे में कस रहा है। वहां उप-राष्ट्रवाद भी उफान पर है। आसमान छूती महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की किल्लत, रोजगार की कमी, बेतहाशा गरीबी, बढ़ती विषमता, नेताओं, सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा जमा की गई अकूत संपत्ति, बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था और जिहादियों की हिंसा से आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। पाकिस्तानी राजनीतिक-सैन्य-मजहबी नेतृत्व की तिकड़ी से पैदा हुआ आतंकवाद का जिन्न अब भस्मासुर बनकर अपने ही आका को बर्बाद करने पर तुला है। भारत के साथ बढ़ता तनाव पाकिस्तान के लिए आत्मघाती है। जब अर्थव्यवस्था उतार पर है, राजनीतिक व्यवस्था पंगु है और तमाम रणनीतिक चुनौतियां हैं तब पाकिस्तान भारत के साथ सीमा पर तल्खी बढ़ाने का जोखिम नहीं ले सकता। भारत के लिए यह सबसे बेहतर समय है कि वह इस स्थिति का लाभ उठाए। मोदी सरकार की सख्ती बढ़िया नीति रही है। मिसाइलों के परीक्षण से पाकिस्तानी खजाने पर बोझ बढ़ा है, जबकि सैन्य खर्च में कटौती की तत्काल आवश्यकता है। इसके बावजूद उसने पिछले वर्ष की तुलना में रक्षा बजट में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी कर 9.6 अरब डॉलर किया। पाकिस्तान का कुल जीडीपी 305 अरब डॉलर का है। इस लिहाज से यह अनुपात बहुत असंतुलित है। रक्षा पर खर्च होने वाला प्रत्येक रुपया समझिए विकास गतिविधियों की अनदेखी करके हो रहा है। चूंकि पाकिस्तान की अधिकांश आबादी दो वक्त के खाने के लिए संघर्ष करने के साथ ही बिजली की कटौती और रोजगार की किल्लत से जूझ रही है इसलिए रक्षा पर बढ़ा खर्च मुश्किल बढ़ाने का ही काम करेगा।

अवधेश राजपूत

बहुसंख्यक बलूच और सिंधियों का एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम चला रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के पठान भी अफगानिस्तान के साथ विलय करना चाहते हैं। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के उदय के बाद सिंधी नेता जीएम सईद ने सिंधियों के लिए सिंधुदेश बनाने के मकसद से जिये सिंध आंदोलन का सूत्रपात किया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित किया। रॉ ने पाकिस्तानी सेना, वायुसेना और विदेश सेवा में कार्यरत बंगालियों को अपना एजेंट बनाया। इन एक साथ दिए झटकों से ही पाकिस्तानी सेना को परास्त किया गया, मगर अब रॉ को एक साथ चार मोर्चों पर सक्रिय होकर बलूच, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गुलाम कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान के विद्रोहियों का साथ देना चाहिए, जो पंजाबी प्रभुत्व के साये में पिस रहे हैं। इन इलाकों में धीरे-धीरे पंजाबियों की बसावट से जनसांख्यिकी अनुपात बिगड़ रहा है और स्थानीय पहचान गुम हो रही है।

स्थानीय लोग भारत के समर्थन के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तानी तालिबान के रूप में केवल एक आतंकी धड़े से निपटने में ही पाकिस्तानी सेना के 70,000 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में अगर भारत चार मोर्चों पर चल रहे विद्रोह को शह दे तो पाकिस्तानी सैन्य बलों को बड़ी चोट पहुंचेगी। जो लोग यह दलील देते हैं कि इससे पाकिस्तान भी भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ाएगा तो वे यह भूल जाते हैं कि चूंकि वह छोटा देश है इसलिए उसे इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे भी इस्लामाबाद पहले से ही इस खेल में लगा है। चार प्रांतों में छद्म युद्ध पाकिस्तान के 60 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जल्द ही पाकिस्तानी जनरलों को अहसास हो जाएगा कि भारत उसके समक्ष गंभीर संकट पैदा कर सकता है। पाकिस्तानी जनरल आलीशान जिंदगी और सेवानिवृत्ति के बाद तमाम सुविधाओं के आदी हैं, ऐसे में वे भारत के साथ तल्ख संघर्ष नहीं पचा सकते।

अमेरिका में सामरिक रणनीतिकारों का एक वर्ग पाकिस्तान के टुकड़े करने की हिमायत करता है। इसमें बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश बनाने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाकों का अफगानिस्तान में विलय की बात होती है जिससे पाकिस्तान केवल सिंध और पंजाब तक सीमित रह जाए। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बफर बनेगा, ईरान की दक्षिण-पूर्व सीमा पर पकड़ बढ़ेगी और ग्वादर बंदरगाह के जरिये कराकोरम को अरब सागर से जोड़ने के चीनी मंसूबे ध्वस्त होंगे। इस विचार को ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी सेंटर ने आगे बढ़ाया है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए भारत को अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर कोई पुख्ता योजना तैयार करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की परमाणु ताकत भी निष्प्रभावी हो जाए। भारत पानी को भी अपना हथियार बनाए। सिंधु जल समझौते को नए सिरे से तय करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा स्वरूप में भारत को नुकसान है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन को सभी रियायतें बंद की जानी चाहिए। भारत को विश्व शक्ति बनने की राह में सबसे बड़े रोड़े को निश्चित रूप से दूर करना चाहिए। हालात भी दुहाई दे रहे हैं कि उनका फायदा उठाया जाए।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

जल संपदा सहेजने का समय

हरेंद्र प्रताप

जल संकट से निपटने के लिए सरकार बोरिंग के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में कोई नीतिगत निर्णय ले

इन कहावतों को हम सब अक्सर ही सुनते हैं- 'जल ही जीवन है।' 'बिन पानी सब सून।' इन कहावतों का आशय यह है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार यहां मौजूद जल ही है। इसके अभाव में पूरी धरती एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। हम भाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जो जल संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन हम इंसानों की नासमझी के कारण यह जल संपदा दिनोंदिन न सिर्फ कम होती जा रही है, बल्कि प्रदूषित भी होती जा रही है। इस संपदा पर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चूंकि जल पर जीवन निर्भर है इसलिए यह कह सकते हैं कि इसके साथ हमारा जीवन भी संकटग्रस्त होता जा रहा है। यह खतरा दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है और भविष्य में इसके और भी गहराने के आसार दिख रहे हैं। समय रहते इससे निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का सुझाव दिया है। पानी की यह समस्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते और गहरा गई है। प्रति वर्ष प्रायः एक जून को केरल में मानसून का प्रवेश हो जाता था, पर इस बार अल नीनो प्रभाव के चलते उसने 8 जून को देश में प्रवेश किया। यह विलंब क्यों? मानसून में इस देरी की एक वजह बढ़ता प्रदूषण और इसके चलते हुआ जलवायु परिवर्तन भी है।

देश में जल के गहराते संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने 'जल शक्ति मंत्रालय' का गठन किया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी ग्राम स्वराज्य के तहत यह घोषणा की है कि वह 2024 तक सभी घरों में शौचालय के साथ ही साथ प्रत्येक घर को 'नल से जल' की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। सवाल यह उठता है कि घरों में जल की आपूर्ति के लिए वह जल कहां से लाएगी? क्या घरों में जलापूर्ति के लिए सरकार भी बोरिंग कर भूमिगत जल का ही उपयोग करने वाली है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में भूमिगत जल का स्तर विगत चार दशक में 20 से 50 फीट तक नीचे चला गया है। देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अप्रैल आते-आते ताल-तलैया के साथ ही साथ हैंडपंप भी सूख जा रहे हैं। इसके तात्कालिक उपाय के रूप में राज्यों की सरकारें हैंडपंप की गहराई बढ़ाती जा रही हैं, पर चूंकि भूगर्भ जल तेजी से नीचे जा रहा है अतः पेयजल का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। देखा जाए तो तीन तरफ से समुद्र और उत्तर में हिमालय से घिरे राष्ट्र के समक्ष आज जो जल संकट पैदा हुआ है वह हमारी अपनी देन है। वास्तव में हमने जल संरक्षण के अपने पारंपरिक तौर-तरीकों को भुला दिया है। गांवों-देहातों में आज भी यह कहावत प्रचलित है, 'ऊपर का जल ऊपर के लिए और नीचे का जल पीने के लिए।'

अर्थात दैनिक नित्यकर्म जैसे कि शौच, स्नान, कपड़े धोने, पशुओं और कृषि कार्य हेतु वर्षा के जल का उपयोग किया जाता था और खाना बनाने और पीने के लिए भूमिगत जल का, जो कुओं से निकाला जाता था। वर्षा जल के संग्रह के लिए बावड़ी, तालाब आदि थे, जिनकी देखभाल की जबावदेही सभी की थी। हिमालय से निकलने वाली नदियों में भी साल भर शुद्ध जल का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में रहता था।

एक समय हिमालय पर बरगद, पाकड़, जामुन, महुआ आदि फलदार और जड़दार पेड़ होते थे जो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रहते थे। वर्षा के समय इन्हीं वृक्षों की जड़ों के कारण बारिश का पानी हिमालय में रुका रहता था और फिर धीरे-धीरे कर रिसते हुए नदियों में बहता रहता था, लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे की पटरी के लिए वैसे वृक्षों को हिमालय में विकसित किया जो रेलवे की पटरी के लिए काम तो आते थे, पर उनकी छाया के नीचे घास भी पैदा नहीं होती थी। हमारी उपेक्षा और वनों की अंधाधुंध कटाई से हिमालय में धीरे-धीरे जड़दार वृक्ष खत्म हो गए। परिणाम हमारे सामने है। वर्षा के समय जल के साथ ही हिमालय से मिट्टी और गाद के कारण नदियों में सिल्ट की समस्या पैदा हो रही है। नदियों में जल प्रवाह और जल की मात्रा में तेजी से कमी आ गई है। जलप्रवाह घटने और नगरीय संस्कृति के प्रभाव में सीवरेज और गंदे जल को प्रवाहित करने से नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि मनुष्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, पशु-पक्षी भी उस जल का उपयोग नहीं करते। जल संकट का दूसरा सबसे बड़ा कारण है आधुनिकता और सुविधा युक्त हमारी जीवन शैली। एक व्यक्ति शौच और लघुशंका के लिए जब-जब शौचालय जाता है तब-तब फ्लश चलाता है। इस दौरान वह लगभग 4-5 लीटर शुद्ध पानी को गंदे नाले में बहा देता है। प्रति व्यक्ति यह बर्बादी कम से कम 30-35 लीटर प्रतिदिन तो है ही। पहले नदी या तालाब में स्नान करने के साथ ही साथ वहां कपड़े भी धो लिए जाते थे। आजकल घरों में वाशिंग मशीन आ गई है। वाशिंग मशीन में कितने जल का इस्तेमाल होता है, इसका कोई हिसाब नहीं। पेयजल के लिए घरों में लगी 'आरओ' मशीन एक लीटर पानी साफ करती है और आधा लीटर बेकार बहाती है। देश में उत्पन्न जल संकट का एक और बड़ा कारण है बोरिंग। आज गांवों से लेकर शहरों तक बोरिंग के माध्यम से भूमिगत जल का तेजी से दोहन हो रहा है। सरकारें भी कृषि कार्य के लिए किसानों को बोरिंग पर सब्सिडी दे रही हैं। बोरिंग के कारण घटते भूमिगत जलस्तर का प्रभाव पेयजल के लिए लगाए गए हैंडपंप और कुओं पर पड़ रहा है।

हालांकि इधर के वर्षों में भूमिगत जल को 'रीचार्ज' करने और 'अपशिष्ट' जल के पुनर्प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है, पर यह समस्या के समाधान की दृष्टि से यह 'ऊंट के मुंह में जीरा' के समान है। जल संरक्षण के लिए सरकार को सबसे पहले बोरिंग के उपयोग के बारे में कोई नीतिगत निर्णय लेना होगा। कृषि के लिए नहर, तालाब या अन्य विकल्पों की तलाश करने के साथ ही दैनिक जीवन में आए परिवर्तन के कारण बर्बाद हो रहे जल के पुनर्प्रयोग की योजना को कड़ाई से लागू करना होगा, वरना यह संकट जल्द ही 'जल युद्ध' का रूप अख्तियार कर सकता है।

(लेखक बिहार विधानपरिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन

मन को मारना नहीं है, संवारना है। मन के बिना मनुष्य कैसा? मन योगी के पास भी है और भोगी के पास भी। मन ऊपर उठता है तो कृष्ण बन जाता है और नीचे गिरता है तो कंस। यह मनुष्य की संकल्प-शक्ति पर निर्भर है कि वह मन का उपयोग कैसे करता है? आदतन मन चंचल होता है। इसीलिए मनुष्य अशांत रहता है। जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार रच देता है और जब आत्मोन्मुख होता है तो संन्यास की डगर पर चल देता है। मन ही है, जो मनुष्य को भवकूप में फंसाता है और भवसागर से उबारता भी है। वह न स्वभाव से अच्छा है और न ही बुरा। अच्छा बनने के लिए मन की गुलामी से बचना होगा।

योगी ही मन की असलियत समझता है। वह जानता है कि संसार मनोकल्पित है। जब तक मन मनमानी करता है, तभी तक मनुष्य प्रपंच में भटकता है। मन के सधते ही प्रपंच मिटने लगता है। सुषुप्ति में मन के न रहने पर संसार भी नहीं रहता। जागृत और स्वप्न की अवस्था में मन सक्रिय हो जाता है और प्रपंच में भटकन शुरू हो जाती है। ध्यान रहे कि जब मन है तो संसार है और मन नहीं है तो संसार भी नहीं है। अर्थात 'अ-मन' होते ही योगी कमलपत्रवत् शरीर-संसार में होते हुए भी दोनों से अलिप्त हो जाता है।

आचार्य शंकर के विचार में यही 'अ-मनी भाव' की अवस्था है। विवेक ज्ञान के अभ्यास से वैराग्य जगता है और मन शांत, एकाग्र और निर्मल हो जाता है। मन के निर्मल होते ही भवसागर सूख जाता है। अपने मन को विराट से जोड़ना है। विराट से जुड़ते ही मन अंदर संचित वासनाओं के घेरे से बाहर निकलने लगता है। फिर तो व्यष्टि मन 'लोकमन' बन जाता है और योगी परमात्मा से जुड़कर सब का हो जाता है। वह सर्वत्र प्रभु को देखता है और प्रभुभाव से ही सोचता, विचारता और कर्म करता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने मन को मेरे 'विराट मन' से जोड़ दो। यही 'जीवन मुक्ति' है, जिसे अध्यात्म की भाषा में 'अ-मनी भाव' कहा गया है। मनुष्य की साधना यात्रा मन पर समाप्त नहीं होती। उसे मन से ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंचना है। मन मंजिल नहीं, बल्कि सीढ़ी है। देह और आत्मा के मध्य मन डोलता रहता है। लोभ से जुड़कर मन लोभी हो जाता है और काम से जुड़कर कामी। करुणा से जुड़ते ही वही मन संत बन जाता है।

डॉ. दुर्गादत्त पांडेय

भीड़तंत्र में तब्दील होते हम

अंशुमाली रस्तोगी

भीड़ का मनोविज्ञान जिस तरह से हिंसा में तब्दील हो रहा है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे का संकेत है

एक सभ्य समाज और लोकतांत्रिक देश में भीड़ का बेकाबू होकर किसी को भी पीट-पीटकर मार डालना उचित नहीं ठहराया जा सकता। भीड़ को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वह कानून अपने हाथों में ले। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से भीड़ द्वारा हत्याओं (मॉब लिंचिंग) की घटनाएं बढ़ी हैं, वे न केवल आतंकित करती हैं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि लोगों में सहनशक्ति का ह्रास इतनी तेजी क्यों हो रहा है? अभी हाल झारखंड में एक युवक को भीड़ ने अपने गुस्से का निशाना बनाया, यह घटना स्तब्ध कर देने वाली है। क्यों हम किसी पर धार्मिक नारा बुलवाने का दबाव डालते हैं? एक लोकतांत्रिक देश में यह अधिकार किसी को नहीं है कि वह किसी को भी कोई भी धर्म मानने या धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करे। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है।

समाज में जब भीड़ ही सबकुछ तय करने लगेगी तो न्याय-व्यवस्था का रोल क्या रह जाएगा! फिर तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। हो दरअसल यही रहा है। कुछ लोगों ने मान लिया है कि वे ही न्यायकर्ता हैं। ऐसे लोग ही भीड़ को उकसाते हैं। मारने-पीटने के लिए उत्तेजित करते हैं। भीड़ द्वारा कथित न्याय का सिलसिला बढ़ना हर व्यक्ति के लिए खतरनाक है। यह देश को भी शर्मसार करता है। भीड़ को उकसाने में सोशल मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आए दिन किसी न किसी घटना के वायरल होते संदेश लोगों में भय और हिंसा का ग्राफ बढ़ाते हैं। देश के कई हिस्सों में ऐसी वारदातें हुई हैं, जिनमें वाट्स एप या फेसबुक के किसी मैसेज से भीड़ भड़की है। गुस्से से भरी भीड़ तब मैसेज के सही या गलत होने पर ध्यान न देकर सीधे खुद ही न्याय करने लग जाती है।

उसमें विवेक तो होता नहीं, बस किसी भी तरह विरोधी को सबक सीखने का नशा उस पर सवार रहता है। यह स्वभाव सिर्फ भीड़ का ही नहीं, हमारा भी हो गया है। हाल में बुलंदशहर में छेड़छाड़ के विरोध में एक युवक ने लड़की के परिवार की दो महिलाओं की कार से रौंद कर हत्या कर दी। बात न मानने पर ऐसी जघन्य वारदात को आंजम देना साफ बताता है कि हमारे भीतर से सहनशक्ति निरंतर कम होती जा रही है। भीड़ का मनोविज्ञान जिस तरह से हिंसा में तब्दील हो रहा है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे का संकेत है। क्योंकि पीढ़ी जो देखेगी वही करने की सोचेगी भी। यही सोच उसे भीड़तंत्र में बदल डालेगी। ध्यान नहीं पड़ता यह भीड़ कभी किसी जन-मुद्दे पर सड़क पर आई हो। भीड़ ने ही कभी भीड़ का विरोध किया हो। हिंसक होते लोगों को कभी समझाने की कोशिश की हो। सहनशीलता का कोई सार्वजनिक संदेश दिया हो।

आपा और सहनशीलता खोते हम जानवर से भी बदतर होते जा रहे हैं। हम अब वह सभ्य मनुष्य या समाज नहीं रह गए हैं, जिसकी परिकल्पना कभी स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बुद्ध ने की थी। हम एक ऐसी हिंसक भीड़ हो गए हैं, जिससे हमें खुद ही डर सताने लगा है। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं किसी अप्रिय घटना का शिकार बनाकर भीड़ हमें ही न निपटा दे। इस डर और भय को गहराई से समझने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आदत बदलने की जरूरत

बेहिसाब दोहन की देन है जल संकट शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. भरत झुनझुनवाला ने जल संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। उनके अनुसार उन क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर में भारी गिरावट आ रही है, वहां चीनी, लाल मिर्च, मेंथा और अंगूर जैसी फसलों का उत्पादन बंद कर देना चाहिए, लेकिन मेरा लेखक से यह सवाल है कि पंजाब में भी भूजल स्तर बहुत गिरता जा रहा है, क्या पंजाब भी चावल की खेती करना बंद कर दें, क्योंकि इस फसल के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? अगर भविष्य में देश के और क्षेत्र भूजल स्तर के गिरने की गिनती में आ गए तो क्या वहां भी दूसरी फसलों के उत्पादन पर रोक लगा दी जानी चाहिए? मेरे खयाल से इससे इस जल संकट का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि उल्टे दूसरी समस्याएं पैदा होने लगेंगी। जल संरक्षण के लिए दूसरे विकल्पों को अपनाने की दरकार है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर नल का प्रयोग करके इन्हें खुला छोड़ देते हैं, जो कि जल की बर्बादी का कारण बनता है। ऐसी छोटी-छोटी लापरवाही भी बहुत से जल को बर्बाद कर देती है। हमें ऐसी छोटी-छोटी गलतियों पर लगाम लगानी होगी।

raju09023693142@gmail.com

दिख रहा सुधार

जम्मू-कश्मीर में हर ओर से सुधार दिख रहा है। अभी सभी विपक्षी दलों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे स्पष्ट है कि सभी दल राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने व पवित्र अमरनाथ यात्रा को पुख्ता सुरक्षा प्रदान करने के पक्ष में हैं। इधर राज्य में सुरक्षा बलों को अच्छी कामयाबी मिल रही है। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। भटके हुए कश्मीरी युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा, रोजगार और विकास को सूबे में अहमियत दी जा रही है। स्कूल कॉलेजों का नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है। यही वजह है कि आज जम्मू-कश्मीर केंद्र सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

दीपक गौतम, सोनीपत

सौहार्द की मिसाल

दिल्ली में मामूली विवाद में लोगों ने धार्मिक रंग दे दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही शामिल रहे। पर खुशी की बात ये रही कि दोनों ही संप्रदायों के जिम्मेदार लोग सामने आए और हालात को शांत करने का भरसक प्रयास किया जो सफल भी हुआ। सांप्रदायिक मतभेदों को दूर करने की ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जहां समाज का प्रबुद्ध वर्ग ऐसे मौकों पर सामने आए और इस तरह की गलतफहमी के कारण उपजे विवादों को बिना पुलिस और कानूनी हस्तक्षेप के दूर करने की कोशिश करे। इसके साथ ही सबको यह विश्वास भी दिलाए कि ये देश सबका है। सबको मिलकर इसे बनाना है और इसमें प्रेम से रहना है।

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

जल संग्रहण

प्रधानमंत्री चार माह बाद फिर रेडियो के जरिये देश की जनता से मुखातिब हुए। इसमें उन्होंने खुलकर अपने मन की बात रखी। जल संरक्षण से शुरू हुई बात 1975 के आपातकाल, उनकी केदारनाथ यात्रा, स्वाध्याय और चुनाव में एनडीए को अपार जन-समर्थन देने के लिए मतदाताओं को बधाई देने तक चली। प्रधानमंत्री मानसून की बेरुखी और देश के ज्यादातर हिस्सों में पेयजल की किल्लत से चिंतित दिखे। 'जन-जन जुड़ेगा, जल बचेगा' नारा अच्छा है, लेकिन इसको चरितार्थ करने के लिए सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। कुछ कड़े फैसले उठाने होंगे। आसमान का अमृत फिर कहीं व्यर्थ न बह जाए। इसके लिए समय कम है। जल संग्रहित न कर पाए तो विकास का दावा बेमानी होगा।

युधिष्ठिर लाल कक्कड़, लक्ष्मी गार्डन, गुरुग्राम

नशे की लत

पश्चिमी देशों के लोग धूम्रपान त्याग रहे हैं, जबकि भारतीय युवाओं में इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। यह बुरी आदत है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे जीवन नरक बन जाता है। भारत में करीब आधी अबादी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब जैसे नशे की आदी है, जिसमें युवतियां भी शामिल हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है।

रवि पांडेय, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2700 प्राकृतिक और 65 हजार मानवनिर्मित छोटी-बड़ी झीलें हैं फिलहाल देश में। इनमें से ज्यादातर शहरीकरण के कारण प्रदूषण की मार झेल रही हैं।

आजकल

पानी बचाने के क्या हैं नए विकल्प

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफएसआइ ग्लोबल से संबद्ध

जल संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार जनशक्ति-जलशक्ति नामक योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें पानी बचाने और उसके इस्तेमाल के नए तौर-तरीकों पर जोर देने की पहल की जानी है, पर यहां अहम सवाल यह है कि झीलों-नदियों के मामले में धनी और मानसून जैसी प्राकृतिक घटना से पानी के मामले में अच्छी तकदीर वाले हमारे देश में पानी को लेकर गंभीर संकट क्यों पैदा हुआ है? साथ ही इस संकट को पानी के नए विकल्पों से कैसे दूर किया जा सकता है?

जल संरक्षण देश में दूसरी बार बनी मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसका खुलासा इधर तब और हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में जल संरक्षण के लिए हर किसी से मिशन मोड में सहयोग करने की अपील की। सरकार इस संबंध में जनशक्ति-जलशक्ति नामक योजना भी शुरू कर रही है, जिसमें पानी बचाने और उसके इस्तेमाल के नए तौर-तरीकों पर जोर देने की पहल की जानी है, पर यहां अहम सवाल यह है कि झीलों-नदियों के मामले में धनी और मानसून जैसी प्राकृतिक घटना से पानी के मामले में अच्छी तकदीर वाले हमारे देश में पानी को लेकर गंभीर संकट क्यों पैदा हुआ है? साथ ही इस संकट को पानी के नए विकल्पों से कैसे दूर किया जा सकता है? ध्यान रहे कि हमारी धरती पर पानी लगभग उसी मात्रा में विद्यमान है, जितना कई लाख साल पहले था और आगे भी इतनी ही मात्रा में बचा रहेगा। कहा जा सकता है कि पानी की उपलब्धता के मामले में पृथ्वी पर ऊपरी तौर पर कोई संकट पैदा नहीं हुआ है, लेकिन गंभीर पड़ताल करें तो पानी की कुछ मुश्किलें साफ नजर आ जाती हैं। असल में पृथ्वी पर मौजूद पानी को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है, साफ पानी के स्रोत घट रहे हैं और बढ़ती आबादी के कारण पानी की खपत में तेज इजाफा हो रहा है। एक बड़ी समस्या यह है कि जिस समुद्र से हमारी दो तिहाई पृथ्वी घिरी हुई है, उसका ज्यादातर पानी खारा (नमकीन) है और पीने योग्य नहीं है। ऐसे में कैसा जल संकट पैदा हो सकता है, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र के लातूर और तमिलनाडु के चेन्नई जैसे इलाके इसकी स्पष्ट गवाही देते रहे हैं।

रुके बेजा खपत

नीति आयोग के मुताबिक दुनिया के मुकाबले भारत की आबादी 17 प्रतिशत है, लेकिन इसी तुलना में साफ पानी सिर्फ 4 फीसद उपलब्ध है। इसमें कोढ़ में खाज वाली स्थिति यह है कि इस उपलब्ध जल का असमान वितरण होता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। भारत में फिलहाल प्रति व्यक्ति 1700 से 1000 क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। वैश्विक पैमानों पर देखें तो प्रति व्यक्ति 1554 क्यूबिक मीटर जल उपलब्धता पानी के भीषण संकट का संकेत मानी जाती है। इस तरह से भारत एक गंभीर जल संकट की तरफ बढ़ते देश में शामिल हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में मौजूद पानी का 84 फीसद खेती में, 12 प्रतिशत उद्योगों में और बाकी बचा चार फीसद घरेलू कार्यों में खर्च होता है। नीति आयोग के आकलन में यह भी कहा गया था कि चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत में खेती के लिए पानी की ज्यादा खपत हो रही है। आंकड़ा यह है कि मुख्य फसल की एक इकाई पैदा करने के लिए जितना पानी चीन-अमेरिका में इस्तेमाल होता है, उससे 2-4 गुना ज्यादा पानी हमारे खेतों में लगता है। यदि खेतीबाड़ी, उद्योग-धंधों और घरेलू इस्तेमाल में उपयोग में ला रहे पानी के वाजिब इस्तेमाल की तकनीकें अपना ली जाएं तो पानी की समस्या को काफी हद तक काबू में किया जा सकता है। इस तरह जो पानी बचेगा, वह दूसरे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि खेती के साथ-साथ घरेलू इस्तेमाल के लिए आज पानी की जरूरतें भूजल यानी बोरवेल और ट्यूबवेल से खींचे गए पानी पर निर्भर हो गई हैं। फिलहाल इस इस्तेमाल के लिए 80 फीसद पानी जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है। जिस तरह से शहरों-कस्बों की आबादी बढ़ रही है, ज्यादा भूजल खींचने की जरूरत पैदा होगी जिससे जलस्तर और नीचे जाना तय है। भूजल की भरपाई यानी उसे रीचार्ज करने की नीतियों (वाटर हार्वेस्टिंग) पर गंभीरता से अमल नहीं होने की सूरत में पानी का यह भविष्य अंधकारमय ही लगता है। यही नहीं, अब जिस तरह से उत्तर भारत में भी ज्यादा पानी खींचने वाली धान और गेहूं की फसलों की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, पानी की उपलब्धता पर असर पड़ना तय है। ऐसे में सवाल है कि अब और पानी कहां से आएगा। इसके लिए फिलहाल जो समाधान सुझाए जा रहे हैं, उनमें से एक यह है कि हिमालय के ग्लेशियरों से पाइप-लाइनें बिछाई जाएं जो उत्तर भारत को पानी सप्लाई करें, पर समस्या यह है कि ग्लेशियरों से गंगा-यमुना नदियों को भी पानी की आपूर्ति में कमी पड़ने लगी है। ऐसी स्थिति में तीन तरफ से समुद्र से घिरे देश के लिए एक बड़ा समाधान सागरों का पानी हो सकता है।

छान लें समुद्रों को

यह सही है कि दुनिया के कई देश पानी के विकल्प के रूप में समुद्रों को बड़ी हसरत से देखते आए हैं, बशर्ते उसके खारेपन को अलग किया जा सके। बड़े पैमाने पर ऐसा मुमकिन हो सके तो अगली कई सदियों तक इंसानों की पानी की जरूरत आसानी से पूरी की जा सकती है, पर समुद्री जल से नमक को छान लेना कभी आसान नहीं रहा। वैसे तो 19वीं सदी के आखिर में यमन और सूडान आदि मुल्कों में समुद्री जल को पेयजल में बदलने का काम शुरू हो गया था, पर आज, जबकि दुनिया में डिसैलिनेशन (समुद्री जल को पीने के पानी में बदलने की प्रक्रिया यानी रिवर्स ऑस्मोसिस) के करीब 16 हजार प्लांट कायम हैं तो भी इनसे इस्तेमाल योग्य पानी की ग्लोबल जरूरत का सिर्फ 0.5 फीसद ही उत्पादित किया जा पा रहा है। इंटरनेशनल डिसैलिनेशन एसोसिएशन के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिदिन 66.5 मिलियन क्यूबिक पानी डिसैलिनेशन के जरिये साफ किया जा रहा है जिससे 300 मिलियन लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट संयुक्त अरब अमीरात में है, जबकि डिसैलिनेशन से मिलने वाले पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इजरायल में होता है जहां घरेलू जरूरतों का 40 फीसद पानी इससे हासिल किया जाता है, पर भूजल, झीलों और तालाबों से मिलने वाले पानी को साफ करके पेयजल में बदलने के मुकाबले समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाना अत्यधिक खर्चीला है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मुख्यतः इसी प्रक्रिया पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके अन्य जलस्रोतों से जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता है। फिलहाल भारत जैसे देश में इस तरह डिसैलिनेशन से मिलने वाले पानी की मौजूदा कीमत 50-55 रुपये प्रति लीटर बैठती है, जो बोतलबंद पानी से कई गुना ज्यादा है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी लागत आगे चलकर कम हो सकती है। इसे कम किया ही जाना होगा, क्योंकि आखिर में हमारे पास समुद्र ही होंगे, जहां पानी होगा।

बचाएं झीलें और तालाब

हमारे देश की झीलें, तालाब, पोखर आदि जलस्रोत भी संरक्षण के हकदार हैं, पर अफसोस कि इन पर इस नजरिये से कोई बड़ी पहलकदमी होते हुए नहीं दिखाई दी है कि ये पेयजल के बहुत बड़े विकल्प हो सकते हैं। हकीकत यह है कि बेंगलुरु मरती हुई झीलों का शहर बन गया है। पिछली सदी में वहां एक-दूसरे से जुड़ी करीब 400 झीलें थीं जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण लगभग खत्म हो गई हैं। इससे जलस्रोतों के प्रति हमारी उपेक्षा दिखती है जो सदियों से हमारे बीच रहे हैं और पानी ही नहीं, जमीन को उपजाऊ बनाने और जलवायु परिवर्तन में उनकी एक निश्चित भूमिका है। कभी शहर-कस्बों की शान कहे जाने वाले तालाब, बावड़ी, झील और वेटलैंड कहे जाने वाले ऐसे ज्यादातर जलस्रोत लोगों की लापरवाही और सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहे हैं। फिलहाल देश में 2700 प्राकृतिक और 65 हजार मानवनिर्मित छोटी-बड़ी झीलें हैं। इनमें से ज्यादातर शहरीकरण के कारण प्रदूषण की मार झेल रही हैं। अगर इन्हें बचाया जा सका तो पानी का यह विकल्प मौजूदा जल संकट का बेहतर समाधान साबित हो सकता है। झीलों, दलदली इलाकों और विशाल तालाबों आदि नम क्षेत्रों को साइंस में वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड न सिर्फ अपने भीतर पानी की विशाल मात्रा सहेजते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आसपास की शुष्क जमीन के लिए पानी भी छोड़ते हैं। यहां तक कि वातावरण की नमी कायम रखने में भी वेटलैंड सहायक साबित होते हैं। इसके अलावा ये जमा हो चुकी गंदगी को छानते हैं और अनेक जलीय तथा पशु-पक्षी प्रजातियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। गंदगी को अपने भीतर समा लेने और उसका संशोधन करने के लिहाज से वेटलैंड आसपास के पर्यावरण के लिए फेफड़े का काम करते हैं।

शहरों में जलयुद्ध के हालात

शहरों की आबादी बढ़ रही है और पेयजल के उनके अपने संसाधन घट रहे हैं, ऐसे में पानी राज्यों के बीच राजनीति और मोलभाव का हथियार बन गया है। हरियाणा को यह बात सख्त नापसंद है कि पड़ोसी राज्य दिल्ली यमुना का सारा पानी पी जाए। पंजाब-हरियाणा और कर्नाटक-तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे के अपने झगड़े हैं, पर दिल्ली के उदाहरणों को सामने रखें तो कहा जा सकता है कि शहरों में किस वजह से पानी का नया संकट पैदा हो जाएगा-इसका अब अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। जैसे एक सालाना परंपरा के रूप में यमुना नदी में अचानक बढ़ने वाली अमोनिया की मात्रा दिल्ली जल बोर्ड के जलशोधन संयंत्रों को बंद करने पर मजबूर कर देती है। असल में ये जलशोधन संयंत्र तभी तक पानी साफ करते रह सकते हैं, जब तक कि नदी से उन्हें मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा तय स्तर से ऊपर न जाए। इसके लिए व्यवस्था यह है कि यमुना नदी में मिलने वाले नालों के पानी में प्रदूषण कम हो, लेकिन इसकी शर्तें तय होने के बावजूद दिल्ली के नजदीक पानीपत में यमुना में मिलने वाले नाले अत्यधिक प्रदूषित हैं। इससे यमुना में अमोनिया खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। पानी का यह ऐसा संकट है जिसके बारे में आज कोई बड़ा शहर गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसे नजारे वहां उपस्थित नहीं होंगे। मुद्दा सिर्फ सरकारों या लोगों का रवैया नहीं है, बल्कि यह भी है कि आखिर शहरों ने पानी के कैसे भी संकट से निपटने के क्या इंतजाम किए हैं और शहरवासी खुद पानी की सार-संभाल को लेकर कितने चिंतित हैं?

शहरों में आम लोगों द्वारा बर्बादी के अलावा पानी के वितरण की नाकाम व्यवस्थाएं, सप्लाई में लीकेज और पानी की चोरी जैसी समस्याएं गंभीर स्थितियां तो पैदा कर ही रही हैं। साथ में बारिश के पानी को जमा करने और भूजल रिचार्ज करने वाली तकनीकों पर गंभीरता से अमल न करके पानी को राजनीति का टूल बनने का मौका दिया जा रहा है। अगर यमुना पर बांध और बैराज बनाकर एवं बारिश के पानी को सहेजकर रखा जाए तो संकट के दिनों में दिल्लीवासियों को छह महीने तक पानी की सप्लाई आराम से हो सकती है। दिल्ली इस मामले में अकेला उदाहरण नहीं है, बेंगलुरु से लेकर अहमदाबाद और सूरत से लेकर कानपुर-तकरीबन हर बड़े शहर में पानी को बचाने एवं सहेजने के बारे में एक-सा लापरवाह रवैया अपनाया गया है। भविष्य में ऐसे संकट न हों, इसके लिए जरूरी है कि हर गांव और शहर के हर घर में पानी के संरक्षण के लिए वहां की परिस्थितियों के अनुसार जल संग्रहण का काम होना चाहिए।

खरी-खरी

इस्तीफा दे दो सजना...!

डॉ. पिलकेंद्र अरोरा

प्राणेश्वरी आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। बोलो, क्या चाहिए? विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर पति ने पत्नी से कहा। आर्य! मैं चाहती हूं आप भी इस्तीफा दे दें! इस्तीफा! किस बात का इस्तीफा और किस पोस्ट से! पति ने आश्चर्य से कहा। पूरे देश में इस्तीफों की बाढ़-सी आई है! एक ठो इस्तीफा आप भी दे दीजिए। मेरे लिए तो यही आपका गिफ्ट होगा! मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगी!

क्या तुम यह कहना चाहती हो कि पिछले 25 वर्षों में मैंने पति पद पर ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य नहीं किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आर्य! मैं तो बस इतना चाहती हूं कि यदि आपका प्रेम सच्चा और पवित्र है, तो आप आज इस शुभ दिन पर ही इस्तीफा दे डालिए। क्या आप मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते? पर मैडम यह तो बताइए कि मैं इस्तीफा कहां से और कैसे दूं? न तो मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूं! न मैंने कभी क्रिकेट के बैट का 'सदुपयोग' ही किया है। न ही मैं किसी 'अंधेर नगरी का चौपट राजा' हूं! तो मैं इस्तीफा दूं तो किस आधार पर?

देखो जी, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। जब सब दे रहे हैं तो आपको देने में हर्ज क्या है? आपको मेरी कसम! देखिए, नाथ मैंने जीवनभर आपसे कुछ नहीं मांगा। कभी नहीं कहा कि मेरे लिए आकाश से चांद-तारे तोड़ कर लाओ! या मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ले चलो! या मेरी मांग इटली के मोतियों से भर दो! बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए।

इस्तीफा! इस्तीफा! इस्तीफा! बंद करो ये बकवास! आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आज हमारी शादी की गोल्डन जुबली है और तुम इस्तीफे की रट लगाए हो, बिना यह जाने कि इस्तीफा किसी पद से दिया जाता है, और वह भी नैतिक आधार पर! भागवान! मैं क्या मेरे खानदान में आज तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया! कभी कोई किसी पद पर रहा ही नहीं तो देता कैसे? और इसी वजह से हमारा नैतिक आधार आज भी सुरक्षित है! हां, अगर मैं किसी जहाज का कप्तान होता और मेरे कारण वह जहाज डूबने वाला होता, तो मैं अवश्य ही इस्तीफा दे देता! ये बात और है कि वह स्वीकारा नहीं जाता। इसलिए अब तुम ही बताओ प्राणप्रिये कि मैं तुम्हारी यह त्रियाहठ कैसे पूरी करूं?

ट्वीट-ट्वीट

मंदिरों के तोड़े जाने की कहानियां हम अपने पुरखों से सुनते रहे, इतिहास में पढ़ते रहे, पर हमारा वर्तमान हमारा इतिहास कैसे बनता है, दुर्गा मंदिर की घटना इसका जीवंत साक्ष्य है।

मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

मैं गैर-मुस्लिम से नुसरत जहां की शादी का समर्थन करती हूं। अंतर-धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं नुसरत के सिंदूर और बदले सरनेम का समर्थन नहीं करती। सिंदूर विवाह का प्रतीक है। उनके पति ने विवाह के बाद कोई प्रतीक नहीं धारण किया तो फिर उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए।

तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

मुंबई में एयरपोर्ट रनवे बंद है, स्कूल बंद हैं, रेलवे स्टेशन पानी में डूब गए हैं, लेकिन मेरे घर में अखबार वक्त पर पहुंचा और वह भी एकदम सूखा। मैं उन गुमनाम नायकों को सलाम करता हूं जो भारी बारिश के बावजूद हमें एक सामान्य दिन होने का आभास करा सकते हैं।

आनंद महिंद्रा@anandmahindra

क्या यूपी से सबक लेगी बिहार सरकार?

रंजन राजन
वरिष्ठ पत्रकार

बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में चमकी बुखार (एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम) से डेढ़ सौ से अधिक बच्चों की अकाल मृत्यु के बाद पटना से दिल्ली तक मची हलचल सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रिया है। मौत की जिम्मेदारी से बचने की राजनीतिक कोशिशों और मातम से टीआरपी बटोरने की मीडिया की आपाधापी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित याचिका को स्वीकार कर राज्य और केंद्र सरकारों को तलब किया है। अब सरकारें अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए चाहे जो जवाब दें, पर हकीकत यही है कि मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बीते करीब दो दशक से हर साल बच्चे विभिन्न बुखार से बेमौत मर रहे हैं। आंकड़ा जिस साल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, शोर ज्यादा सुनाई देता है, जिस साल कम रहता है, आवाज दब जाती है। बावजूद इसके इससे बचाव और उपचार के विशेष सरकारी उपाय इलाके में कहीं नजर नहीं आते। मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक में जरूरी संसाधनों का अभाव दुखदायी है।

रहस्यमयी बुखार के चलते दो साल पहले तक इससे भी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के जिलों में थी, लेकिन वहां अब स्थिति पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया है। इस कामयाबी को आप आंकड़ों के आईने में देख सकते हैं। गोरखपुर के आसपास कुल 14 जिलों में 2017 में रहस्यमयी बुखार के 2,247 मामले सामने आए थे, जिनमें 511 बच्चों की मौत हो गई थी। 2017 के अंत में इससे निपटने के गंभीर प्रयास शुरू हुए। इससे 2018 में मौत का आंकड़ा काफी कम हो गया। कुल 1047 मामले सामने आए, जिनमें 166 बच्चों की मौत हुई। और इस साल अब तक सिर्फ 82 मामले सामने आए हैं, जिनमें 20 बच्चों की मौत हुई है। यूपी सरकार की इस कामयाबी को पिछले दिनों यूनिसेफ तक ने सराहा है।

यह इस बात का सुबूत है कि सरकार यदि इच्छाशक्ति दिखाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। हैरानी की बात यह है कि बिहार सरकार ने अपने पड़ोसी राज्य में उठाए गए कदमों से अब तक कोई सीख नहीं ली! यहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे कुछ कदमों की चर्चा करना प्रासंगिक होगा, जिनसे सीख लेकर बिहार सरकार भी इस अभिशाप को नियंत्रित कर सकती है।

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है। इसलिए इस इलाके में रहस्यमयी बुखार के साथ-साथ डेंगू, कालाजार, मलेरिया और चिकनगुनिया आदि से हर साल हो रही मौतों से वे अच्छी तरह वाकिफ थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने इससे निपटने की इच्छाशक्ति दिखाई। उनके निर्देश पर कई विभागों ने साथ मिलकर समेकित कार्ययोजना तैयार की। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास, पंचायती राज और नगर विकास विभाग की टीमों ने इलाके में एक साथ स्वच्छता से लेकर साफ पेयजल की उपलब्धता तक और जागरूकता से लेकर टीकाकरण अभियान तक के कार्यक्रम चलाए। पूरे पूर्वांचल में इंसेफलाइटिस के रिकॉर्ड टीकाकरण हुए, जिनमें करीब 40 लाख बच्चों को कवर किया गया। गोरखपुर और बस्ती मंडल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ-साथ एक लाख से अधिक स्थानीय लोगों को भी रहस्यमयी बुखार के विशेष उपचार से संबंधित ट्रेनिंग दी गई।

गोरखपुर के सबसे बड़े अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफलाइटिस के लिए बेड की संख्या 268 से बढ़ा कर 428 की गई। यहां आधुनिक वेंटिलेटर लगाए गए। सरकार ने यह भी प्रयास किया कि मरीजों को सीधे गोरखपुर आने की जरूरत न पड़े। इसके लिए ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक 104 इंसेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर (ईटीसी) की स्थापना की गई। यहां पेशेंट ऑडिट का फॉर्मूला लागू किया गया, जिसने सरकारी सिस्टम को कार्य करने पर मजबूर किया। हर जिला अस्पताल में 10 से 15 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया। प्रत्येक सीएचसी में भी कम-से-कम 3 बेड का आइसीयू/ एनआइसीयू स्थापित कर वहां योग्य चिकित्सकों की तैनाती की गई, ताकि स्थानीय स्तर पर भी बेहतर इलाज मिल सके। हर आशा कार्यकर्ता को नकद इनाम मिलता है, यदि वह अपने इलाके के किसी मरीज को ढूंढकर अस्पताल पहुंचा देती है।

स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संबंधित विभागों ने साथ मिलकर युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। गांवों और शहरों में लार्वीसाइड छिड़काव और जल स्रोतों के क्लोरीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। शहरी क्षेत्र में गंदगी से निपटने किए नगर निगम और नगर पालिका के द्वारा कूड़ा प्रबंधन की शुरुआत की गई। रहस्यमयी बुखार के रोगियों की पहचान के लिए प्रदेश में 19 सेंटीनल सर्विलांस प्रयोगशाला और स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में सेंटीनल प्रयोगशाला की स्थापना की गई। बीमारी के कारकों की पहचान के लिए विशेष परीक्षण के लिए केजीएमयू, एसजीपीजीआइ लखनऊ में और एनआइवी पुणे की फील्ड यूनिट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में स्थापित की गई।

इन ठोस उपायों के साथ ही राज्य सरकार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और डॉक्टरों को चेतावनी भी जारी की, ताकि बीमारी से निपटने के उपायों में कोई कोताही न हो। इस तरह महामारी का रूप ले चुकी बीमारी को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली, लेकिन क्या बिहार सरकार ऐसे उपायों पर अब भी ध्यान देगी या बरसात के साथ बीमारी का प्रकोप कम होते ही फिर बेफिक्र हो जाएगी और अगली गर्मी में भी हम ऐसी ही पीड़ा से गुजरेंगे?

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद पानी बचाने को लेकर लोग गंभीर होंगे?

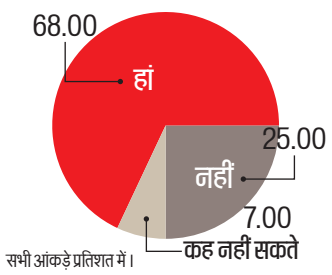

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या विश्व कप टीम के लिए विजय शंकर के स्थान पर मयंक अग्रवाल का चयन सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पानी-पानी हो रहे कई शहर अरु ग्राम,
फिर भी पानी के लिए तरसे मानुष आम।
तरसे मानुष आम धरा को गया निचोड़ा,
अब कुदरत का आप झेलिए प्रबल हथौड़ा।
ना सुधरे तो और जायगी बिगड़ कहानी,
संततियों को आप कहां से देंगे पानी?

-ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

विकृतियों के महिमामंडन से बचे सिनेमा

पीयूष द्विवेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

सिनेमा यदि समाज से प्रभावित होकर बनता है तो उसका प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। ऐसे में फिल्म निर्माताओं का सामाजिक दायित्व है कि वे फिल्मों में समाज की विसंगतियों का महिमामंडन करने के बजाय उनसे मुक्ति का मार्ग दिखाने की कोशिश करें

हाल के वर्षों में हिंदी सिनेमा में फिल्मों के पुनर्निर्माण (रीमेक) का चलन बढ़ा है। आए दिन किसी न किसी विदेशी या दक्षिण भारतीय फिल्म के पुनर्निर्माण की खबरें आती रहती हैं। खास बात यह है कि इस तरह की फिल्में कामयाब भी हो रही हैं। इन दिनों एक ऐसी ही पुनर्निर्मित फिल्म 'कबीर सिंह' की चर्चा है। यह अगस्त 2017 में आई तेलुगु भाषी फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का पुनर्निर्माण है। हर विषय की तरह कबीर सिंह को लेकर भी सोशल मीडिया दो खेमों में बंट गया है। एक खेमा जहां फिल्म को नारी-विरोधी, मर्दवादी, अति-हिंसक जैसे विशेषणों से नवाजते हुए निशाने पर लिए बैठा है, वहीं दूसरा खेमा शाहिद कपूर के अभिनय की तारीफ करते हुए फिल्म की तारीफ में डूबा है। दोनों खेमों के अपने-अपने तर्क और दलीले हैं। इस समर्थन और विरोध को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर 'कबीर सिंह' फिल्म का विषय और सामग्री क्या है।

फिल्म की कहानी की बात करें तो इसका नायक 'कबीर सिंह' बेहद अहंकारी, गुस्सैल और एक हद तक सनकी किस्म का व्यक्ति है। पेशे से सर्जन है। अपनी पढ़ाई के दौरान एक लड़की से उसे पहली नजर में ही प्रेम हो जाता है तो वह बिना उस लड़की को जाने-पहचाने 'ये मेरी बंदी है' के रूप में अपने प्रेम का सार्वजनिक एलान कर देता है। फिर उस लड़की पर जरूरत से ज्यादा हक जताने लगता है। उस पर चिल्लाता है, गाली-गलौज करता है और हाथ तक उठा देता है। बावजूद इसके वह लड़की भी उससे प्रेम करने लगती है और उसकी सब ज्यादतियां सहती रहती है। मगर लड़की के पिता उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं जिसके बाद कबीर सिंह भारतीय सिनेमा के पारंपरिक नायकों के मार्ग का अनुसरण करते हुए नशे में डूबकर खुद को बर्बाद करने लगता है। मोटे तौर पर फिल्म की कहानी इतनी ही है।

इसमें नायक और नायिका दोनों का जो चरित्र-चित्रण किया गया है, वह अनेक सवालों को जन्म देता है। यह ठीक है कि 'तेरे नाम', 'रहना है तेरे दिल में' आदि कई फिल्मों में पहले भी गुस्सैल और सनकी नायक

हमने देखे हैं, लेकिन कबीर सिंह उन सबकी सीमाओं को तोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ जाता है। फिल्म की पूरी कहानी केवल कबीर सिंह के मर्दवादी चरित्र को महान बनाने की ओर समर्पित है। नायिका के प्रति उसकी समस्त ज्यादतियों को फिल्म प्रेम की आड़ लेकर सही ठहराने की कोशिश करती है। हालांकि वह प्रेम पूरी फिल्म में कहीं नजर नहीं आता। नजर आता है तो केवल कबीर सिंह का सनकीपन, गुस्सा और कहीं-कहीं असभ्य कामातुर स्वभाव, मगर इन सब विसंगतियों के बावजूद फिल्म कबीर सिंह के पक्ष में खड़ी रहती है।

शराब और ड्रग्स के नशे में भयंकर ढंग से डूबे कबीर सिंह के महिमामंडन में भी फिल्म नहीं चूकती। यहां तो वह नैतिकता के साथ-साथ तर्कों को भी तिलांजलि दे देती है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण फिल्म का वह हिस्सा है, जिसमें कबीर सिंह के नशे की हालत में सफल सर्जरी करने की बात सामने आती है। प्रेम में असफल नायक का नशे में डूब जाना भारतीय सिनेमा के लिए कोई नई बात नहीं है, मगर उसका ऐसा महिमामंडन शायद पहली बार ही हुआ है। फिल्म के ज्यादातर हिस्सों में नायक के समक्ष नायिका की स्थिति डरी-सहमी और बेहद दयनीय ही रही है। वह कभी कबीर सिंह की ज्यादतियों का गंभीरतापूर्वक और सख्ती से प्रतिवाद नहीं कर पाती। सवाल उठता है कि एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा, जिसका तेज-तर्रार और तार्किक होना अपेक्षित है, इतनी दीन-हीन और भावुक कैसे हो सकती है? मगर कबीर सिंह के चरित्र को प्रभावशाली दिखाने की लालसा ही है कि नायिका को इतना दयनीय बना दिया गया है।

हालांकि इन सब बातों के आधार पर तमाम नारीवादियों द्वारा जिस तरह से फिल्म को नारी-विरोधी का तमगा दिया जा रहा, वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि यदि सिनेमा को नारीवाद और पुरुषवाद के चश्मे देखा जाने लगा तो हर फिल्म में ही किसी न किसी प्रकार की समस्या नजर आएगी। इसी तरह इस फिल्म के समर्थकों की यह दलील कि अबसे पहले भी फिल्मों में नशा और हिंसात्मकता का चित्रण हुआ है अतः 'कबीर सिंह' में कुछ गलत नहीं है, भी बेतुकी ही प्रतीत होती है। निश्चित ही अनेक फिल्मों में ये सब चीजें दिखाई गई हैं, मगर उनका ऐसा महिमामंडन नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर 'देवदास' में ज्यादा शराब पीने के कारण देवदास की मौत हो जाती है, न कि वह सफल सर्जरी करने लगता है।

अब सवाल यह उठता है कि इतनी विसंगतियों के बावजूद यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल कैसे हो रही है? इसका एक कारण तो यह है कि फिल्म को विवादों का भरपूर लाभ मिला है। इसके अलावा वर्तमान युवाओं में प्रेम को लेकर परिपक्व समझ का भारी अभाव है। प्रेम में लड़की के 'ना' कर देने पर उसे नुकसान पहुंचाने या खुद को खत्म कर लेने वाली नासमझ मानसिकता दबे-छिपे रूप में युवाओं में मौजूद है। कबीर सिंह इसी तरह की मानसिकता को संतुष्ट करने वाला नायक है, जिसके प्रति युवाओं का आकर्षण स्वाभाविक है। बहरहाल फिल्म-निर्माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि सिनेमा यदि समाज से प्रभावित होकर बनता है तो उसका प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। ऐसे में फिल्म-निर्माताओं का सामाजिक दायित्व है कि वे फिल्मों में समाज की विसंगतियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने और उनका महिमामंडन करने के बजाय उन विसंगतियों से मुक्ति का मार्ग दिखाने की कोशिश करें।

जून में सोने का आयात 12.6 फीसद बढ़ा

नई दिल्ली : सरकारी सूत्रों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत में उछाल के बीच जून में भारत का स्वर्ण आयात साल-दर-साल आधार पर 12.6 फीसद बढ़कर 2.69 अरब डॉलर (करीब 186 अरब रुपये) पर पहुंच गया। जून का आयात हालांकि मई के 4.78 अरब डॉलर के मुकाबले 44 फीसद कम है। (प्रेटू)

भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। नोटबंदी का भारत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है।
— निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

सेंसेक्स	39,816.48 ▲ 129.98	निफ्टी	11,910.30 ▲ 44.70	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 34,120 ▼ ₹20	चांदी प्रति किलोग्राम	₹38,500 ▼ ₹70	$ डॉलर	₹68.95 ▲ ₹0.01	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$63.44

कारपोरेट हलचल

एनबीसीसी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एनबीसीसी ने शरीर मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग उत्सव का आयोजन किया। कंपनी के नई दिल्ली स्थिति निगमित कार्यालय में आयोजित योग दिवस पर निदेशक (वाणिज्य) राजेंद्र चौधरी, सीवीओ संजीव स्वरूप और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

जापान-भारत में कौशल विकास

जापान और भारत के बीच कौशल विकास पर रणनीतिक चर्चा हुई। इससे भारत में निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं। दोनों देशों के बीच बनी इस सहमति में सरकार के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय की अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस संदर्भ में जापान के राजदूत केंजी हिरामात्सु ने केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात की।

सीडब्ल्यूसी में योग दिवस

केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के कॉरपोरेट कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कंपनी के निदेशक (कार्मिक) आरके सिन्हा की उपस्थिति में अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में सक्रियता से भाग लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य के प्रति योग का महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी।

नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 'इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग' विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एक सरकार की तरफ से चलाये जा रहे अभियान की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू मुख्य अथिति के तौर पर उपस्थित हुए। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत भी मौजूद थे।

पश्मीना पर बीआइएस की बैठक

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने पिछले दिनों श्रीनगर में पश्मीना के कारोबार और उससे संबंधित सभी पक्षों के साथ एक बैठक की। बैठक क्राफ्ट डवलपमेंट इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी (आइआइसीटी) के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस क्षेत्र से जुड़े सभी संगठनों के करीब 70 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

सेफ्टी अधिकारी सम्मेलन

एनटीपीसी दादरी में 34वें सेफ्टी अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 25 जून को निदेशक (प्रचालन) प्रकाश तिवारी ने दीप प्रज्जवलित करके किया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक (सेफ्टी) पीके सिन्हा, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (डीबीएफ एंड ह्राइड्रो) आरएस राठी और मुख्य महाप्रबंधक अपूर्व कुमार दास उपस्थित थे। सम्मेलन में एनटीपीसी के केंद्रीय कार्यालय सहित विभिन्न परियोजनाओं व स्टेशनों से आये 63 सेफ्टी अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

एनएसआइसी के प्रयासों की सराहना

पर्यटन मंत्रालय में महानिदेशक सत्यजीत रजन ने पिछले सप्ताह नेशनल स्माल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन (एनएसआइसी) के लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने एनएसआइसी की तरफ से एमएसएमई सेक्टर के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन एके श्रीवास्तव भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

आइएसटीएम (डीओपीटी) की निदेशक डॉ. सुनीता एच खुराना ने डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिसिटी) हरेंद्र प्रताप सिंह को कार्यशाला में शामिल होने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किया। यह कार्यशाला इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेट्रियट टीआरआइ ने पॉलिसी फॉरमेशन टू लेजिसलेशन के प्रोसेस को लेकर आयोजित की गई थी।

19वां रीजनल एबिलिंपिक्स दिल्ली में 4-5 जुलाई को

नई दिल्ली (वि) : रोजगार के मामले में दिव्यांगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ नॉर्थ जोन एबिलिंपिक्स का 19वां संस्करण चार और पांच जुलाई को आयोजित किया जा रहा है।

हाउसिंग सेक्टर पर हो सकती है खास इनायत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर इस बार बजट में खास नजर-ए-इनायत हो सकती है। सरकार की तरफ से हाउसिंग उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को साफ तौर पर संकेत दिया गया है कि इस क्षेत्र में मांग को बढ़ाने के कई उपाय किये जाएंगे। खास तौर पर वर्ष 2022 तक हर परिवार को उसका अपना मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सस्ती आवासीय इकाइयों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इस बारे में सरकार की गंभीरता का पता इस बात से चलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में रियल एस्टेट उद्योग के साथ तीन बैठकें हो चुकी हैं।

सरकार के साथ अपनी मांगों पर चर्चा करने वाले रियल एस्टेट के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें इस बात का पक्का आश्वासन मिला है कि समूचे हाउसिंग सेक्टर की मंदी को दूर करने के लिए समग्र तौर पर उपाय किये जाएंगे। सिर्फ बजटीय घोषणाएं नहीं होंगी बल्कि इस सेक्टर के समक्ष फंड की दिक्कत को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से भी घोषणाएं होंगी। सरकारी एजेंसियां और उद्योग जगत मिलकर इस वर्ष के अंत तक रियल एस्टेट सेक्टर की मंदी को दूर करने की कोशिश करेंगे।

बजट की तैयारियों में जुटे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को रियल एस्टेट सेक्टर के संस्थान क्रेडाई ने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें होम लोन पर ब्याज को आयकर छूट की मौजूदा स्तर दो लाख को बढ़ा कर चार लाख करने की मांग सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरी मांग है, सस्ते मकान उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। क्रेडाई के चेयरमैन जक्षय शाह का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर नोटबंदी की मार से उबर चुका है। जीएसटी को लेकर जो दिक्कतें पैदा हुई थीं वे भी तकरीबन सुलझ गई हैं। रेरा को लेकर भी कोई संशय नहीं है और सभी इसे सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से बजट में मिलने वाला थोड़ा सा सहयोग पूरे आवासीय सेक्टर को मंदी से निकालने वाला साबित हो सकता है। यह सेक्टर एक साथ सीमेंट, स्टील समेत आवासीय उपकरण बनाने वाले उद्योग को नई तेजी से दे सकता है जो अभी मंदी से जूझ रहा है।

बजट से उम्मीद : सरकार का सस्ती आवासीय इकाइयों को बढ़ावा देने पर जोर

मंदी से गुजर रहा है देश का रियल एस्टेट सेक्टर। प्रतीकात्मक

सरकार के सामने विकल्प

- हाउसिंग लोन ब्याज पर कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी
- रियल एस्टेट सेक्टर को ढांचागत उद्योग का दर्जा
- एनबीएफसी की फंड की दिक्कत दूर करने के लिए विशेष उपाय
- कंपनियों को जमीन खरीदने के लिए भी बैंकों से मिले कर्ज

क्यों चाहिए मदद

- वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराना है लक्ष्य
- एनबीएफसी से रियल एस्टेट कंपनियों को नहीं मिल रहा कर्ज
- देश की अर्थव्यवस्था में 7.5 फीसद हिस्सा है
- सीधे तौर पर तकरीबन 7 करोड़ लोगों को मिलता है रोजगार
- तकरीबन 5 लाख अनबिके मकान खरीददार के इंतजार में

मुद्दा ▶ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया जवाब

सरकार ने नोटबंदी के प्रभाव पर नहीं किया कोई अध्ययन

निर्मला सीतारमण ने कहा, नोटबंदी का भारत पर नहीं पड़ा कोई बुरा प्रभाव

नई दिल्ली, एएनआइ : नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा रोजगार पर क्या असर पड़ा यह जानने के लिए सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में की गई नोटबंदी को लेकर काफी विवाद हुआ है।

विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि नोटबंदी के कारण देशी की विकास दर को दो फीसद का नुकसान पहुंचा है और लघु उद्योगों तथा अनौपचारिक क्षेत्र पर इसने अत्यधिक बुरा असर डाला है। सरकार हालांकि इन आरोपों को खारिज करती रही है। सरकार का कहना है कि इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा है। राज्यसभा में एक अन्य जवाब में सीतारमण ने कहा कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और नोटबंदी का भारत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। 2018-19 में विकास दर में जो गिरावट आई, उसका कारण यह है कि उस दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण संबंधी सेवा क्षेत्र और लोक प्रशासन व रक्षा क्षेत्रों में सुस्त विकास हुआ। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास सरकार की कार्यसूची में काफी ऊपर है। जीडीपी के विकास के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कई कदम उठा रही है।

बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट : निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक बैंक घोटाले में कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष में ऐसे घोटालों की संख्या 6,735 रही। इन मामलों में 2,836 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। इससे एक साल पहले ऐसे 9,866 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 4,228 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था।

वित्त मंत्री आरबीआइ के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगी। पारंपरिक रूप से वित्त मंत्री बजट पेश करने के बाद आरबीआइ के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करते हैं। इस दौरान आर्थिक मुद्दों और वित्तीय नीति से जुड़े फैसलों पर चर्चा होगी।

1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के हुए विलफुल डिफॉल्ट्स

मुंबई : निर्मला सीतारमण ने संसद में दिए एक लिखित जवाब में कहा कि सरकारी बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपये (21.76 अरब डॉलर) के लोन को विलफुल डिफॉल्ट श्रेणी में डाला। इसमें भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई है।

भारत ने टैक्स चोरी पर ओईसीडी समझौते को मंजूरी दी

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कहा कि टैक्स चोरी पर ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की परियोजना को लागू करने से जुड़े बहुपक्षीय समझौते को भारत ने मंजूरी दे दी। द्विपक्षीय कर समझौतों के लिए इससे जुड़े प्रावधान 2020-21 से प्रभावी होंगे।

कृषि निर्यात बढ़ाने को सहकारी क्षेत्र निर्यात प्रोमोशन फोरम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सहकारी क्षेत्र निर्यात प्रोमोशन फोरम के गठन का निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा मंगलवार को एक संयुक्त प्रेसवार्ता में की। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 तक मौजूदा निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) में कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन फोरम का गठन किया जाएगा, जो देश के 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने के लिए काम करेगा। सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहकारी ट्रेड फेयर का 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन किया जा रहा है। देश में कुल आठ लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। देश के 15 करोड़ किसानों में से 94 फीसद किसान कम से कम एक सहकारी संस्था के सदस्य हैं। गोयल ने कहा कि इसके बावजूद कृषि उत्पादों की निर्यात में हिस्सेदारी बहुत कम है। इसे प्रोत्साहित करने की सख्त जरूरत है, जिसके लिए सहकारिता ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है।

गोयल ने कहा कि कृषि निर्यात से किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसी मकसद से विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय कॉपरेटिव ट्रेड फेयर से अपनी सहकारी संस्थाओं को विदेशी ग्राहकों की जरूरत का पता चलेगा। इस फेयर का आयोजन वाणिज्य, कृषि और विदेश मंत्रालय सहकारी संस्थाओं के सहयोग से कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सहकारिता कृषि क्षेत्र की रीढ़ है, जिसे मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैठ बनानी होगी। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब एक विभाग के मंत्री और अफसरों का दूसरे मंत्रालयों के अफसरों से सामंजस्य नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तोमर ने कहा कि घरेलू कृषि उपज की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने की जरूरत है। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए इसकी महती आवश्यकता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

- 11 से 13 अक्टूबर को प्रगति मैदान में होगा अंतरराष्ट्रीय सहकारी ट्रेड फेयर
- वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का है सरकार का लक्ष्य

प्रतीकात्मक

ऊर्जा व आइटी शेयरों में खरीदारी से दूसरे दिन भी उछले बाजार

मुंबई, प्रेटू : ऑयल एंड गैस, आइटी और वित्तीय शेयरों में खरीदारी बढ़ने से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन देश के शेयर बाजारों में उछाल दर्ज किया गया। बीएसई का सेंसेक्स 129.98 अंकों की तेजी के साथ 39,816.48 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 44.70 अंकों की तेजी के साथ 11,910.30 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में ओएनजीसी में सर्वाधिक 2.89 फीसद तेजी रही। एचडीएफसी, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और एचसीएल टेक में भी एक फीसद से अधिक तेजी रही। दूसरी ओर यस बैंक में सर्वाधिक 7.60 फीसद की गिरावट रही। ऐसी चर्चा है कि मुंबई की एक रियल्टी कंपनी ने बैंक से लिए 1,200 करोड़ रुपये के एक लोन की किस्त को चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया है। टाटा मोटर्स और सन फार्मा दो फीसद से अधिक लुढ़के। इंडसइंड बैंक में 1.17 फीसद गिरावट रही।

एशियाई बाजारों का मिला-जुला प्रदर्शन : एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में शंघाई, हांगकांग, टोक्यो और सियोल के बाजारों का मिला-जुला प्रदर्शन रहा। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव देखा गया।

कॉक्स एंड किंग्स में गिरावट जारी

नई दिल्ली : ट्रैवल सर्विस कंपनी कॉक्स एंड किंग्स में मंगलवार को भी गिरावट जारी रही। कंपनी के शेयर बीएसई पर 4.91 फीसद गिरकर निचले सर्किट पर पहुंच गए और 32.95 रुपये पर बंद हुए।

इकरा के सीईओ को जबरन छुट्टी देने पर शेयर तीन फीसद लुढ़के

नई दिल्ली : रेटिंग एजेंसी इकरा के शेयर बीएसई पर 3.19 फीसद गिरकर 3,115.55 रुपये पर बंद हुए। एजेंसी ने पूंजी बाजार नियामक सेबी द्वारा उठाए गए मुद्दे की चल रही जांच को देखते हुए अपने एमडी और सीईओ नरेश टक्कर को जबरन छुट्टी पर भेज दिया है।

एनक्लैट की अगली सुनवाई में जेपी इन्फ्रा के लिए एनबीसीसी की बोली में हो सकता है संशोधन

नई दिल्ली, प्रेटू : दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के कर्जदाताओं द्वारा एनबीसीसी की बोली को खारिज किए जाने के बाद नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने मंगलवार को बैंकों, घर खरीदारों और अन्य पक्षों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे 17 जुलाई को उसके समक्ष उपस्थित हों। उस दौरान वे घर खरीदारों के हित के लिए बोली में जरूरी संशोधन की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

एनक्लैट को बताया गया कि एनबीसीसी को बोली पर किए गए मतदान में 34.75 फीसद घर खरीदारों ने बोली के पक्ष में मत दिया। 1.44 फीसद ने विरोध में मतदान किया, जबकि 23.8 फीसद ने मत नहीं दिया। हालांकि सभी 13 बैंकों ने जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करने के लिए जमा की गई एनबीसीसी की बोली के विरोध में मतदान किया। कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) में बैंकों का 40.75 फीसद प्रतिनिधित्व है। मतदान 31 मई को शुरू हुआ था और 10 जून को समाप्त हुआ। सीओसी में घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करीब 60 फीसद है।

मामले की सुनवाई में एनक्लैट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस चरण में वह अडानी समूह की बोली पर विचार नहीं करना चाहती। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसका मुख्य ध्यान घर खरीदारों के हितों का ध्यान रखना है। पीठ ने विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अगली सुनवाई में उपस्थित रहें। अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि सभी पक्षों और खासकर घर खरीदारों के लाभ के लिए एनबीसीसी की बोली में क्या संशोधन किया जा सकता है।

प्रतीकात्मक

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई

नई दिल्ली : जेपी इन्फ्राटेक से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि कंपनी को संपत्ति बिक्री (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया में नहीं भेजा जाए। क्योंकि इससे घर खरीदारों को भारी नुकसान होगा। गौरतलब है कि कंपनी के लिए कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया की समय सीमा खत्म हो चुकी है।

समस्या

आर्थिक सुस्ती के कारण लोगों की खरीदने की क्षमता में गिरावट आई है, वित्तीय संस्थानों से ऑटो लोन मिलना हुआ कठिन, उत्सर्जन/ सुरक्षा मानकों का अनुपालन और तेल की ऊंची कीमतों ने भी बढ़ाई मुश्किल

कई दबावों ने खस्ता कर दी ऑटो सेक्टर की हालत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आर्थिक सुस्ती, ऑटो लोन में सख्ती, महंगे तेल तथा उत्सर्जन व सुरक्षा मानकों के अनुपालन से लागत और कीमतों में बढ़ोतरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की हालत खराब कर दी है। हताश उद्योग अब बजट से आस लगाए बैठा है। जहां से उसे उम्मीद है कि उसकी मुश्किलें कम करने के कुछ न कुछ उपाय अवश्य किए जाएंगे।

वैसे तो ऑटोमोबाइल की मौजूदा हालत की कई वजहें हैं। परंतु परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूदा आर्थिक सुस्ती को सबसे बड़ा कारण मानते हैं। इसकी शुरुआत पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ही हो गई थी, जब भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के आंकड़े सामने आए थे। उसका असर लोगों की क्रय शक्ति के साथ एफएमसीजी उत्पादों के और वाहनों की बिक्री पर सबसे ज्यादा पड़ा है।

दूसरी प्रमुख वजह उत्सर्जन और सुरक्षा के नए सख्त मानकों को लागू करने की विवशता है। परिणामस्वरूप वाहन निर्माण की लागत बढ़ी है और इसकी भरपाई के लिए कंपनियों को मजबूरन वाहनों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के मुताबिक नए मानकों को पूरा करने में उद्योग को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। उत्पादन लागत बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के कारण भी बीते महीनों लोगों में वाहन खरीद को टालने की प्रवृत्ति दिखाई दी।

ग्राहक नया वाहन खरीदने से बच रहे हैं। फाइल

आइएलएंडएफएस घोटाले के बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) पर बढ़ी सख्ती का भी वाहनों की बिक्री पर असर पड़ा है। वित्तीय क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि पहले ये कंपनियां धड़ल्ले से वाहन खरीद के लिए कर्ज प्रदान करती थीं। परंतु अब काफी मीन-मेख के बाद मुश्किल से कर्ज दिया जाता है। नियम सख्त होने से बैंक भी ऑटो लोन देने में अब पहले जैसा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। पिछले एक साल से कमोबेश यहीं स्थिति है। ग्राहक फिलहाल नया वाहन खरीदने से बच रहे हैं। तेल और रुपये की कीमतों ने भी ऑटोमोबाइल बिक्री को प्रभावित किया है। जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रुपया कमजोर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को इन दिनो संक्रमण के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन पर एक साथ कई चीजों को बदलने का दबाव है।

एक तरफ उन्हें अप्रैल, 2020 से बीएस-6 वाहनों के उत्पादन की तैयारियां करनी पड़ रही हैं और गाड़ियों के सुरक्षा मानकों को मजबूत करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के सरकार के रोडमैप के हिसाब से भी चलना पड़ रहा है। इसके कारण लागत बढ़ने से वाहनों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। परिणामस्वरूप बिक्री में और गिरावट हो रही है। हालत ये है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास तकरीबन 30 हजार करोड़ रुपये के वाहनों का अनबिका स्टॉक जमा हो गया है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के एसपी सिंह के अनुसार वाहन बीमा दरों में लगातार भारी बढ़ोतरी से भी वाहनों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वाहन बीमा दरों का निर्धारण बाजार पर नहीं छोड़े जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

छह माह में मात्र 1 टाटा नैनो बिकी

नई दिल्ली : पिछले छह माह के दौरान टाटा मोटर्स की केवल एक नैनो कार की बिक्री ने ऑटोमोबाइल उद्योग की खराब हालत को लेकर और चिंता पैदा कर दी है। टाटा मोटर्स ने इस वर्ष जनवरी से एक भी नैनो कार का उत्पादन नहीं किया है। जबकि फरवरी से एक भी नैनो कार की बिक्री नहीं की है। हालांकि कंपनी का कहना है कि बिक्री गिरने के कारण नैनो का उत्पादन बंद करने के बारे में उसने अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम मांग के मुताबिक बिक्री कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में कंपनी ने सानंद संयंत्र में 82 नैनो कारों का उत्पादन किया था। इसके बाद जनवरी से लेकर जून तक एक भी नैनो नहीं बनाई गई है। इस अवधि में एक भी नैनो का निर्यात भी नहीं हुआ। इससे पहले टाटा मोटर्स ने संकेत दिए थे कि अप्रैल, 2020 से नैनो का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा और भविष्य में इस कार पर और निवेश की कंपनी की कोई योजना नहीं है।

दुनिया में कहीं भी भुगतान के लिए हाजिर है फेसबुक की लिब्रा

दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल साइट फेसबुक लोगों को जोड़ने के साथ आपका लेनदेन भी आसान बनाने जा रही है। कहीं भी अपना भुगतान बिना करेंसी चेंज के कर सकते हैं। फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा को लेकर दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों को इसकी राह में रोड़े भी कम नहीं दिख रहे। इसके पहले डिजिटल करेंसी बिटकॉइन तेजी से लोकप्रिय हुई थी लेकिन किसी देश के केंद्रीय बैंक से मान्यता न होने और भुगतान नेटवर्क न होने से यह विफल हो गई। माना जा रहा है कि लिब्रा अपनी खूबियों के चलते दुनिया भर में वित्तीय प्रणाली से दूर और अछूते लोगों का प्रभावी समावेशन करा पाएगी। हालांकि अभी इसकी स्थिरता और वैधानिकता पर सवाल बना हुआ है। अभी विश्व बैंक की ओर से इसके भुगतान शुल्क का मुद्दा भी है। लेकिन फेसबुक का कहना है कि इसकी यह लागत लगभग शून्य होगी।

क्या होगा फायदा

अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है या किसी दूसरे देश से किसी के पास पैसा आता है तो उसे उस देश की करेंसी में परिवर्तन कराना होता है। इसके चलते यदि आप दूसरे देश में जाते हैं तो आपको करेंसी बदलने की जरूरत नहीं होगी।

कैसे बनाएगा बाजार

इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यह एम पैसा, भीम, मास्टर और वीसा कार्ड की तर्ज पर व्यक्ति से व्यक्ति पेमेंट करेगा। मोबाइल पेमेंट की तरह भी काम करेगा। इससे लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी।

क्या है लिब्रा

फेसबुक की डिजिटल करेंसी (क्रिप्टो करेंसी) है। यह सार्वभौमिक, स्थायी और आसानी से लोगों और कारोबार के बीच स्थानांतरित की जा सकने वाली मुद्रा है। इसके लिए स्थायी पेमेंट नेटवर्क की गठन की जरूरत नहीं होगी। फेसबुक के साथ इस दिशा में कई कंपनियां जुड़ चुकी हैं।

कहां लटका है मुद्दा

इस करेंसी का सबसे बड़ा मसला भुगतान शुल्क है, जिसे विश्व बैंक को तय करना है। परदेस से आने वाली रकम की विनियम का औसत शुल्क वर्तमान में सात फीसद है। कुछ देशों में रकम भेजने के लिए लोगों को 10 फीसद तक शुल्क चुकाना पड़ रहा है। हालांकि फेसबुक का दावा है कि इससे लेनदेन का शुल्क न बराबर होगा।

क्या है क्रिप्टो करेंसी

क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। यह एक कंप्यूटर मोड से दूसरे कंप्यूटर मोड को दी जा सकती है। इसे आभासी मुद्रा कह सकते हैं। साक्षात नहीं देखा जा सकता है।

वैधानिकता का सवाल

वैसे तो इस करेंसी के इस्तेमाल से देश विदेश में कहीं भुगतान में आसानी होगी लेकिन इसकी स्थिरता और वैधानिकता को लेकर व्यापारियों में अभी आशंका है। क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी देश के केंद्रीय बैंक ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि फेसबुक को अपने बड़े प्लेटफॉर्म और ब्रांड का भरोसा है।

भारत और अफ्रीकी देश निगाह में

फेसबुक अपनी इस करेंसी के लिए भारत और अफ्रीकी देशों जैसे विकासशील देशों पर निगाहें जमा रखी हैं। गरीब लोगों की बड़ी आबादी है जो परंपरागत बैंक खाते का महंगा रखरखाव वहन नहीं कर सकती है। ये लोग तेजी से मोबाइल ऑनलाइन और एप से बैंकिंग कर रहे हैं। हालांकि भारत सहित कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है।

न्यूज गैलरी

रूस में पनडुब्बी में लगी आग 14 नाविकों की मौत

मॉस्को : रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गहरे पानी के भीतर एक पनडुब्बी में आग लगने से 14 नाविकों की मौत हो गई। यह पनडुब्बी उत्तरी शहर सेवरोमोर्स्क में एक सैन्य बेस में तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक जुलाई को गहरे पानी में पनडुब्बी पर बायोमीट्रिक आकलन के दौरान आग लग गई। पनडुब्बी में जहरीला धुआं फैलने से 14 नाविकों की मौत हो गई। उसने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। (एएफपी)

सऊदी एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय समेत नौ घायल

रियाद : यमन के हाउती विद्रोहियों ने मंगलवार को सऊदी अरब के आभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिर हमला किया। इस हमले में एक भारतीय और आठ सऊदी नागरिक घायल हो गए। विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने आभा हवाई अड्डे पर सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने इससे पहले 23 जून को भी इस सऊदी एयरपोर्ट पर हमला किया था। (एएनआइ)

दुनियाभर में अब तक का सबसे गर्म महीना रहा जून

पेरिस : दुनिया भर में इस साल के जून को अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। यूरोपीय यूनियन (ईयू) की सेटेलाइट एजेंसी के मुताबिक, पिछले महीने पश्चिमी यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। ईयू की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा (सी3एस) द्वारा ली गई वैश्विक रीडिंग के अनुसार, यूरोप का तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया और वैश्विक रूप से पृथ्वी का तापमान जून के पिछले रिकॉर्ड से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सहारा से लेकर यूरोप तक में चिलचिलाते मौसम के बीच गत सप्ताह लू ने सबसे गर्म दिन के राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिए। (प्रेटू)

ट्रंप बोले, आग से खेल रहा ईरान

किया आगाह ▶ परमाणु समझौते का उल्लंघन कर यूरेनियम के ज्यादा भंडारण पर चेताया

दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा ईरान : पोंपियो

वाशिंगटन, प्रेटू : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु करार का उल्लंघन कर तय सीमा से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडारण करने पर ईरान को आगाह करते हुए कहा कि वह आग से खेल रहा है। ईरान ने सोमवार को पहली बार यह माना था कि उसने तय सीमा से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडारण किया है। ईरान ने 2015 में दुनिया के छह शक्तिशाली देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ करार किया था। लेकिन गत वर्ष मई में इस करार से अमेरिका हट गया था और ईरान पर सख्त प्रतिबंध थोप दिए थे।

ट्रंप ने ह्वाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'ईरान के लिए कोई संदेश नहीं। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे आग के साथ खेल रहे हैं। इसलिए उनके लिए कोई संदेश नहीं है।' जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने अपने कड़े बयान में ईरान से यूरेनियम संवर्धन बंद करने को कहा। उन्होंने कहा, 'परमाणु हथियारों से लैस ईरानी शासन क्षेत्र और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए अमेरिका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरे का समाधान करने के लिए ईरानी शासन के साथ नया और व्यापक समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध है।' इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जरीफ ने कहा था कि उनके देश ने संवर्धित यूरेनियम के भंडारण की सीमा का उल्लंघन करते हुए 300 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड (यूएफ6) का भंडारण किया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ईरान ने तय सीमा से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडारण किया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भी ईरान से यूरेनियम संवर्धन बंद करने को कहा है। फाइल

इस कारण है दोनों देशों में तनाव : दोनों देशों में तनाव उस समय से शुरू हुआ, जब पिछले साल मई में ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने का एलान किया था। इसके साथ ही उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आतंकी संगठनों का समर्थन करने को लेकर यह कदम उठाया था। अमेरिका ने ईरान से खतरे के मद्देनजर पश्चिमी एशिया में पिछले माह विमानवाहक पोत और बमवर्षक विमान तैनात कर दिए थे।

संवर्धित यूरेनियम का भंडारण कम करे ईरान : फ्रांस

पेरिस, एएफपी : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान द्वारा तय सीमा से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडारण किए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने मंगलवार को ईरान से अपील की कि वह संवर्धित यूरेनियम के भंडारण को कम कर दे।

ईरान के फैसले पर चीन ने जताया खेद

बीजिंग, एएफपी : चीन ने मंगलवार को कहा कि वह तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित करने के ईरान के फैसले पर खेद जताता है। साथ ही चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा बनाया गया अधिकतम दबाव तनाव का मूल कारण है।

अब भारत को भी मिलेगा नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा

▶ अमेरिकी सीनेट ने कानूनी प्रावधान पारित किया, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम

वाशिंगटन, प्रेटू/आइएएनएस : अमेरिकी सीनेट ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया है, जिससे भारत का दर्जा अमेरिका के नाटो सहयोगियों और इजरायल एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान हो जाएगा। वित्त वर्ष 2020 के लिए पिछले सप्ताह पारित राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में इस तरह का प्रस्ताव निहित था।

सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष सांसद मार्क वार्नर एवं जॉन कॉर्निन द्वारा पेश किए गए संशोधन में मानवीय मदद, आतंकवाद, जल-दस्युओं से निपटने और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में हिंद महासागर में भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। पिछले सप्ताह ह्वाउस इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष ब्रैड शर्मन ने कांग्रेस सांसद जोए विलसन, अमी बेरा, टेड योहो, जॉर्ज होल्डिंग, एड केस और राजा कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा ही कानूनी प्रस्ताव 'ह्वाउस एफवाई 2020 एनडीएए' पेश किया था, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा।

अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों (प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट) द्वारा पारित किए जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। सदन द्वारा एनडीएए के इस संस्करण को जुलाई में किसी समय पेश करने की संभावना है क्योंकि अगस्त में एक महीने के अवकाश के लिए 29 जुलाई को सदन स्थगित कर दिया जाएगा। दोनों देशों की सामरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक बयान में कॉर्निन और वार्नर की प्रशंसा की है।

मार्क वार्नर। फाइल

तकनीक के क्षेत्र में भी शीर्ष पर पहुंचेगा भारत

वर्तमान में भारत, अमेरिका का गैर नाटो सहयोगी है। यह दर्जा मिलने के बाद जापान और आस्ट्रेलिया जैसे अन्य नाटो सहयोगियों की तरह भारत भी शीर्ष टेक्नोलाजी तक पहुंच सकेगा। भारत पहले से ही अमेरिका का बड़ा रक्षा साझीदार है और उसे अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच हासिल है। इससे कोई बड़ा अंतर नहीं आएगा, लेकिन सीनेट एक शक्तिशाली निकाय है इसलिए भारत-अमेरिका साझीदारी के पक्ष में विश्वास मत एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व विदेश सचिव ललित मानसिंह ने कहा कि इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए।

दाऊद के करीबी मोती का अमेरिका प्रत्यर्पण विफल करने में जुटा पाकिस्तान

▶ लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाबिर मोतीवाला के बचाव में डी कंपनी समर्थित वकील ने दी दलीलें

▶ कहा-मोतीवाला गंभीर अवसाद से ग्रस्त और तीन बार आत्महत्या की नाकाम कोशिशें कर चुका है

लंदन, आइएएनएस/प्रेटू : दाऊद इब्राहिम के एक करीबी साथी जाबिर मोतीवाला के अमेरिका प्रत्यर्पण को रोकने के लिए लंदन स्थित पाकिस्तानी राजनयिक हर कोशिश में जुटे हुए हैं। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) की प्रत्यर्पण याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी राजनयिकों की तरफ से समर्थित डी-कंपनी के बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मोतीवाला गंभीर अवसाद से ग्रस्त है और तीन बार आत्महत्या की नाकाम कोशिशें कर चुका है। इसलिए उसे मनीलांड्रिंग, ड्रग तस्करी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराध के आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है।

मोतीवाला दाऊद इब्राहिम का बेहद भरोसेमंद आदमी है, जिसे अगस्त 2018 में लंदन में मनी लांड्रिंग और ड्रग तस्करी के आरोपों में एफबीआइ की सूचना पर गिरफ्तार किया गया था। भारतीय एजेंसियों के करीबी सूत्रों ने बताया कि लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने शुरू में आरोपित के वकील की तरफ से अदालत में एक पत्र सौंप कर यह कहते हुए प्रत्यर्पण को विफल करने की कोशिश की थी कि मोतीवाला पाकिस्तान में एक प्रसिद्ध और सम्मानित कारोबारी है।

असल में पाकिस्तान को डर है कि यदि मोतीवाला को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया, तो डी-कंपनी का यह करीबी साथी दाऊद इब्राहिम के कराची से संचालित अंडरवर्ल्ड नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसिस इंटेलिजेंस (आइएसआइ) के बीच के गठजोड़ को उजागर कर देगा। जबकि अमेरिका दाऊद इब्राहिम को पहले ही एक वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है, जो एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट चलाता है और गिरोह के मार्गों को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के साथ साझा करता है।

सूत्रों ने बताया है कि दाऊद का प्रमुख वित्त सहयोगी मोतीवाला लंदन में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। उसे स्कॉटलैंड यार्ड की प्रत्यर्पण इकाई ने मनी लांड्रिंग और डी-कंपनी के हवाले से अर्जित नारकोटिक्स धन को साझा करने के आरोपों में गिरफ्तार किया था।

सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी सरकार की तरफ से पेश हुए बैरिस्टर जॉन हार्डी ने अदालत से कहा कि मोतीवाला खूब यात्रा करता है और अपने बॉस दाऊद इब्राहिम के लिए (अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधों के लिए) बैठकें करता है। दाऊद अपने भाई अनीस सहित भारत में आतंकी अपराधों के लिए वांछित है। सूत्रों ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि मोतीवाला गंभीर अवसाद से ग्रस्त है और पिछले कई वर्षों में आत्महत्या के कई प्रयास कर चुका है। वकील ने कहा कि ऐसी स्थिति में उसे मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता।

सूत्रों ने कहा कि इसके ठीक विपरीत अमेरिकी पक्ष के वकील ने कहा कि मोतीवाला डी-कंपनी के काले धन को विदेश में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करता रहा है। वह कथित तौर पर ड्रग तस्करी में संलिप्त रहा है और डी-कंपनी की तरफ से धन उगाही के लिए यूरोप की यात्रा भी करता रहा है। यदि मोतीवाला को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया, तो यह दाऊद के साथ ही पाकिस्तानी शासन व्यवस्था में मौजूद उसके संरक्षकों को एक बड़ा झटका होगा।

हांगकांग मामले में दखल पर अमेरिका ब्रिटेन और यूरोपीय संघ पर भड़का चीन

बीजिंग, प्रेटू : हांगकांग मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के दखल से चीन भड़क गया है। उसने हांगकांग की विधायी परिषद में घुसने वाले प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह का भ्रामक संकेत देने को लेकर ईयू और इन देशों को आगाह किया है। चीन ने कहा कि वह देश के आतंरिक मामलों में इनके हस्तक्षेप का सख्ती से विरोध करता है।

हांगकांग की विधायी परिषद में सोमवार को प्रदर्शनकारी घुस गए थे और घंटों कब्जा जमाए रखा था। इस दौरान उन्होंने फर्नीचर आदि को नुकसान पहुंचाया और दीवारों पर नारे लिख दिए। आरोपितों को चीन प्रत्यर्पित करने वाले प्रस्तावित कानून के खिलाफ पिछले तीन हफ्ते से हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। ब्रिटेन ने एक जुलाई, 1997 को हांगकांग इस शर्त के साथ चीन को सौंपा था कि वह इसकी स्वायत्तता को बरकरार रखेगा। सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, चीन के हांगकांग और मकाऊ मामलों के दफ्तर के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारियों के विधायी परिषद की इमारत में घुसने की कड़ी निंदा की जाती है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अति कट्टरपंथी करार दिया। प्रवक्ता ने कहा कि हांगकांग की सरकार और पुलिस जिस तरह इन घटनाओं से निपट रही है, चीन उसका समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी हांगकांग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के समर्थन को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, 'मैं यह दोहराना चाहूंगा कि हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है और इसका मामला पूरी तरह आंतरिक है। हम चीन के मामले में इन देशों के दखल का विरोध करते हैं।' अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू ने कहा है कि हांगकांग के लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने हालांकि हिंसा से बचने का आग्रह भी किया है।

हांगकांग में सोमवार को उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैसे के गोले छोड़े थे। एएफपी

हांगकांग की आजादी से कोई समझौता नहीं

लंदन, रायटर : ब्रिटेन ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह हांगकांग की आजादी को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ही उसने चीन को आगाह किया है कि दमन से हांगकांग संकट का समाधान नहीं हो सकता। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरमी हंट ने कहा, 'हम अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे।'

नाइजीरिया में टैंकर में विस्फोट से 45 मरे, 100 से ज्यादा झुलसे

अहुंवे, एएफपी : मध्य नाइजीरिया में सड़क हादसे के बाद पेट्रोल टैंकर में विस्फोट होने से कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। मारे गए लोग दुर्घटना के बाद टैंकर से पेट्रोल निकालने के लिए वहां जमा हुए थे। नाइजीरिया की आपात सेवा ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

टैंकर सोमवार को बेनुए प्रांत में अहुंबे गांव से होकर जा रहा था। टैंकर जहां पलटा, वहां पास में कुछ दुकानें थीं। उससे रिस रहे पेट्रोल को लेने के लिए स्थानीय लोग वहां पहुंच गए। करीब एक घंटे तक टैंकर से रिसते तेल को लोग इकट्ठा करते रहे। इस बीच टैंकर में विस्फोट हो गया। बेनुए प्रांत के संघीय सड़क सुरक्षा आयोग के सेक्टर कमांडर आलियू बाबा ने कहा, 'हमने घटनास्थल से 45 लोगों के शव निकाले हैं, जबकि घटना में 101 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। आग बुझाते हुए दो दमकलकर्मी भी झुलसे हैं।'

उन्होंने कहा कि आग तब लगी जब यात्रियों से भरी एक बस मौके से गुजर रही थी और उसके नीचे लगा एक पाइप जमीन से टकरा गया। इससे चिंगारी निकली और आग भड़क गई। इससे पहले स्थानीय परिषद के एक प्रवक्ता ने घटना में 64 लोगों की मौत की बात कही।

पेरिस में अमेजन मुख्यालय पर प्रदर्शन

फ्रांस में मंगलवार को पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने दिग्गज ऑनलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी कंपनी अमेजन पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और नौकरियों को नष्ट करने का आरोप लगाया। राजधानी पेरिस में कार्यकर्ताओं ने अमेजन मुख्यालय पर धरना देते हुए कहा कि कंपनी लोकल बिजनेस में रोजगार को खत्म कर रही है और भारी मात्रा में सामानों की ढुलाई से हानिकारक तत्वों के उत्सर्जन से पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है। प्रदर्शनकारी फ्रांस में अमेजन के तीन नए गोदामों का भी विरोध कर रहे हैं और इसकी वेबसाइट को भी बाधित कर रहे हैं। फिलहाल अमेजन ने प्रदर्शन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एएफपी

स्वतंत्रता दिवस

अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को टैंक और लड़ाकू विमान प्रदर्शित करने का पेंटागन को दिया आदेश

अमेरिका डे पर अपने देश की सैन्य ताकत दिखाएंगे डोनाल्ड

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका डे (चार जुलाई) के मौके पर दुनिया को अपने देश की सैन्य ताकत दिखाना चाहते हैं। अमेरिका इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन से कहा है कि गुरुवार को राजधानी वाशिंगटन में सलामी परेड में सेना के टैंक प्रदर्शित किए जाएं। देश की हवाई ताकत दिखाने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने आतिशबाजी करने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे भी इस खास मौके पर उनके साथ मौजूद रहें।

राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सोमवार को ट्रंप ने कहा, 'यह अमेरिका डे बेहद खास होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कुछ नए अविश्वसनीय सैन्य उपकरण हैं और हमें उन पर नाज है।' परेड में नवीनतम अब्राम और शर्मन टैंक प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है। एम1 अब्राम टैंक का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ था। अमेरिकी सेना इसका अब भी उपयोग कर रही है। एम4 शर्मन टैंक का उपयोग द्वितीय विश्वयुद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान किया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एपी

लिंकन मेमोरियल से भाषण भी देंगे : ट्रंप गुरुवार शाम लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण भी देंगे। वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा।

दो दिन में कैसे होगी तैयारी : पेंटागन के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन यह बात जरूर कही कि राष्ट्रपति के टैंक प्रदर्शित करने के आग्रह को इतने कम समय में कैसे पूरा किया जाएगा? समारोह के लिए महज दो दिन बचे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 60 टन से ज्यादा वजन वाले टैंक किस तरह कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाए जाएंगे? टैंकों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भी जरूरत पड़ेगी। कई सैनिक अभी छुट्टियों पर अपने घर चले गए हैं।

2017 में जताई थी सैन्य परेड की इच्छा : ट्रंप के दिमाग में सैन्य परेड का खयाल वर्ष 2017 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्तील डे में शामिल होने के वक्त आया था। इस मौके पर फ्रांस अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करता है। तब ट्रंप ने कहा था, 'हम भी चार जुलाई को वाशिंगटन के पेंसिल्वेनिया एवन्यू में ऐसा ही कुछ करेंगे।' इसके बाद उन्होंने सैन्य परेड की वकालत की थी, लेकिन अधिकारियों के विरोध और परेड पर नौ करोड़ डॉलर (करीब 620 करोड़ रुपये) का खर्च आने के चलते उन्होंने इस खयाल को छोड़ दिया था।

खाड़ी युद्ध के बाद हुई थी परेड : अमेरिका में सैन्य परेड खाड़ी युद्ध समाप्त होने के बाद हुई थी। इसका आयोजन जून, 1991 में राजधानी वाशिंगटन डीसी में किया गया था।

माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की कोर्ट ने दी अनुमति

▶ कहा -जज एम्मा के फैसले के कुछ पहलुओं पर जिरह की जा सकती है

▶ माल्या ने कहा-मेरे खिलाफ आरोप मनगढ़ंत, कर्ज चुकाने की फिर पेशकश

लंदन, प्रेटू/एएनआइ : ब्रिटेन के हाईकोर्ट से भारत प्रत्यर्पण के मामले में भगोड़े भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ी राहत मिल गई है। ब्रिटिश अदालत ने उसे भारत प्रत्यर्पण के ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जाविद के आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद माल्या ने रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत यह प्रमाणित हो गया है। साथ ही उसने भारतीय बैंकों का बकाया कर्ज भी चुकाने की फिर से पेशकश की।

लंदन स्थित रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को जिरह सुनने के बाद अपील करने की अनुमति का आदेश दिया। जस्टिस जार्ज लेगट और एंड्रयू पोपिलवेल ने कहा कि वेस्टमिनिंस्टर मेजिस्ट्रेट्स कोर्ट की चीफ मेजिस्ट्रेट जज एम्मा अर्थबथनॉट के फैसले के कुछ पहलुओं पर जिरह की जा सकती है। हाईकोर्ट के जजों ने 63 वर्षीय विजय माल्या के बचाव पक्ष की दलीलों को सुना। इस सुनवाई के दौरान ब्रिटिश गृह मंत्री और भारत सरकार की ओर से जिरह करने वाली क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। उल्लेखनीय है कि विजय माल्या पर भारतीय बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये का घपला करने और मनी लांड्रिंग के सिलसिले में अदालती कार्यवाही के लिए ब्रिटिश सरकार उसके भारत प्रत्यर्पण का आदेश दे चुकी है।

किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक माल्या के वकील क्लेयर मांटगोमरी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। वहां पहले से ही इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। राजनीतिक पक्षपात के चलते भारत में न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। भारत की जेल के हालात उसके मूलभूत मानवाधिकारों का हनन करेंगे।

ये भी जानिए

भारत की ओर से 2019 में सबसे ज्यादा बार 25 से ज्यादा का स्कोर कोहली ने 14 बार बनाया है। उनके बाद रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धौनी ने 12-12 बार, शिखर धवन, केदार जाधव और राहुल ने छह-छह बार बनाया है।

रोहित का जवाब नहीं

- भारत ने बांग्लादेश को 28 रनों से हराया
- रोहित ने जड़ा इस विश्व कप में चौथा शतक
- बुमराह के चार और हार्दिक के नाम तीन विकेट

अभिषेक त्रिपाठी ● बर्मिंघम

एजबेस्टन स्टेडियम की उसी पिच पर इंग्लैंड से हारने के बाद भारतीय टीम नई सीख के साथ उतरी थी और उसका फायदा उठाते हुए उसने कमतर प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश के खिलाफ पहले खेलते हुए 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 314 रन बनाए। भारत एक समय 350 के पार जाता दिख रहा था, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में 63 और आखिरी के पांच ओवरों में 35 रन बनने की वजह से भारत को 314 के दायरे में सीमित होना पड़ा। जवाब में बांग्लादेश की टीम 48 ओवरमें 286 रनों पर ही पवेलियन लौट गई और 28 रनों से यह मुकाबला हार गई। भारतीय टीम इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी टीम बन गई है। वहीं बांग्लादेश की टीम विश्व कप से बाहर होने वाली पांचवीं टीम बन गई। बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने 66 रन, मुहम्मद सैफुद्दीन ने नाबाद 51 रनों की पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा चार और हार्दिक पांड्या ने तीन विकेट चटकाए।

इससे पहले, इस विश्व कप में चौथा, ओवरऑल विश्व कप में पांचवां और करियर का 26वां वनडे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा (104) जब आउट हुए तो भारत ने छह से ज्यादा के रन रेट से 29.2 ओवर में 180 रन बना लिए थे। उसके पास नौ विकेट हाथ में थे और ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से 350 का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन केएल राहुल (77), रिषभ पंत (48) और महेंद्र सिंह धौनी (35) की पारियों के बावजूद ऐसा नहीं हो सका। भारत ने आखिरी ओवर में तीन और आखिरी तीन ओवर में कुल चार विकेट गंवाए।

छोटी बाउंड्री पर बड़ा निशाना : जिस तरह जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय ने एजबेस्टन स्टेडियम में रविवार को भारत के खिलाफ एक तरफ की छोटी बाउंड्री को निशाना बनाते हुए पहले विकेट के लिए 160 रनों की साझेदारी की थी वैसे ही रोहित शर्मा और अभी तक फेल चल रहे केएल राहुल ने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ किया। चूंकि यह मैच भी उसी पिच पर था इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों ने वही रणनीति अपनाई और इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी (180) की। भारत ने विश्व कप के किसी भी संस्करण में पहले विकेट के लिए अपनी सबसे बड़ी साझेदारी की। इससे पूर्व विश्व कप में पहले विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी साझेदारी (174) का रिकॉर्ड रोहित शर्मा और शिखर धवन के नाम था, जो उन्होंने 2015 के विश्व कप में हैमिल्टन में आयरलैंड के खिलाफ बनाया था। इसका विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के उपुल थरंगा (133) और तिलकरत्ने दिलशान (144) के नाम है। इस जोड़ी ने 2011 विश्व कप में पहले विकेट के लिए जिंबाब्वे के खिलाफ 282 रन जोड़े थे।

एक बार फिर रोहित छा गए : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साउथैंप्टन में नाबाद 122, पाकिस्तान के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में 140 और एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन बनाने वाले हिटमैन बांग्लादेश के खिलाफ शुरू से 59 मीटर की बाउंड्री को अपना कार्यक्षेत्र बनाने की योजना के साथ आए थे। उन्होंने अपने पांच में से चार छक्के उसी तरफ लगाए, जबकि एक छक्का साइट स्क्रीन की तरफ सीधे गया। हालांकि, एक बार फिर इस मैच में पांचवें ओवर में उनका कैच छूटा। वह उस समय नौ रन थे और भारत का कुल स्कोर 18 हुआ था। तमीम डीप स्क्वॉयर लेग से बायीं ओर 15 मीटर दौड़ते हुए गेंद के नीचे आ गए और आसान कैच को उससे ज्यादा आसानी से छोड़ दिया। रोहित ने पहले ओवर में 59 मीटर की छोटी बाउंड्री की तरफ ही स्क्वॉयर लेग पर तो छठे ओवर में दूसरे छोर से एक्स्ट्रा कवर पर छक्का मारा। उन्होंने 24वें ओवर की पहली गेंद पर मुस्तफिजुर के सिर के ऊपर से साइटस्क्रीन के ऊपर छक्का मारा। राहुल ने भी उनका अच्छा साथ दिया। भारत का पहला विकेट 30वें ओवर में रोहित के रूप में गिरा। सौम्य सरकार ने उन्हें लिटन दास के हाथों कैच आउट कराया। इस टूर्नामेंट में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम ने 25 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गंवाया।

हिटमैन के रिकॉर्ड : रोहित ने 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लेकर अपना शतक पूरा किया। वह एक विश्व कप में चार शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज बने। इससे पहले भारत की तरफ से तीन शतक सौरव गांगुली ने 2003 विश्व कप में लगाए थे। वह विश्व कप में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में सचिन से पीछे हैं, जिन्होंने विश्व कप में सबसे ज्यादा छह शतक लगाए हैं। वह विश्व कप में 500 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। जहां तक इस विश्व कप की बात है तो वह सबसे ज्यादा 544 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और आरोन फिंच ने इस विश्व कप में 500 के आंकड़े को पार किया है। वार्नर और फिंच ने आठ-आठ मैचों में क्रमशः 516 और 504 रन बनाए हैं। रोहित की फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने क्रिकेट के महाकुंभ में कुल सात मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने चार शतक लगाए हैं।

फिर मध्य क्रम डगमगाया : रोहित के आउट होने के 15 रन बाद राहुल और 237 के कुल स्कोर पर विराट कोहली (26) भी आउट हो गए। इस विश्व कप में पांच अर्धशतक लगाने वाले कोहली को मुस्तफिजुर ने अपना पहला शिकार बनाया। पिछले मैच में आत्मविश्वास से डिगे-डिगे लग रहे रिषभ पंत ने 41 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के के साथ अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने सैफुद्दीन के पांचवें और मैच के 40वें ओवर में लगातार तीन चौके मारे, लेकिन हार्दिक पांड्या (00), दिनेश कार्तिक (08), भुवनेश्वर कुमार (02) और मुहम्मद शमी (01) के आउट होते रहने के कारण ज्यादा स्कोर नहीं बन सका। धौनी ने 33 गेंदों पर चार चौकों के साथ 35 रन बनाकर अच्छी कोशिश की। वहीं, मुस्तफिजुर ने करियर में चौथी बार और भारत के खिलाफ तीसरी बार पांच सा उससे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने 2015 में ढाका में अपने करियर के पहले और दूसरे मैच में भी भारत के खिलाफ क्रमशः पांच और छह विकेट लिए थे। वहीं, महमूदुल्लाह के फिटनेस टेस्ट में फेल होने के कारण बांग्लादेश ने इस मैच में शब्बीर रहमान को मौका दिया।

2019 विश्व कप में सबसे अधिक शतक

100	50	खिलाड़ी	देश	मैच	पारी	रन	औसत
4	1	रोहित शर्मा	भारत	7	7	544	90.66
2	4	शाकिब	बांग्लादेश	7	7	542	90.33
2	1	विलियमसन	न्यूजीलैंड	7	6	454	113.50
2	3	आरोन फिंच	ऑस्ट्रेलिया	8	8	504	63.00
2	3	जो रूट	इंग्लैंड	8	8	476	68.00
2	3	डेविड वार्नर	ऑस्ट्रेलिया	8	8	516	73.71

230 छक्के रोहित वनडे में मार चुके हैं। वह इस मामले में महेंद्र सिंह धौनी (228) से आगे निकल गए। वनडे में सबसे ज्यादा 351 छक्के शाहिद आफरीदी ने लगाए हैं

189 शतक 1975 विश्व कप से अब तक लगाए गए हैं। इस विश्व कप में अब तक 24 शतक लगाए जा चुके हैं

06 शतक इस विश्व कप में सबसे ज्यादा इंग्लैंड की टीम की तरफ से लगे हैं, जबकि भारत की तरफ से पांच शतक लगे हैं जिसमें चार रोहित के और एक शिखर धवन के नाम है

500 रन एक विश्व कप में बनाने वाले रोहित दूसरे भारतीय हैं। सचिन ने 1996 और 2003 विश्व कप में 500 रन के आंकड़े को पार किया था

विश्व कप की अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	रद	अंक	नेट रन रेट
ऑस्ट्रेलिया	8	7	1	0	14	1.000
भारत	8	6	1	1	13	0.811
न्यूजीलैंड	8	5	2	1	11	0.572
इंग्लैंड	8	5	3	0	10	1.000
पाकिस्तान	8	4	3	1	9	-0.792
श्रीलंका	8	3	3	2	8	-0.934
बांग्लादेश	8	3	4	1	7	-0.195
दक्षिण अफ्रीका	8	2	5	1	5	-0.080
वेस्टइंडीज	8	1	6	1	3	-0.335
अफगानिस्तान	8	0	8	0	0	-1.418

स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (बल्लेबाजी) — मैन ऑफ द मैच : रोहित शर्मा

भारत — **314/9** (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लोकेश राहुल का. रहीम बो. रुबेल	77	92	06	01
रोहित शर्मा का. लिटन बो. सौम्य	104	92	07	05
कोहली का. रुबेल बो. मुस्तफिजुर	26	27	03	00
रिषभ पंत का. मुसद्दक बो. शाकिब	48	41	06	01
पांड्या का. सौम्य बो. मुस्तफिजुर	00	02	00	00
धौनी का. शाकिब बो. मुस्तफिजुर	35	33	04	00
कार्तिक का. मुसद्दक बो. मुस्तफिजुर	08	09	01	00
भुवनेश्वर कुमार रन आउट	02	03	00	00
मुहम्मद शमी बो. मुस्तफिजुर	01	02	00	00
जसप्रीत बुमराह नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-6, नोबॉ-1, वा-6) 13

कुल : 50 ओवर में नौ विकेट पर 314 रन

विकेट पतन : 1-180 (रोहित, 29.2), 2-195 (राहुल, 32.4), 3-237 (कोहली, 38.2), 4-237 (हार्दिक, 38.4), 5-277 (पंत, 44.1), 6-298 (कार्तिक, 47.2), 7-311 (धौनी, 49.3), 8-314 (भुवनेश्वर, 49.5), 9-314 (शमी, 49.6)

गेंदबाजी :
मशरफे मुर्तजा 5-0-36-0
मुहम्मद सैफुद्दीन 7-0-59-0
मुस्तफिजुर रहमान 10-1-59-5
शाकिब अल हसन 10-0-41-1
मुसद्दक हुसैन 4-0-32-0
रुबेल हुसैन 8-0-48-1
सौम्य सरकार 6-0-33-1

परिणाम : भारत 28 रनों से जीता

कार्तिक को 15 साल बाद मिला पहला विश्व कप मैच

बर्मिंघम : महेंद्र सिंह धौनी, रिषभ पंत, केएल राहुल और दिनेश कार्तिक सहित भारत ने इस मैच में चार विकेटकीपर खिलाए। इसमें सबसे खास बात रही कि 2004 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे खेलने वाले दिनेश कार्तिक का 15 साल बाद किसी विश्व कप मुकाबले में उतरना। 34 वर्षीय कार्तिक ने पांच सितंबर 2004 को इंग्लैंड के ही लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला वनडे खेला था। उसमें वह एक रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, उन्हें 2007 विश्व कप टीम में चुना गया, लेकिन धौनी के विकेटकीपर के तौर पर होने के कारण उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। 2011 और 2015 विश्व कप में उन्हें टीम में ही नहीं चुना गया। भारत के लिए 26 टेस्ट, 92 वनडे और 32 टी-20 खेलने वाले कार्तिक 2019 की विश्व कप टीम में तो आए, लेकिन शुरुआती सात मुकाबलों में वह अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थे। यही नहीं, शिखर धवन के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल हुए एक और विकेटकीपर रिषभ पंत को भी इंग्लैंड के खिलाफ उतार दिया गया, लेकिन मंगलवार को कार्तिक के लिए वह क्षण आया जब वह विश्व कप खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। 45वें ओवर में विकेटकीपर रिषभ के आउट होने के बाद वह बल्लेबाजी करने आए तो उनका साथ निभाने के लिए विकेटकीपर धौनी क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि, वह नौ गेंद पर एक चौके के साथ आठ रन बनाकर आउट हुए।

बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाने के बाद जश्न मनाते भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। एपी

'चहल प्रेम' के शिकार कुलदीप यादव

अभिषेक त्रिपाठी, बर्मिंघम

- पिछले मैच में सबसे खराब प्रदर्शन करने के बावजूद चहल टीम में
- पिछले मैच में रॉय का विकेट लेने और अच्छा स्पैल करने के बावजूद यादव बाहर

भले ही इंग्लैंड में टीम इंडिया किसी के भी कारण टेस्ट सीरीज हारे, भले ही इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में युजवेंद्रा सिंह चहल बिना विकेट लिए 88 रन खर्च करके इस टूर्नामेंट में एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले भारतीय गेंदबाज बनें, भले ही वह पिछले साल आयरलैंड व इंग्लैंड के खिलाफ चार टी-20 में सबसे ज्यादा 12 विकेट ले चुके हों, लेकिन जब भी टीम में बदलाव की जरूरत होगी तो कुलदीप यादव को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और ऐसा ही मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले में भी दिखाई दिया।

जहां टीम इंडिया को चहल को बाहर का रास्ता दिखाना था, वहां कप्तान विराट कोहली ने अपनी आइपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) के गेंदबाज को बचाया और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप की जगह तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को अंतिम-11 में जगह दी। भारत ने इस मैच के लिए एक बदलाव और किया। इसमें केदार जाधव की जगह दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद भारतीय टीम दबाव में थी और उसे सही संयोजन खोजना था और इस खोज में उसने जाधव के साथ कुलदीप को बलि का बकरा बनाना उचित समझा। कलाई के स्पिनर चहल ने रविवार को बर्मिंघम के ही एजबेस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में 88 रन दिए। इंग्लिश बल्लेबाजों ने उनके ओवरों में सात चौके और छह छक्के लगाए। कोई ऐसा ओवर नहीं गया जब ऐसा लगा हो कि वह विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की स्थिति में हों। वहीं, कुलदीप ने 10 ओवर में 72 रन दिए और जेसन रॉय का विकेट गिराया। रॉय का विकेट गिरने के बाद ही इंग्लैंड का रन रेट कम हुआ और 360 की ओर बढ़ रही मेजबान टीम 337 रनों पर सीमित हो गई। हालांकि, इसके बावजूद भारतीय टीम वह मैच 31 रनों से हार गई। कुलदीप के ओवरों में पांच चौके और तीन छक्के लगे। यही नहीं, इंग्लैंड के मुकाबले में चहल और कुलदीप में कौन बेहतर था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चहल के नौवें और मैच के 40वें ओवर में बेन स्टोक्स ने रिवर्स स्लॉग स्वीप के जरिये छक्का मारा, जो आम बात नहीं है। चहल के अगले ओवर में स्टोक्स ने सबसे लंबे काऊ कॉर्नर पर छक्का और रूट ने चौका लगाया। वहीं, अपने शुरुआती चार ओवरों में 46 रन देने वाले कुलदीप ने आखिरी छह ओवर में सिर्फ 26 रन देकर इंग्लैंड के स्कोर पर लगाम लगाई और चहल से बेहतर गेंदबाजी की। बेयरस्टो और रॉय के अलावा कोई बल्लेबाज उनको मार नहीं सका। वहीं, चहल को हर बल्लेबाज ने उधेड़ा। 24 वर्षीय कुलदीप ने 50 वनडे में 4.93 की इकॉनमी और 23.59 के औसत से 92 विकेट लिए हैं, जबकि चहल ने इस मैच से पहले 47 वनडे में 5.04 के इकॉनमी और 25.62 के औसत से 82 विकेट लिए हैं। हालांकि, इस विश्व कप में चहल ने 10 विकेट लिए हैं, जबकि कुलदीप ने पांच विकेट लिए हैं। हालांकि, विराट ने इस दौरान उन्हें 10 से 40 ओवर के बीच गेंदबाजी कराई जिसमें विकेट कम मिलते हैं।

पहले भी हुआ है ऐसा : ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कुलदीप बलि का बकरा बने हैं। पिछले साल जब भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर गई थी तो कुलदीप ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 में चार, दूसरे में तीन, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 में पांच और दूसरे में कोई विकेट नहीं लिया। वहीं, चहल ने इन चार मैचों में क्रमशः तीन, तीन, शून्य और एक विकेट लिया। इसके बावजूद ब्रिस्टल में हुए तीसरे टी-20 में कुलदीप को यह कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि यहां का मैदान छोटा है इसलिए उसके आकार को देखकर उन पर ज्यादा रन बनेंगे, जबकि वह इससे पहले के चार मैचों में 12 विकेट ले चुके थे। वहीं, चहल को इस मैच में भी मौका दिया गया और उन्होंने चार ओवर में 30 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं लिया। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे में कुलदीप ने क्रमशः छह, तीन और शून्य विकेट लिए वहीं चहल ने एक, तीन और शून्य विकेट लिया।

इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत के टेस्ट स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उतारा और दूसरे टेस्ट में लॉर्ड्स की तेज गेंदबाजों की पिच पर टीम प्रबंधन ने खराब फैसला लेते हुए दो स्पिनर उतारने का फैसला किया। बारिश के कारण इस मैच का टॉस भी दूसरे दिन हुआ और भारतीय प्रबंधन को छोड़कर सबको पता था कि नमी से ओतप्रोत इस पिच पर दो स्पिनर नहीं उतारने चाहिए तब भी रवि शास्त्री और विराट ने अश्विन और कुलदीप को उतारने का फैसला किया। इस मैच में कुलदीप से सिर्फ नौ ओवर गेंदबाजी कराई गई और ट्रेंट ब्रिज में हुए तीसरे टेस्ट में बिना उतारे ही उन्हें मुरली विजय के साथ वापस भारत भेज दिया गया। विशेष तरह की गेंदबाजी करने वाले और पूरी दुनिया के बल्लेबाजों को डराने वाले कुलदीप को लेकर उस समय शेन वार्न ने भी कहा था कि यह भारत की गलती है। भारत को साउथैंप्टन और ओवल में आखिरी दो टेस्ट मैचों में उनकी कमी खलेगी और वैसा ही हुआ। अनफिट अश्विन कुछ नहीं कर पाए और आखिरी दो टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा।

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्रा सिंह चहल। एपी

भारत में टी-20 जीतने से आत्मविश्वास बढ़ा : कमिंस

मैनचेस्टर, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कहा है कि भारत में टी-20 सीरीज जीतने से टीम के अंदर यह आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वह विश्व कप जीत सकती है। कमिंस ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत में मिली सीरीज जीत, खासकर टी-20 सीरीज जीतने से मुझे यह अहसास हुआ कि हमें विश्व कप में इसका फायदा मिल सकता है। कमिंस ने इस साल 27 फरवरी को बेंगलुरु के एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए टी-20 मैच का विशेष रूप से जिक्र किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 191 रन का लक्ष्य मिला था।

ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के 55 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 113 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी के दम पर दो गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था। कमिंस ने कहा कि बेंगलुरु में मैक्सवेल ने शतक जड़ा और हमने वहां अप्रत्याशित जीत हासिल की। इससे हमें बहुत आत्मविश्वास मिला। हमें एक खास टीम की तरह महसूस हुआ। कुछ महत्वपूर्ण जीतों से हमें यह महसूस हुआ है कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप में आठ में से सात मैच जीते हैं और वह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। कमिंस ने कहा कि हर कोई अपनी भूमिका को लेकर सहज हैं। हर कोई अच्छी स्थिति में है। हम उसी तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से हम खेलना चाहते हैं।

उलटफेर करना चाहते हैं डिसिल्वा

चेस्टर ली स्ट्रीट, एएफपी : श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज धनंजय डिसिल्वा विश्व कप के अपने आखिरी मैच में भारत के खिलाफ उलटफेर करना चाहते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सोमवार को रोमांचक मैच में श्रीलंका ने 23 रनों से जीत दर्ज की। हालांकि, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में नौ विकेट की हार ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। टूर्नामेंट के अपने आखिरी मैच में श्रीलंका का सामना पड़ोसी भारत से होगा। डिसिल्वा ने बताया कि हमने अन्य आइसीसी प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हमने वेस्टइंडीज को हराया, ताकि हम इस आत्मविश्वास और लय को अगले मैच में ले जाते हुए भारत को हरा पाएं। हम हर मैच को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर हम भारत को मात दे देते हैं तो पांचवें पायदान पर रहेंगे। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पिछले आठ में से केवल एक वनडे मैच जीता है, लेकिन उन्होंने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को मात दी थी।

सम्मान पाने की कोशिश करेंगे : पूरन

चेस्टर ली स्ट्रीट, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम विश्व कप के निराशाजनक प्रदर्शन से सीख लेगी और भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में खोया हुआ सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेगी। पूरन ने सोमवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ 118 रनों की दमदार पारी खेलते हुए अपने करियर का पहला शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी थी। हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे पास एक युवा टीम और युवा बल्लेबाजी क्रम है। उम्मीद है कि मेरी तरह शिमरोन हेटमायर, शाई होप और फेबियान एलेन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि भारत के खिलाफ सीरीज में हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और वेस्टइंडीज क्रिकेट के खोए हुए सम्मान को वापस लेकर आएंगे। भारतीय टीम तीन अगस्त से वेस्टइंडीज का दौरा करेगी।

मैथ्यूज शानदार दिखे : करुणारत्ने

चेस्टर ली स्ट्रीट, प्रेट्र : श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने सोमवार को यहां विश्व कप के मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद अनुभवी ऑलराउंडर एंजलो मैथ्यूज की जमकर तारीफ की। मैथ्यूज ने बल्ले से 26 रनों का योगदान दिया और एक विकेट भी लिया। करुणारत्ने ने कहा कि पूरन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और हमें दो ओवर निकालने थे। मैथ्यूज ने अपना हाथ उठाया और कहा कि वह गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और एक कप्तान के रूप में मैं उनसे यही उम्मीद कर रहा था।

विश्व कप डायरी

तीसरी बार पिता बने वार्नर

लंदन, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने तीसरी बार पिता बनने की जानकारी दी। वार्नर ने इंस्टाग्राम पर पत्नी और तीनों बेटियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमने अपने परिवार की नई सदस्य इसला रोज वार्नर का रविवार देर रात 10:30 बजे स्वागत किया। कैंडिस यह अद्भुत था। माता-पिता बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसकी बड़ी बहनें बेहद खुश हैं। प्राउड डैड। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व कप के अगले मैच से पहले एक सप्ताह का समय होगा। ऑस्ट्रेलिया को अब छह जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम लीग मैच में खेलना है। वार्नर इस विश्व कप में शानदार फॉर्म में हैं और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। वार्नर ने मौजूदा विश्व कप के सात मैचों में अब तक 516 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है और वह सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है।

सेमीफाइनल की उम्मीद में उतरेंगे इंग्लैंड व न्यूजीलैंड

चेस्टर ली स्ट्रीट, एएफपी : इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बुधवार को यहां विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। यहां तक की हार से भी दोनों टीमों की उम्मीदें समाप्त नहीं होंगी और 10 टीमों के बीच राउंड रोबिन आधार पर खेले जा रहे टूर्नामेंट में उनके पास आगे बढ़ने का मौका बना रहेगा।

इंग्लैंड के 10 अंक हैं और न्यूजीलैंड पर जीत से वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इंग्लैंड की टीम पिछले मैच में भारत पर 31 रन से जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी है। यह जीत उसे श्रीलंका और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से लगातार दो हार के बाद मिली है। भारत के खिलाफ जीत इंग्लैंड के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि उसके वे कारक फिर से सामने आए जिससे पिछले कुछ वर्षों में वह वनडे में चरम पर पहुंचने में सफल रहा था। जॉनी बेयरस्टो (111) और चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले जेसन रॉय (66) ने पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़े जिसके बाद बेन स्टोक्स ने 79 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। यह उनका लगातार तीसरा अर्धशतक है। इससे इंग्लैंड ने सात विकेट पर 337 रन बनाए।

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन। एपी

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर। एपी

पहली बार विश्व कप जीतने की कवायद में लगे इंग्लैंड ने इसके बाद अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण किया। क्रिस वोक्स ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जबकि लियाम प्लंकेट ने फिर से बीच के ओवरों में विकेट निकाले।

दूसरी तरफ न्यूजीलैंड लगातार दो मैचों में हार के बाद इस मैच में उतरेगा। उसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और तूफानी गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन का सामना करना किसी भी टीम के लिए चुनौती होगी। न्यूजीलैंड स्पिनर ईश सोढ़ी की जगह पर एक अन्य तेज गेंदबाज मैट हेनरी को अंतिम एकादश में रख सकता है क्योंकि रिवरसाइड की पिच से स्पिनरों को बहुत अधिक मदद नहीं मिलती है। लेकिन, जहां इंग्लैंड के कई बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में हैं तो वहीं न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन और सीनियर बल्लेबाज रॉस टेलर पर बहुत अधिक निर्भर है। कोलिन मुनरो को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से बाहर किया गया था, जबकि दूसरे सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 73 रन बनाने के बाद अगली छह पारियों में केवल 85 रन ही बना पाए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लाथम भी नहीं चल पाए हैं। उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में केवल 8.2 की औसत से रन बनाए हैं।

89 वनडे मैच हुए हैं अभी तक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। इनमें से न्यूजीलैंड ने 43 और इंग्लैंड ने 40 मैच जीते, जबकि दो मैच टाई व चार मैच बेनतीजा रहे

30 वनडे मैच खेले गए हैं न्यूजीलैंड व इंग्लैंड के बीच इंग्लिश सरजमीं पर। इनमें इंग्लैंड ने 16 व न्यूजीलैंड ने 12 मैच जीते। दो मैच बेनतीजा रहे

08 वनडे मैच खेले गए हैं न्यूजीलैंड व इंग्लैंड के बीच विश्व कप में। इनमें से न्यूजीलैंड ने पांच व इंग्लैंड ने तीन मैच जीते हैं

04 वनडे मैच खेले गए हैं न्यूजीलैंड व इंग्लैंड के बीच विश्व कप में इंग्लिश सरजमीं पर। इनमें से न्यूजीलैंड ने एक व इंग्लैंड ने तीन मैच जीते हैं

भारत को सुधार की जरूरत : लॉयड

विशेष संवाददाता, बर्मिंघम : वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्लाइव लॉयड का मानना है कि भारत इस विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से है, लेकिन विराट कोहली की टीम को नॉकआउट चरण से पहले अपने बल्लेबाजी के निचले क्रम को मजबूत करना होगा। बलेबाजी में भारत सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली पर काफी निर्भर है। महेंद्र सिंह धौनी समेत मध्य क्रम के बल्लेबाज अभी तक नाकाम रहे हैं। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी पांच ओवर में 71 रन चाहिए थे, लेकिन वे 39 रन ही बना सके।

वेस्टइंडीज को 1975 और 1979 में विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान लॉयड ने आइसीसी के लिए अपने कॉलम में लिखा कि भारत के सामने चयन की दुविधा है। इंग्लैंड ने उसके स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की। भारत को अपने निचले क्रम के बल्लेबाजों को मजबूत बनाना होगा। लॉयड ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच ही चुका है और भारत पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि दोनों टीमें विश्व कप में लाजवाब रही हैं। उन्होंने हालात को बेहतर समझा।

यूरो टी-20 स्लैम से जुड़े डेल स्टेन

जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन यूरो टी-20 स्लैम से जुड़ चुके हैं। टूर्नामेंट का पहला संस्करण 30 अगस्त से शुरू होगा। यह प्रतियोगिता छह फ्रेंचाइजी के बीच खेली जाएगी और आयरलैंड, नीदरलैंड्स एवं स्कॉटलैंड इसकी संयुक्त मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट को शुरू करने की घोषणा के कुछ ही समय में छह क्रिकेटर- शाहिद अफरीदी, क्रिस लिन, शेन वॉटसन, बाबर आजम, ब्रैंडन मैकुलम, ल्यूक रोंची इससे जुड़ चुके हैं।

समस्या केवल यह है कि क्या आप नियमित रूप से क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर आप क्या टच में हैं। आपको यह देखना होगा कि मयंक अग्रवाल नियमित कितने मैच खेले हैं और क्या वे इसके टच में हैं। यही बात पंत के साथ भी है। **-मुहम्मद कैफ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर**

विंबलडन ▶ पहले दौर के अपने-अपने मुकाबलों में दोनों खिलाड़ियों को मिली शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया के किर्गियोस कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे दौर में पहुंचे

सितसिपास और ज्वेरेव टूर्नामेंट से बाहर

विंबलडन में मैच के दौरान शॉट खेलते ग्रीस के स्टीफानो तिसिपास। एपी

लंदन, एएफपी : ग्रीस के स्टीफानो सितसिपास और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव यहां जारी साल के तीसरे ग्रैंडस्लैम विंबलडन के पुरुष सिंगल्स वर्ग के पहले दौर में उलटफेर का शिकार हो गए। सितसिपास को कड़े मुकाबले में इटली के फेबियो फोग्निनी, जबकि ज्वेरेव को चेक गणराज्य के जिरी वेस्ले ने पराजित किया।

सितसिपास और फोग्निनी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में इटली के खिलाड़ी पांच सेटों में 6-4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3 से जीत दर्ज की। पहले सेट में ग्रीस के खिलाड़ी का खेल बेहतरीन नहीं रहा, लेकिन उन्होंने दूसरे सेट में वापसी की। इसी तरह तीसरे सेट में भी वह फोग्निनी के बेहतरीन खेल का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन टाईब्रेकर में गए चौथे सेट को जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। पांचवें और अंतिम सेट में इटली के खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और जीत दर्ज करते हुए दूसरे दौर में जगह बनाई। दूसरी ओर, विश्व के 124वें नंबर के खिलाड़ी वेस्ले ने एक सेट से पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी की और ज्वेरेव को 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 से हराया। यह मुकाबला दो घंटे और 31 मिनट तक चला।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को पहले दौर की बाधा पार करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। किर्गियोस को हमवतन जॉर्डन थॉम्पसन ने कड़ी चुनौती पेश की और तीन घंटे 26 मिनट तक मैच को ले गए। किर्गियोस ने यह मैच 7-6, 3-6, 7-6, 0-6, 6-1 से अपने नाम कर दूसरे दौर में जगह बनाई।

कर्बर और बार्टी भी जीतीं : गत विजेता एंजेलिक कर्बर और विश्व नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बनाई। विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी कर्बर ने महिला सिंगल्स के पहले दौर के मैच में हमवतन तातजाना मारिया को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से परास्त किया। इस मैच को जीतने में कर्बर को एक घंटे 21 मिनट का समय लगा। इस साल फ्रेंच ओपन के रूप में अपना पहला ग्रैंडस्लैम जीतने वाली बार्टी ने चीन की सईसई झेंग को एक घंटे 16 मिनट में 6-4, 6-2 से शिकस्त दी।

विंबलडन जीतना लक्ष्य : कोरी

लंदन : कोरी गॉफ का जब जन्म हुआ तब तक वीनस विलियम्स विंबलडन में दो सिंगल्स खिताब जीत चुकी थीं और अब पांच बार की चैंपियन को पहले दौर में हराने के बाद इस 15 वर्षीय किशोरी का लक्ष्य यह ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचना है। अमेरिका की किशोरी हमवतन वीनस के खिलाफ किसी तरह की परेशानी में नहीं दिखी।

विश्व में 313वें नंबर की गॉफ ने अपने से 24 वर्ष बड़ी वीनस को आसानी से 6-4, 6-4 से हराया। इसके बाद गॉफ ने टूर्नामेंट को लेकर अपनी महत्वकांक्षाओं को भी नहीं छिपाया। गॉफ ने कहा, 'मेरा लक्ष्य यहां खिताब जीतना है। मैं पहले भी यह कह चुकी हूं। मैं बड़ी खिलाड़ी बनना चाहती हूं। जब मैं आठ साल की थी तो मेरे पिता ने कहा था कि मैं ऐसा कर सकती हूं। मैं अब भी यह चाहती हूं, भले ही शत-प्रतिशत आश्वस्त नहीं हूं। लेकिन, आप नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। उन्होंने (वीनस) शानदार प्रदर्शन किया और मैच के दौरान वह बहुत अच्छी थीं। मैं जब भी उनसे मिली हूं, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया है।' टेनिस से इतर रिहाना और बियोंस को अपना रोल मॉडल मानने वाली गॉफ ने कहा कि वीनस बचपन से ही उनकी आदर्श रही हैं।

डेविस कप के लिए रैंकिंग को दांव पर लगने को तैयार हैं प्रजनेश

लंदन : भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन पाकिस्तान के खिलाफ आगामी डेविस कप मुकाबले में खेलने के लिए अपनी एटीपी रैंकिंग को दांव पर लगने के लिए तैयार हैं।प्रजनेश एटीपी रैंकिंग में शीर्ष-100 में शामिल हैं और डेविस कप के एशिया ओसियाना ग्रुप एक के मुकाबले में भारत को इस्लामाबाद में सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है।

भारतीय टीम 55 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली है और टेनिस के राष्ट्रीय महासंघ (एआइटीए) ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार पड़ोसी देश के दौरे के लिए मंजूरी दे देगी। प्रजनेश ने विंबलडन में पहले दौर के मुकाबले को गंवाने के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि मैं खेलूंगा, हालांकि अब हमारे पास इसे छोड़ने का भी विकल्प है।' भारत के लिए एटीपी सर्किट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रजनेश और रामकुमार रामनाथन इस मुकाबले में भारतीय चुनौती की अगुआई कर सकते हैं। डेविस कप के लिए प्रजनेश को दो सप्ताह का ब्रेक लेना होगा, जिससे उनकी रैंकिंग प्रभावित हो सकती है, लेकिन बायें हाथ के इस खिलाड़ी को रैंकिंग की ज्यादा चिंता नहीं।

उन्होंने कहा, 'मैं शीर्ष-100 में बना रहना चाहता हूं, लेकिन उन दो सप्ताह में मेरी रैंकिंग प्रभावित हो सकती है। देश के लिए खेलना काफी खास है और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भारतीय खिलाड़ियों में अगर मेरी रैंकिंग चार या पांच होती तो मैं इस मौके की तलाश में होता। मैं शीर्ष भारतीय खिलाड़ी हूं फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।' सोमवार को विंबलडन में पहले दौर में 15वीं वरीयता प्राप्त मिलोस राओनिक से प्रजनेश 6-7, 4-6, 2-6 से हार गए। उन्होंने कहा, 'मेरे ध्यान में थोड़ी कमी रही और इससे मैच का नतीजा प्रभावित हुआ। मेरे पास मौका था लेकिन मैं भुना नहीं पाया। मैंने दूसरे और तीसरे सेट की शुरुआत में उसे बढ़त लेना का मौका दे दिया।'

डीडीसीए का सचिव को निलंबित करना गैरकानूनी : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली : दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव विनोद तिहारा को निलंबित किए जाने के डीडीसीए के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने फैसले में कहा कि सचिव ने जिन मुद्दों को उठाया था, उन्हें जनरल बॉडी के सामने रखा जाए और सदस्य ही इस पर अंतिम निर्णय लें। पीठ ने साफ किया जनरल बॉडी द्वारा चयनित हुए सदस्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हटा सकता। विनोद तिहारा के अधिवक्ता गौतम दत्ता ने बताया कि जनरल बॉडी द्वारा चुने गए सचिव को डीडीसीए ने गैरकानूनी तरीके से अनगंल आरोप लगाकर निलंबित कर दिया था। जबकि, विनोद तिहारा का चयन 4300 सदस्यों वाली जनरल बॉडी ने किया था। तीस हजारी अदालत ने 28 अगस्त, 2018 को निलंबन के फैसले को गलत करार दिया था। इसके खिलाफ डीडीसीए ने हाई कोर्ट में अपील की थी। पीठ ने कहा कि 12 सदस्य मिलकर एक सचिव को नहीं हटा सकते, जो 4300 सदस्यों वाली जनरल बॉडी ने चुना है।

अंतिम-4 से पहले ब्राजीली कोच टिटे की उड़ी नींद

कोपा अमेरिका ▶ सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना से ब्राजील की भिड़ंत

वेलो होरिजोंते, ब्राजील, एएफपी : कोपा अमेरिका में बुधवार को विश्व की दो दिग्गज टीमों ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। हालांकि, इस मुकाबले से पहले ही ब्राजील की फुटबॉल टीम के कोच टिटे की नींद उड़ गई हैं। टिटे ने स्वीकारा है कि अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल से पहले उन्हें नींद नहीं आ रही है।

अर्जेंटीना को पहले सेमीफाइनल में मेजबान ब्राजील से मिनेराओ स्टेडियम में भिड़ना है, जहां उसे फीफा विश्व कप 2014 के अंतिम चार में जर्मनी से मिली 1-7 जैसी करारी हार का डर सता रहा है। 2016 के कोपा अमेरिका में खराब प्रदर्शन के बाद ही डुंगा को हटाकर टिटे को ब्राजील का कोच बनाया गया था और उन्होंने कहा है कि अभी वह कुछ वैसे ही बेचैन हैं जैसा वह अपने राष्ट्रीय टीम का कोच बनने के शुरुआती मैचों में थे। टिटे ने कहा कि मैं सही से नहीं सो सका। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं। मैं जैसा हूं वैसा कर रहा हूं और मैं इसका सामना कर सकता हूं। मेरी नींद सुबह तीन बजकर 15 मिनट पर खुल गई। तब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। एक कोच होने के नाते हमेशा मेरे आगे एक नोट पैड रहता है, ताकि उस पर मैं कुछ लिख सकूं। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बल्कि लियोन स्कॉलनी (अर्जेंटीना के कोच) सहित सभी कोचों के साथ है। टिटे का मानना है कि अर्जेंटीना की टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की वजह से अर्जेंटीना एक मजबूत टीम की तरह है। आप लियोन मेसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उन पर थोड़ी लगाम लगा सकते हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं। आप फिलिप कौटिन्हो, फर्मिनो, विलियिन और नेरेस जैसे खिलाड़ियों को बेअसर नहीं कर सकते हैं। ये सभी आपको कुछ ना कुछ देंगे। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में पेरू का सामना चिली से गुरुवार को होगा।

ब्राजील के कोच टिटे। एपी

चिली के साथ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं सांचेज

पोर्तो अलेग्रे, एएफपी : 1967 में एक गीत प्रचलन में आया था जिसके बोल थे ऑल यू नीड इज लव। अब चिली के कोच रेनाल्डो रूइदा के मुताबिक एलेक्सी सांचेज अपने इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड के साथ पिछले 18 महीने से इसी लव को मिस कर रहे थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सांचेज एक आकर्षक स्ट्राइकर के रूप में मशहूर हुए और उन्हें दो बार आर्सेनल का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया लेकिन युनाइटेड के साथ जुड़ने के बाद पिछले 18 महीनों में उन्होंने अपना फॉर्म और आत्मविश्वास दोनों खो दिया। हालांकि कोपा अमेरिका कप में सांचेज अपनी पुरानी लय में नजर आए हैं जहां उन्होंने कोलंबिया के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट में निर्णायक गोल करके चिली को सेमीफाइनल में पहुंचाया और अब वह पेरू के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में अपनी लय को जारी रखने उतरेंगे।

हितों के टकराव की वजह से द्रविड़ ने नहीं संभाला पद

नई दिल्ली, प्रेट्र : हितों के संभावित टकराव के कारण राहुल द्रविड़ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में क्रिकेट प्रमुख का पद अभी तक नहीं संभाला है, जबकि उन्हें एक जुलाई को पदभार ग्रहण करना था। द्रविड़ इंडिया सीमेंट के वैतनिक कर्मचारी हैं और बीसीसीआइ संविधान के अनुसार कोई एक व्यक्ति एक समय में कई पदों पर नहीं रह सकता है। इससे यह पूर्व कप्तान हितों के टकराव के दायरे में आ जाता है।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'द्रविड़ ने अभी एनसीए में पदभार नहीं संभाला। उन्हें एनसीए से जुड़ने के लिए संभवतः इंडिया सीमेंट से त्यागपत्र देना होगा।' पिछले महीने बीसीसीआइ के नैतिक अधिकारी डीके जैन ने वीवीएस लक्ष्मण के खिलाफ फैसला सुनाया था। इस पूर्व बल्लेबाज के कई पदों पर होने के कारण मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य संजीव गुप्ता ने हितों के टकराव का आरोप लगाया था।

गुप्ता ने जैन और प्रशासकों की समिति (सीओए) को 30 जून को लिखित शिकायत करके द्रविड़ के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। पूर्व भारतीय कप्तान और जूनियर टीम के कोच द्रविड़ को बेंगलुरु में एनसीए में दो साल के अनुबंध की पेशकश की गई है। इस नए पद का मतलब होगा कि वह भारत-ए और अंडर-19 टीमों के साथ विभिन्न दौरों पर नहीं जा पाएंगे जैसा कि वह पहले किया करते थे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज पारस म्हाम्ब्रे और अभय शर्मा जूनियर टीम के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा बने रहेंगे।

राहुल द्रविड़। फाइल फोटो, प्रेट्र

विविध

ताकि न बुझे किसी और के घर का चिराग...

जागरण विशेष

- 16 वर्षीय बेटे की डैम में डूबने से हुई थी मौत, माता-पिता ने लिया दूसरों को बचाने का प्रण
- रंग लाई मुहिम, घटनाओं पर लगा अंकुश
- मंदार के मम्मी-पापा दूसरों को कर रहे सावधान, सरकारों से कर रहे गंभीर प्रयास की मांग

ब्रजेंद्र वर्मा, भोपाल

घटना 21 मार्च 2015 की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी में रहने वाला 16 वर्षीय मंदार 10वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ केरवा डैम पर घूमने गया था। सुरक्षा-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से मंदार की डैम में डूबने से मौत हो गई। वहीं उसके एक दोस्त को लोगों ने बचा लिया। इस घटना ने मंदार के मम्मी-पापा प्रतिभा और विश्वास घुषे को झकझोर दिया। पेशे से अंग्रेजी ट्रेनर प्रतिभा और मैनेजमेंट कंसल्टेंट विश्वास पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बेटे को तो वे खो चुके थे, लेकिन किसी और के साथ ऐसी घटना न घटे, यह सोचकर उन्होंने प्रण लिया कि वे इसके लिए अवश्य कुछ करेंगे। बेटे की मौत के महज दो दिन बाद उन्होंने केरवा डैम पर दुर्घटना स्थल के आसपास की जगह पर सुरक्षा के इंतजाम करने का काम शुरू कर दिया।

क्यों होते हैं ऐसे हादसे : प्रतिभा-विश्वास ने डैम के खतरनाक हिस्सों को चिन्हित किया, जो दुर्घटना का कारण बने हुए थे। साथ ही, नगर निगम की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे, ऐसी खामियों को भी उन्होंने चिन्हित किया। संकेतक व चेतावनी बोर्ड पर लिखे अक्षर मिटे हुए थे। कहां कितनी गहराई है, इसकी कोई जानकारी अंकित नहीं थी। इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण डैम में बीते कुछ वर्षों में 175 बच्चों व युवाओं की डूबने से मौत हो चुकी थी। बारिश के दौरान ज्यादातर घटनाएं हुई थीं। पत्थरों पर फिसलन के कारण लोग गहरे पानी में चले जाते थे और डूब जाते थे।

लेकिन शासन-प्रशासन को शर्म नहीं आई...

भोपाल (मप्र) के निकट स्थित केरवा डैम। नवदुनिया

विश्वास घुषे बताते हैं कि बेटे के खोने का गम जिंदगीभर नहीं भूल सकते। हम नहीं चाहते कि जो दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूटा, वो किसी और पर टूटे। जब नगर निगम ने नहीं सुनी तो दो गोताखोरों को केरवा डैम पर तैनात कराया। दो साल तक दोनों का करीब 14 हजार रुपये मासिक वेतन अपनी तरफ से दिया। पुलिस चौकी पर लाइफ जैकेट, ट्यूब सहित अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित समग्री रखवाई, जिससे डूबने वालों को बचाया जा सके।

बेटे की याद में लगवाया मंदार टावर

केरवा डैम पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था। जो लोग वहां घूमने जाते, उनके मोबाइल फोन काम नहीं करते थे। सर्वे में पता चला कि कुछ घटनाओं में ऐसा हुआ कि डूबने की घटनाओं के बाद त्वरित मदद नहीं उपलब्ध हुई। ऐसे में मंदार के पिता ने मोबाइल टावर लगवाने के प्रयास शुरू कर दिए। 10 जुलाई 2016 को बीएसएनएल के सहयोग से टावर लगवाया गया। इसका नाम मंदार टावर रखा गया। इसके बाद डैम पर मोबाइल से बातचीत होने लगी।

केरवा डैम इलाके में मंदार के माता-पिता के प्रयास से लगा मोबाइल टावर। नवदुनिया

तो थम गईं दुर्घटनाएं : प्रतिभा और विश्वास ने पुख्ता सर्वे रिपोर्ट तैयार की और नगर निगम व पुलिस अधिकारियों को सौंपी। लेकिन जिम्मेदारों ने डैम पर सुरक्षा बढ़ाने के कोई इंतजाम नहीं किए। ऐसे में दंपती ने स्वयं के खर्चे पर खतरनाक जगहों को सुरक्षित बनावाया और लाइफ जैकेट, ट्यूब सहित त्वरित बचाव के अन्य सामान रखवाए। सुरक्षा की व्यवस्था करने से साल 2015 से अब तक एक भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई।

मंदार नो-मोर फाउंडेशन की स्थापना : बेटे की याद में दंपती ने 2018 में मंदार नो-मोर फाउंडेशन की स्थापना की। अब प्रदेश में जलाशयों पर होने वाली घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आसपास के जिलों के जलाशयों में डूबने की घटनाएं रोकने के लिए फाउंडेशन काम कर रहा है। भविष्य में पूरे देश में जलाशयों में डूबने की घटनाएं रोकने का काम करेगा।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

भारत में हर साल 40 हजार मौतें डूबने से होती हैं। इनमें 25 वर्ष से कम आयु के युवक-युवतियों की संख्या ज्यादा होती है। हमारी मांग है कि केंद्र व राज्य सरकारें जलाशयों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीरतापूर्वक काम करें। मां-बाप भी अपने बच्चों को लेकर सावधानी बरतें। उन्हें जलाशय आदि स्थलों पर जाने की इजाजत देने से पहले हर पहलू पर सोचें और सावधान रहें।
-विश्वास घुषे, स्व. मंदार के पिता

उत्तराखंड के जलाशयों को संवारने में जुटी हैं 'जल प्रहरी' बेटियां

पहल ▶ पौड़ी गढ़वाल में जल संरक्षण को छेड़ी गई अनूठी मुहिम

अजय खंतवाल, कोटद्वार

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जब भी जीवटता की बात होती है, ध्यान चौंदकोट क्षेत्र के उन बाशिंदों की ओर चला जाता है, जिन्होंने पांच के दशक में कुदाल व फावड़ा थामकर चंद दिनों में ही 30-30 किमी लंबी दो सड़कें बना पूरे क्षेत्र को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ दिया था। 'जनशक्ति मार्ग' के रूप में आज भी यह मार्ग क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान कर रहा है। अब इसी क्षेत्र की बेटियां 'जल प्रहरी' बनकर सूखे जलाशयों को नवजीवन देने में जुटी हुई हैं।

जल संरक्षण

क्षेत्र के गांवों की बेटियां आगे आईं तो अन्य लोग भी इस मुहिम में जुड़ते गए। अब सभी मिलकर अपने क्षेत्र में पुरखों के बनाए जलाशयों को पुनर्जीवन देने का प्रेरक प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले का चौंदकोट क्षेत्र अपनी नैसर्गिक सुंदरता और अपने निवासियों के पुरुषार्थ के बूते समूचे उत्तराखंड में अलग पहचान रखता है। जहां एक ओर वर्ष 1951 में इस क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने श्रमदान के बूते चंद दिनों में ही 30-30 किमी के मोटर मार्गों का निर्माण कर देश-दुनिया को श्रमशक्ति की अहमियत समझाई, वहीं अब क्षेत्र की मातृशक्ति युवा जोश को साथ ले क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे पेयजल संकट को खत्म करने की दिशा में कार्य कर रही है। जल प्रहरी के रूप में बालिकाएं अपने-अपने गांवों में वर्षा जल संरक्षण के लिए चाल-खाल (छोटे-बड़े जलाशय) बनाने में जुटी हुई हैं। स्थानीय संस्था भलु लगदु इन्हें इस काम में सहयोग कर रही है। आसपास के अनेक गावों की बेटियों ने मिलकर पूरे क्षेत्र में पुराने चाल-खालों और तालाबों को सहेजने का संकल्प लिया है और इस दिशा में वह तेजी से आगे भी बढ़ रही हैं।

कोटद्वार, उत्तराखंड के चौंदकोट क्षेत्र में सूखे पड़े जलाशय के पुनरुद्धार में जुटी स्थानीय बेटियां। जागरण

12वीं कक्षा में अध्ययनरत पोखड़ा ब्लॉक की दीपा को आभास है कि उनके क्षेत्र के लोग ही नहीं, वरन पूरी दुनिया आज जल संकट की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। दीपा ने कुदाल उठाई और अकेले ही चाल-खाल बनाने में जुट गई। प्रयास सफल रहा और दीपा ने स्वयं की मेहनत से दो मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा और दो मीटर गहरा ताल बना डाला। यह प्रयास क्षेत्रवासियों की प्रेरणा का सबब बना। नूतन, तनु, निर्मला सुंद्रियाल, वंदना बिष्ट... अब दीपा जैसी अनेक बेटियां जल प्रहरी बन इस काम में जुट गई हैं। इनके नेतृत्व में अब तक करीब दर्जनभर जलाशय तैयार किए जा चुके हैं।

भलु लगदु संस्था के सुधीर सुंद्रियाल बताते हैं कि गत वर्ष शुरू हुई इस मुहिम में 150 महिलाएं और अनेक ग्रामीण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कभी पेयजल के अनेक प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये जलस्रोत सूखते चले गए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां-जहां पानी के भूमिगत सोते (जलस्रोत) होने की संभावना होती है, वहां छोटे-छोटे तालाब बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है। उन्हीं छोटे तालाबों को चाल-खाल कहा जाता है। बरसात में चाल-खाल में वर्षा जल एकत्र होता है, जो जमीन में से रिसकर कमजोर या मृत हो चुके प्राकृतिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करता है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

पनबिजली परियोजनाओं में लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन

जागरण संवाददाता, मंडी

राज्य विद्युत परिषद के पनबिजली परियोजनाओं में जून में निर्धारित लक्ष्य से करीब 14.25 मिलियन यूनिट अधिक बिजली उत्पादन हुआ है। परियोजनाओं के कैचमेंट क्षेत्र में बारिश से नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ने से बिजली उत्पादन बढ़ा है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने परिषद के पनबिजली परियोजनाओं में जून में 249.06 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था, जबकि इस दौरान 263.31 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हुआ।

यह निर्धारित लक्ष्य से करीब 14.25 मिलियन यूनिट अधिक है। संजय विद्युत परियोजना भावानगर में 82.667, गानवी परियोजना में 12.852, नोगली परियोजना में 0.775, चाबा परियोजना में 0.191 और गिरी परियोजना में 5.973 मिलियन यूनिट उत्पादन दर्ज किया गया है। आंध्र परियोजना में 9.131, गुम्मा 0.797, बस्सी परियोजना में 41.654, बिनवा परियोजना में 3.654, गज में 4.426, बनेर में 4.671, खोली परियोजना में 4.352, लारजी परियोजना में 84.774 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन रिकॉर्ड किया है। रुकती में 0.303, भूरि सिंह चंबा में 0.208, थिरोट 0.455, भावा आर्गुमेंटेशन 0.605 व गानवी द्वितीय में 5.824 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हुआ है। सुंदरनगर स्थित विद्युत परिषद के उपमुख्य अभियंता (उत्पादन) पंकज सिंह का कहना है नदी-नालों में पानी की आवक अच्छी रहने से जून में तय लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन हुआ है।

बीबीएमबी की परियोजनाओं में 3910 लाख यूनिट अधिक उत्पादन : बीबीएमबी की परियोजनाओं में जून में लक्ष्य से 3910 लाख यूनिट अधिक बिजली उत्पादन हुआ है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने बीबीएमबी को 10360 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य दिया था। इस दौरान 14270 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हुआ है। डैहर पावर हाउस में 3900 लाख यूनिट का लक्ष्य था। उत्पादन 4423 लाख यूनिट हुआ है। पौंग बांध में लक्ष्य 820 लाख यूनिट का था और बिजली उत्पादन 1204 लाख यूनिट हुआ है।

बिहार में वृद्धाश्रम और अल्पवास गृहों की अब होगी ऑनलाइन निगरानी

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में सरकारी या फिर गैर सरकारी स्तर पर चलने वाले वृद्धाश्रम, महिला अल्पवास गृह, रक्षा गृह, उत्तर रक्षा गृह, बालिका, बालक गृहों को सरकार आधुनिक रूप देगी। इन गृहों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

समाज कल्याण विभाग के अनुसार सभी सरकारी-गैर सरकारी गृहों की ऑनलाइन निगरानी होगी और इसके लिए बकायदा अपना घर परिसर में एक नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। इसके पूर्व सभी गृहों को सीसीटीवी से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए 9.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक घर की अलग पहचान हो सके इसके लिए इन्हें गहरे आसमानी रंग से रंगा जाएगा। साथ ही यहां रहने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, भिक्षुओं को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें इसके लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी गृहों में कम से कम दो वाटर प्यूरीफायर, दो कंप्यूटर प्रिंटर के साथ, प्रत्येक गृह में कम से कम दो टीवी, बच्चों से संबंधित गृहों में 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए अलग से टीवी लगाया जाएगा।

मौसम विशेष

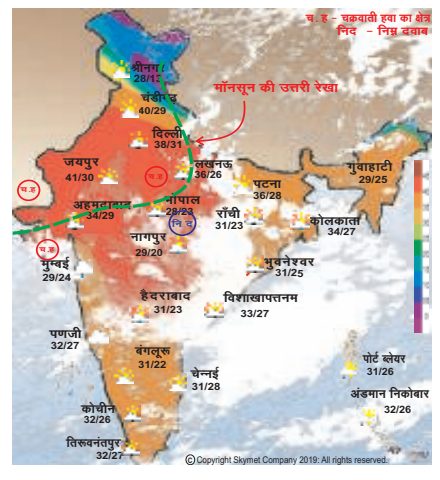

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। रात का मौसम आरामदायक व सुहावना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में उमस में वृद्धि होगी तथा मौसम काफी गर्म रहेगा। हरियाणा, दिल्ली व पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ आंधी और हल्की वर्षा संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/25/व	अहमदाबाद	37/27/व
कोलकाता	35/28/व	बड़ोदा	34/26/व
चेन्नई	37/30/आंवा	नागपुर	31/21/व
हैदराबाद	33/24/व	इन्दौर	36/24/व
बंगलूरू	31/22/व	रांची	32/27/व
त्रिवेन्द्रम	31/26/व	पटना	32/26/व
गुवाहाटी	29/25/व	जमशेदपुर	37/29/आंवा
गंगटोक	18/12/व	पुणे	24/23/आंवा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 3 जुलाई 2019
आजकल
14
www.jagran.com

दुनिया के पहले ऑटोमोबाइल का उत्पादन

1886 में आज ही जर्मन ऑटोमोबाइल इंजीनियर कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटरवैगन का प्रदर्शन किया। इसे दुनिया के पहले ऑटोमोबाइल का तमगा हासिल है। तब इसकी कीमत करीब 150 अमेरिकी डॉलर थी। तीन पहियों वाले इस वाहन के पिछले हिस्से में इंजन लगा था।

भाप से चलने वाले रेल इंजन ने बनाया रफ्तार का रिकॉर्ड

1938 में आज ही इंग्लैंड में मालार्ड नामक भाप से चलने वाले रेल इंजन ने 202 .58 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया। 24 लाख किमी की यात्रा कर चुकने के बाद इसे सेवामुक्त किया गया। आजकल यह यॉर्क के नेशनल रेलवे म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है।

लाइनोटाइप मशीन से छपने वाला पहला अखबार बना द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून

1886 में आज ही अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून लाइनोटाइप मशीन पर छपने वाला दुनिया का पहला अखबार बना। इससे पहले अखबारों का प्रकाशन टाइपसेटिंग तकनीक से होता था। इसे अमेरिका की मर्गेंथेलर लाइनोटाइप कंपनी ने बनाया था। इस तकनीक से समाचार पत्रों की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव संभव हुआ। इससे कम समय में ज्यादा पेज तैयार करना आसान हुआ। इसके 90 अक्षरों वाले कीबोर्ड से आसानी से पूरी लाइन तैयार की जा सकती थी। द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून की स्थापना 1841 में हुई थी। इसके प्रथम संपादक होरेस ग्रीली थे।

2030 तक बढ़ती गर्मी
छीन लेगी आठ करोड़ नौकरियां

संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा जारी वर्किंग ऑन वॉर्मर प्लानेट रिपोर्ट के मुताबकि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी से 2030 तक वैश्विक स्तर पर काम के घंटों में 2.2 फीसद की गिरावट होगी, जो कि आठ करोड़ नौकरियों के बराबर है। तापमान में वृद्धि से उत्पन्न स्वास्थ्य में खराबी के कारण लोग काम करने में असमर्थ होंगे। विकासशील देशों पर इसका असर ज्यादा होगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा।

भारत को होगा ज्यादा नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार, अपनी बड़ी आबादी के कारण भारत को इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। यहां काम के घंटों में 5.8 फीसद की कमी आएगी, जो कि 3.4 करोड़ नौकरियों के बारबर है।

लगेगी आर्थिक चोट

1995 में बढ़ती गर्मी के कारण वैश्विक स्तर पर 280 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन 2030 में यह आंकड़ा 2.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। इसमें निम्न मध्यम और निम्न आय वाले देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

अन्य देशों की स्थिति

बढ़ती गर्मी से चीन अपने कुल कार्य घंटों का 0.78 फीसद खो देगा, जो कि 50 लाख नौकरियों के बराबर है। जबकि अमेरिका कुल कार्य घंटों का 0.21 फीसद खो देगा, जो कि 30 लाख नौकरियों के बराबर है। कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को काम के घंटों में अधिक गिरावट आने का अनुमान है। चाड में काम के घंटों में 7.11 फीसद की गिरावट आ सकती है। वहीं सूडान में 5.9, कंबोडिया में 7.83 और थाईलैंड में 6.39 फीसद की गिरावट आ सकती है।

बन सकता बड़ा खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण 2030 और 2050 के बीच दुनिया भर में प्रतिवर्ष 38,000 अतिरिक्त मौतें होने की संभावना है।

यह क्षेत्र होंगे प्रभावित

कृषि और निर्माण क्षेत्र बढ़ती गर्मी के कारण बुरी तरह प्रभावित होंगे। दोनों काम के घंटों का 60 फीसद और 19 फीसद खो देंगे। परिवहन, पर्यटन, खेल और औद्योगिक जैसे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे।

तेजी से बढ़ेगा पलायन: काम के घंटे कम होने के कारण बेहतर काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों और अन्य देशों की ओर तेजी से पलायन करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 से 2015 की अवधि के दौरान गर्मी का स्तर बढ़ने से आउट-माइग्रेशन में तेजी से वृद्धि देखी गई थी।

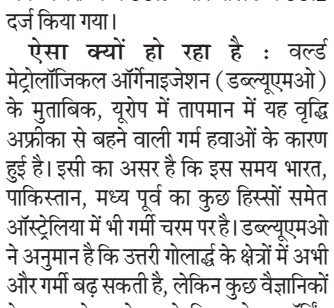

क्या है जलवायु परिवर्तन

औद्योगिक क्रांति के बाद धरती का औसत तापमान साल दर साल बढ़ रहा है। आइपीसीसी की रिपोर्ट ने इससे पहली बार आगाह किया था। अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और प्रवृत्ति बढ़ चुकी है। ऐसा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से हो रहा है।

इधर-उधर की

1300 साल से जमीन पर नहीं रखा पैर

बीजिंग, एजेंसी : आमतौर पर इंसान तो जमीन पर ही अपना घर बनाकर निवास करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जनजाति है, जिन्होंने 1300 साल से जमीन पर अपना पैर ही नहीं रखा है। इस जनजाति का नाम है टांका, जो चीन में निवास करती है। इस जनजाति के 7000 लोग समुद्र में रहना पसंद करते हैं। पानी ही इनकी दुनिया है। इन्होंने समुद्र में ही तैरता हुआ गांव बसा लिया है। इन्हें जिप्सीज ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये लोग शायद ही कभी जमीन पर पैर रखते हैं। करीब 700 ईस्वी से लेकर अब तक ये लोग समुद्र में बनाए घरों में ही रह रहे हैं। यह अपना पूरा जीवन पानी के घरों और मछलियों के शिकार में ही बीत जाता है।

शोध अनुसंधान

एंटीकोलिनर्जिक दवाओं से डिमेंशिया का खतरा

एंटीकोलिनर्जिक दवाओं को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसमें यह पाया गया है कि इन दवाओं का सालों से इस्तेमाल करने वाले लोगों में डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। यह एक मानसिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। एंटीकोलिनर्जिक दवाओं का उपयोग डिप्रेशन (अवसाद) से लेकर मिर्गी तक के उपचार में किया जाता है। ये दवाएं खासतौर पर बुजुर्गों को खाने की सलाह दी जाती है। इन दवाओं को लेकर यह कोई नया आकलन नहीं है, लेकिन जेएएमए इंटरनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययन में बड़े पैमाने पर और व्यापक विश्लेषण किया गया है। इंग्लैंड की नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैरोल कपलैंड के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में 55 साल की उम्र के करीब दो लाख 85 हजार लोगों पर गौर किया गया। इन लोगों को एंटीकोलिनर्जिक दवाओं की सलाह दी गई थी। इनमें से करीब 59 हजार लोगों में डिमेंशिया की पहचान की गई। पूर्व के अध्ययनों में भी यह बात सामने आई थी कि कुछ एंटीकोलिनर्जिक दवाओं के इस्तेमाल करने से बुजुर्गों में डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। -द न्यूयॉर्क टाइम्स

बिना हाथ-पैर चलाए केवल दिमाग से सुलझेंगी समस्याएं

खोज ▶ अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने विकसित किया नया तरीका

इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी कैप पहनकर बैठे-बैठे टेट्रिट जैसे गेम खेल सकते हैं लोग

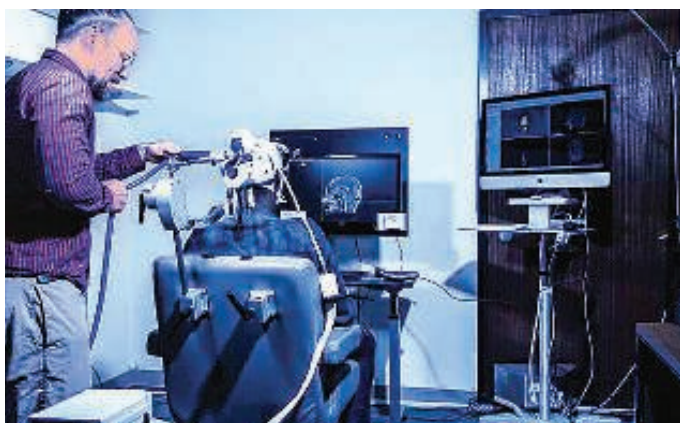

'ब्रेननेट' के जरिये भविष्य में दिव्यांगों को काम करने में मदद मिल सकती है। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : टेलीपैथिक संचार को वास्तविकता के और करीब लाते हुए अमेरिका में एक भारतीय मूल के शोधकर्ता सहित वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक ऐसा तरीका विकसित किया है, जिससे तीन लोग मिलकर अपने दिमाग के जरिये समस्याओं को हल कर सकते हैं।

साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इसके जरिये दो या दो से अधिक लोग मिलकर केवल अपने दिमाग से ही टेट्रिस-जैसे गेम आसानी से खेल सकते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करके दूसरों को जानकारी भेज पाएंगे और उनकी सूचनाओं को पाने में भी सक्षम होंगे।

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के राजेश राव ने कहा कि हम यह जानना चाहते थे कि क्या कोई समूह केवल अपने दिमाग का उपयोग करके कोई काम कर सकता है। इसके बाद हमें 'ब्रेननेट' को विकसित करने का विचार आया। इसमें दो या दो से अधिक लोगों के मस्तिष्कों को इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी कैप के जरिये कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो भी टास्क सिस्टम में प्रदर्शित होता है, उसे हल करने के लिए व्यक्ति जो भी गणना अपने मस्तिष्क में करते हैं वह कैप के जरिये विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो जाती है और टास्क को पूरा करने में मदद मिलती है।

इस अध्ययन के लेखक प्रिस्टन झींग ने कहा कि 'टेट्रिस' में स्क्रीन के शीर्ष से एक ब्लॉक नीचे की ओर आता दिखाई देता है। इसे बिना खाली जगह छोड़े नीचे तक लाकर टास्क पूरा करना होता है। दो लोग इन ब्लॉकों को नीचे की ओर आते तो देख सकते हैं, लेकिन इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इस टास्क को पूरा करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति अपने दिमाग का प्रयोग कर यह तय करता है कि आखिर सतह को छूने से पहले ब्लॉक को कैसे रखना है। उसे दाएं की घुमाना पड़ेगा या बाईं ओर, वह तुरंत निर्णय लेकर उसे उचित स्थान पर ले जाकर टास्क पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि 'ब्रेननेट' जरिये दो या दो से अधिक लोग भी आसानी से टेट्रिस का टास्क पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के निष्कर्षों का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को टेट्रिस गेम खेलने के लिए कंप्यूटर सिस्टम दिए और उन्हें इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी कैप पहनाई जो उनके दिमाग में चल रही गतिविधियों को समझकर उसे विद्युत तरंगों में बदल कर बॉक्स को उचित स्थान पर ले जा सकता है।

सॉफ्टवेयर देगा वज्रपात से पहले मोबाइल पर अलर्ट, बचेंगी जानें

दिलीप कुमार, रांची : झारखंड सर्वाधिक वज्रपात से प्रभावित राज्यों में से एक है। अब नई तकनीक यहां के लोगों की जान बचाएगी। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की आपदा विभाग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे वज्रपात के आधे घंटे पहले संबंधित क्षेत्र के मोबाइल टावर से संबद्ध सभी मोबाइलों में अलर्ट मैसेज चला जाएगा। अगर यहां यह प्रयोग सफल रहा तो इस तकनीक का इस्तेमाल दूसरे राज्य भी कर सकेंगे।

आपदा विभाग का यह साफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से मौसम विभाग से जुड़ा हुआ है। इसकी खासियत है कि सिर्फ जिले तक ही नहीं, बल्कि गांव के नाम के साथ लोकेशन तक की सूचना वज्रपात के आधे घंटे पहले आपदा विभाग को बता देगा। अब आपदा विभाग संबंधित गांव के मोबाइल टावर के माध्यम से संबद्ध सभी मोबाइलों पर यह मैसेज फ्लैश कर देगा कि सतर्क हो जाएं, वज्रपात होने वाला है। यह साफ्टवेयर इस साल के अंत तक पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। इस पर दस दिनों के बाद ट्रायल शुरू होना है।

आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ने कहा कि वज्रपात से हो रही मौतों को रोकने के उद्देश्य से एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इससे सुदूर गांव तक की जानकारी वज्रपात से पूर्व विभाग को मिल जाएगी। इसके बाद गांव के मोबाइल टावर के संपर्क के सभी मोबाइलों पर अलर्ट मैसेज चला जाएगा। यह व्यवस्था साल के अंत तक पूरी तरह शुरू हो जाएगी। बता दें कि वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका वैज्ञानिक अभी तक कोई तोड़ नहीं खोज पाए हैं। पूर्वी भारत के राज्य इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

आखिर हीटवेव से क्यों प्रभावित हैं यूरोपीय देश

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क

बीते सप्ताह फ्रांस में 45.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था तापमान

बढ़ती गर्मी भारत के साथ-साथ पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। बीते सप्ताह यूरोप में भी लगातार छह दिनों तक चली हीटवेव (गर्म हवाओं) ने वहां तापमान के पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और जंगलों में फैली आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इसके चलते फ्रांस और स्पेन में दो-दो और इटली में तीन लोगों की मौत हो गई। हालांकि, सोमवार से इस महाद्वीप के तापमान में कुछ बदलाव आया और इसके बाद अधिकारियों ने हीटवेव की चेतावनी देना बंद कर दिया।

बता दें कि जून के आखिरी सप्ताह में दक्षिणी फ्रांस के गैलार्गस-ले-मॉट्यूक्स में तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिसने गर्मी के अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। वहीं, जर्मनी में तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस, चेक गणराज्य में 38.9 और पोलैंड में 38.2 दर्ज किया गया।

ऐसा क्यों हो रहा है : वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) के मुताबिक, यूरोप में तापमान में यह वृद्धि अफ्रीका से बहने वाली गर्म हवाओं के कारण हुई है। इसी का असर है कि इस समय भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्व का कुछ हिस्सों समेत ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी चरम पर है। डब्ल्यूएमओ ने अनुमान है कि उत्तरी गोलार्द्ध के क्षेत्रों में अभी और गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने तापमान के बढ़ते स्तर के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है। डब्ल्यूएमओ ने कहा कि यूरोप और अन्य इलाकों में बढ़ती गर्मी के लिए जलवायु परिवर्तन को इतनी जल्दी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन डब्ल्यूएमओ ने यह जरूर माना कि हीटवेव जलवायु के वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप ही है। माना जा रहा है कि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के घुलने से भविष्य में वैश्विक तापमान में और वृद्धि हो सकती है। हीटवेव के अलावा कई जलवायु मॉडल यह संभावना भी जता रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा और बाढ़ भी आ सकती है।

हीटवेव क्या है : अगल-अलग देशों ने हीटवेव को अपने स्तर पर वर्गीकृत किया है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक देश के लिए जो जगह सर्वाधिक गर्म है वह दूसरे के लिए सामान्य हो। इस संबंध में वर्ष 2016 में डब्ल्यूएमओ ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि किस मौसम को हीटवेव की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत में मौसम विभाग ने उस स्थिति को हीटवेव की श्रेणी रखा है जब तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस पार हो जाए और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो।

हीटवेव के दुष्प्रभाव : डब्ल्यूएमओ ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर लोगों के स्वास्थ्य और कृषि पर पड़ता है। इसके अलावा खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग इससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि युवाओं के मुकाबले उनका शरीर बाहरी तापमान को अपने अनुकूल नहीं कर पाता। गर्मी बढ़ने से थकावट, हीट स्ट्रोक और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कई बार शरीर के अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। यूरोप में ज्यादातर लोग एयर कंडीशनर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वहां का औसत तापमान सामान्य ही रहता है। जर्मनी में तो केवल दो फीसद लोग ही एसी का प्रयोग करते हैं।

ओरियन स्पेसक्राफ्ट के लिए अबॉर्ट सिस्टम का परीक्षण

अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप केनावरल में मंगलवार को एयरफोर्स स्टेशन से ओरियन क्रू कैप्सूल के लिए अबॉर्ट सिस्टस का सफल परीक्षण किया गया। नासा के इस डेमो में कैप्सल में कोई सवार नहीं था। इस फ्लाइट टेस्ट को 'एस्सेंट अबॉर्ट-2' नाम दिया गया था। इसके तीन अंग रॉकेट, अबॉर्ट सिस्टम और कैप्स्यूल थे। इस परीक्षण का उद्देश्य अंतरिक्ष में लेकर जा रहे रॉकेट के लांच के बाद विस्फोट या अन्य मुश्किल स्थिति में ओरियन कैप्स्यूल से अंतरिक्षयात्रियों का निकासन था। ओरियन 2024 में अंतरिक्षयात्रियों को चंद्रमा पर लेकर जाएगा। यह ओरियन के लिए अबॉर्ट का दूसरा परीक्षण था। एपी

चिली लिक्विड मिले पूल में मस्ती

चीन के हुनान प्रांत स्थित निंगशियांग में मंगलवार को भीषण गर्मी से राहत तलाशने के बीच अनोखा आयोजन हुआ। इसके तहत चिली (मिर्च) लिक्विड मिले पूल में लोगों को स्नान का चैलेंज दिया गया। मिर्च के तीखेपन के चलते बहुतों को यह भले ही कठिनाई भरा लगे लेकिन यहां लोगों ने इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रायटर

स्क्रीन शॉट

अभिनय देव की फिल्म में दिखेगा सौरव गांगुली का कारनामा

इन दिनों वर्ल्डकप क्रिकेट की खुमारी छाई है, वहीं बॉलीवुड में लगातार खेलों पर फिल्में बन रही हैं। अभिनय देव ने खेल आधारित डॉक्युफिक्शनल ड्रामा 'दूसरा' का निर्देशन किया है। 'डेल्ही बेली' और '24' जैसी सीरीज का निर्देशन कर चुके अभिनय वर्ष 2002 में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर हुए नेटवेस्ट फाइनल मैच की याद ताजा कराएंगे। उस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतारकर घुमाई थी। अभिनय देव के मुताबिक, उस मैच ने उनके साथ कई युवाओं के जीवन पर प्रभाव डाला था। अभिनय बताते हैं कि उस मैच के वक्त वह 32 वर्ष के थे। इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए भारत ने जीत हासिल की, जिसके बाद खुशी और गर्व से सौरव ने अपनी टी-शर्ट उतारकर घुमाई थी। उस मैच के बाद लगा कि जब वह कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अभिनय कहते हैं कि वह उस ऊर्जा और भावनाओं को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि उस ऐतिहासिक पल की वजह से देश का गर्व बढ़ गया था। यही वजह है कि एक काल्पनिक कहानी को उस ऐतिहासिक पल के साथ जोड़कर यह फिल्म बनाई है, ताकि उन भावनाओं को आज के युवाओं तक पहुंचाया जा सके। सर्वविदित है कि वर्ष 2002 में लंदन हुए नेटवेस्ट सीरीज में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच को 2 विकेटों से जीत लिया था। युवराज सिंह और मुहम्मद कैफ की कमाल की पार्टनरशिप ने इंग्लैंड के 325 रनों का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में 326 रन बनाए थे।

'भूल भुलैया' की सीक्वल में कार्तिक आर्यन!

अक्षय कुमार की 2007 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'भूल भुलैया' का सीक्वल बनाया जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। सीक्वल में लीड भूमिका कार्तिक आर्यन निभाएंगे। कार्तिक फिलहाल दो सीक्वल फिल्मों 'लव आज कल 2' और 'दोस्ताना 2' में काम कर रहे हैं। यही नहीं, कार्तिक फिल्म 'पति पत्नी और वो' के रीमेक में भी काम कर रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार, हालांकि मेकर्स ने सीक्वल बनाने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन अभी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार, फिल्म के लिए निर्देशक भी अभी तय नहीं हुआ है और फिल्म को इस साल के अंत तक फ्लोर पर लाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में निर्देशक का फैसला हो जाएगा, उसके बाद फिल्म की लीड एक्ट्रेस और अन्य कलाकारों का नाम फाइनल होगा।

जूही की बेटी भी हुईं ग्रेजुएट

शाह रुख खान की बेटी सुहाना के बाद अब जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता भी ग्रेजुएट हो गई हैं। जूही ने अपनी बेटी के फेयरवेल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। उसमें जाह्नवी क्लासरूम में बैठी हैं। जाह्नवी (लाल घेरे में) की मुस्कान बेहद प्यारी लग रही है। जूही ने लिखा, 'जाह्नवी...अपने स्कूल फेयरवेल में...एक ही वक्त पर खुशी और गम...।'

बेटे की उपलब्धि पर माधवन को गर्व

आर माधवन ने फिल्मी दुनिया में अपना परचम लहराया है, लेकिन उनके बेटे वेदांत फिलहाल खेल की दुनिया में सिक्का जमा रहे हैं। हाल ही में वेदांत ने जूनियर नेशनल स्वीमिंग मीट में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी काबिलियत दिखाई। माधवन ने बेटे की इस जीत पर सोशल मीडिया पर बताया कि वेदांत ने इस तैराकी प्रतियोगिता में चार पदक जीते हैं, जिनमें तीन स्वर्ण और एक रजत पदक शामिल हैं। माधवन ने अपने बेटे का पदक के साथ वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'ईश्वर का अशीर्वाद तुम्हारे साथ है वेदांत, तुमने हमें एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। 3 स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। अब एशियन गेम्स है लक्ष्य।' माधवन दक्षिण और बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार होते हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म 'रॉकेटरी : द नांबी इफेक्ट' की शूटिंग पूरी की है, जिसमें वह एयरोस्पेस इंजीनियर नांबी नारायणन का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म माधवन की बतौर निर्देशक डेब्यू फिल्म भी है।

लंदन में कॉलेज के दोस्तों से मिलेंगी परिणीति

परिणीति चोपड़ा जल्द ही अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन जाने वाली हैं। यह फिल्म हॉलीवुड की हिट थ्रिलर 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की रीमेक होगी। परिणीति मूल फिल्म में एमिली ब्लंट द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार को जीवंत करेंगी। पाउला हॉकिंस द्वारा लिखी गई बेस्टसेलर किताब पर आधारित यह फिल्म एक महिला की कहानी है, जो एक लापता व्यक्ति की जांच में उलझ जाती है। लंदन में परिणीति के कई दोस्त रहते हैं। दरअसल, अभिनेत्री बनने से पहले उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस एवं इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री ली थी। वर्ष 2009 में वह करियर बनाने के लिए भारत आ गई थीं। लेकिन दोस्तों से उनका संपर्क बना रहा।

स्वस्थ शरीर

अमेरिका की अगस्ता यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 175 बच्चों पर अध्ययन कर निकाला निष्कर्ष

रोचक गतिविधियों से कम कर सकते हैं मोटापा

वाशिंगटन, प्रेट्र : हमारी जीवनशैली में आ रहे बदलाव और व्यस्तता के कारण मोटापे की समस्या अब आम हो गई है। इससे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर इससे निपटने का एक बेहतरीन तरीका सुझाया है। इसके जरिये न केवल बच्चों का मोटापा घटाया जा सकता है, बल्कि उनके मूड को भी अच्छा रखा जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्कूल के बाद यदि बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल किया जाए, जिनमें वे रुचि लेते हैं तो उनके मोटापे को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

अमेरिका की अगस्ता यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि नियमित व्यायाम बच्चों और वयस्कों के लिए बेशक लाभकारी है, लेकिन यदि बच्चों को स्कूल के बाद कला और संगीत जैसी रुचिकर गतिविधियों में भाग लेने को प्रेरित किया जाए तो यह मोटापा घटाने में बच्चों के लिए अन्य तरीकों के मुकाबले ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। यह अध्ययन ट्रांसलेशनल बिहेवियरल मेडिसिन नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कहा कि हर बच्चे का स्वभाव दूसरे से भिन्न होता है। पढ़ाई की बात करें तो कई बच्चों का रुझान इस ओर जल्दी बढ़ता है, कुछ का देर से और कई बच्चे इसे बोझ मानते हैं। ऐसे बच्चों में अवसाद और तनाव बढ़ने लगाता है और वे धीरे-धीरे एकाकी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बच्चों में मोटापा बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है।

मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रतीकात्मक

शोधकर्ताओं ने कहा कि पांच से छह घंटे की लगातार कक्षाएं करने के बाद बच्चे पूरी तरह थक जाते हैं। ऐसे में उन्हें ऐसी गतिविधियां कराई जाएं जो वे करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों की मानसिक थकान दूर होगी और वे खुद को दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्फूर्त महसूस करेंगे।

इस तरह किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने आठ से 11 साल के 175 बच्चों को शामिल किया। इनमें ज्यादातर बच्चे मोटापे का शिकार थे। शोधकर्ताओं ने बच्चों को फन ड्राइविंग, एरोबिक डांस, बोर्ड गेम व अन्य कलात्मक गतिविधियां कराईं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मूड में बदलाव के लिए ऐसा करना जरूरी : अध्ययन के लेखक सेलेस्टाइन एफ विलियम्स ने कहा कि व्यायाम निश्चित तौर पर शरीर की वसा को कम करता है और इससे शरीर सुडौल बनता है, पर मूड में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि बच्चों की इच्छा अनुसार उनसे गतिविधियां कराई जाएं। उन्होंने कहा कि अध्यन के दौरान शोधकर्ताओं ने स्कूल के बाद बच्चों को कला और शिल्प, चुनौतीपूर्ण खेलों के खेलने के साथ-साथ लोकप्रिय गानों को गाने के लिए कहा, जिसमें सभी ने बढ़चढ़कर हिस्सा भी लिया। इसके बाद उन्हें शारीरिक गतिविधियां भी कराई गईं और बच्चों की भागीदारी के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। विलियम्स ने कहा कि अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो बच्चे पहले अवसाद और तनावग्रस्त रहते थे, उनकी प्रवृत्ति में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखा गया।